R.N.I. NO.HIN/2002/8718 M.P./BHOPAL/642/2021-23

• प्रदेश में मेडिकल माफिया सक्रिय • जवान होंगे मप्र के उम्रदराज बांध!

In Pursuit of Truth

पाक्षिक

अक्स

www.akshnews.com

नेता मजबूत, संगठन कमजोर

वर्ष 19, अंक-15 1 से 15 मई 2021 पृष्ठ-48 मूल्य 25 रूपये

ये नरसंहार ही तो है...!

तंत्र की चूक से घातक होती महामारी

We Deal in Pathology & Medical Equipments

Anu Sales Corporation

Add: Ground Floor, 17/1, Shanti Niketan, Near Chetak Bridge, Bhopal-462023

M. : 9329556524, 9329556530, E-mail : ascbhopal@gmail.com

इस अंक में

यादें

9 | हंसते हुए रुलाकर चली गई रेणु

21 अप्रैल 2021 भारतीय पत्रकारिता के लिए वह काला दिन था जब जानी-मानी पत्रकार और दि प्रिंट हिंदी की संपादक रेणु आगाल ब्रह्माण्ड में लीन हो गईं। इसके साथ ही पत्रकारिता जगत ने एक ऐसे पत्रकार को खो दिया...

राजपथ

10-11 | नेता मजबूत, संगठन कमजोर

वर्ष 2018 के विधानसभा चुनाव में पड़े 3,81,38,186 वोट में से 40.89 फीसदी यानी 1,55,95,154 वोट पाकर 114 सीटें जीतने वाली मप्र कांग्रेस आज देश में सबसे कमजोर स्थिति में है। दरअसल, सत्ता से बेदखल...

अवैध खनन

15 | अवैध खनन लॉक नहीं

लॉकडाउन के दौरान प्रदेश में नर्मदा सहित अन्य नदियों में रात के अंधेरे में जमकर रेत का खनन किया जा रहा है। हाइवा-डंपरों के जरिए खाली पड़े खेतों में रेत का भंडारण किया जा रहा है। भंडारण ऐसी जगह किया जा रहा है, जहां प्रशासन की नजर न पड़े।

विवाद

18 | गोचर भूमि गायब

मप्र में सरकारी रिकार्ड से जमीनों के गायब होने की पड़ताल के दौरान ग्वालियर जिले में साल 2004 के बाद से 15 हजार हैक्टेयर चरनोई यानि की गोचर की भूमि गायब पाई गई है। आनन-फानन में कलेक्टर ने इसकी जांच बैठा दी है लेकिन मामला रसूखदार भूमाफियों से जुड़ा हुआ है...

आवरण कथा 24, 25, 26, 27, 28

किसी भी देश के शासक का पहला कर्त्तव्य होता है अपने देश की जनता को सुरक्षित रखना। लेकिन कोरोना महामारी के बीच भारत में शासन और शासक दिग्भ्रमित दिखे। इसका असर यह हुआ कि देश में कोरोना संक्रमण की दूसरी लहर आउट ऑफ कंट्रोल हो गई है। देश के श्मशानों, कब्रिस्तानों, नदी-नालों में लाशों का अंबार लगा हुआ है। मरीज ऑक्सीजन, दवा और इलाज के बिना मर रहे हैं। इलाहाबाद हाईकोर्ट ने इसे नरसंहार माना है।

राजनीति

30-31 | केसरिया गढ़ बनेगा बंगाल?

दुनिया की सबसे बड़ी राजनीतिक पार्टी भाजपा जब अपना 41वां स्थापना दिवस मना रही है, उस वक्त उसका सपना कोलकाता की राइटर्स बिल्डिंग में अपने मुख्यमंत्री को देखने का है। इसी कोलकाता में 70 साल पहले मार्च, 1951 में डॉ. श्यामाप्रसाद मुखर्जी ने जनसंघ की पश्चिम बंगाल...

महाराष्ट्र

35 | गिर सकती है सरकार

भारत की राजनीति में वर्ष 2022 काफी महत्वपूर्ण रहने वाला है। 8 राज्यों में विधानसभा चुनाव होगा जिसके नतीजों का सीधा असर केंद्र की राजनीति पर पड़ेगा। इन 8 में से 6 प्रदेशों में भाजपा की सरकार है। पंजाब इनमें से एकलौता प्रदेश है जहां भारत की प्रमुख विपक्षी दल कांग्रेस...

राजस्थान

37 | कांग्रेस नेताओं की उम्मीदें अधूरी

राजस्थान में अशोक गहलोत के नेतृत्व वाली सरकार के ढाई साल का यानी आधा कार्यकाल पूरा कर लिया है। इसके बावजूद अभी तक राजनीतिक नियुक्तियों की कांग्रेस नेताओं की उम्मीदें पूरी नहीं हो सकीं। हालांकि, पूर्व उपमुख्यमंत्री सचिन पायलट...

6-7 अंदर की बात
41 महिला जगत
42 अध्यात्म
43 कहानी
44 खेल
45 फिल्म
46 व्यंग्य

अपनी बात

आपदा को तो अवसर न बनाएं...

मानवीय तकाजा है कि आपदा के वक्त लोग एक-दूसरे का सहयोग करें, उन्हें जरूरी सुविधाएं और जीवन रक्षक सामग्री उपलब्ध कराएं, मगर कोरोना की इस दूसरी लहर में बड़े पैमाने पर ऐसी अमानवीय घटनाएं सामने आ रही हैं, जिन्हें देख-सुन कर दिल दहल जाता है। इस वक्त जब देशभर के अस्पताल ऑक्सीजन और इस संक्रमण के इलाज में काम आने वाली जरूरी दवाओं की कमी से जूझ रहे हैं, तब कई जगहों से कुछ दवा विक्रेताओं, वितरकों और सक्षम लोगों द्वारा इनकी जमाखोरी और कालाबाजारी की खबरें भी मिल रही हैं। रोगियों और शवों को ढोने वाले वाहन चालक मनमाने पैसे वसूलते देखे जा रहे हैं, तो अस्पतालों में बिस्तर दिलाने, ऑक्सीजन सिलेंडर और इस संक्रमण के लिए जरूरी मानी जा रही दवा रेमडेसिविर आदि उपलब्ध कराने के नाम पर हजारों रुपए ऐंठने वाले गिरोह भी बड़ी संख्या में सक्रिय हो गए हैं। इस समस्या को लेकर सर्वोच्च न्यायालय में जनहित याचिका भी दायर की गई। अब केंद्र सरकार ने अदालत को आश्वस्त किया है कि सभी राज्य सरकारों से ऑक्सीजन सिलेंडर, दवाओं और दूसरी आवश्यक सामग्री की जमाखोरी और कालाबाजारी करने वालों के खिलाफ सख्ती बरतने का अनुरोध किया गया है। अब तक इस मामले में 157 लोगों के खिलाफ कार्रवाई भी की गई है। विचित्र है कि जिन मामलों में लोगों को खुद नागरिक बोध और मानवीय संवेदना से संचालित होकर सहयोग के लिए आगे आना चाहिए, उनमें भी अदालतों और सरकारों को कड़ाई से पेश आना पड़ रहा है। हालांकि ऐसे वक्त में बहुत सारे लोग अपनी क्षमता के मुताबिक रोगियों की मदद के लिए तरह-तरह से सहयोग करते हुए मिसाल पेश कर रहे हैं। चाहे वह मुफ्त ऑक्सीजन पहुंचाना हो, लोगों को अस्पताल पहुंचाना हो, उन्हें भोजन, दवा आदि उपलब्ध कराना हो, हर तरह की मदद पहुंचाने की कोशिश कर रहे हैं। कई लोग अपनी जमा पूंजी इसके लिए खर्च कर रहे हैं, तो कुछ अपने जेवर तक बेचकर लोगों की मदद को तैयार दिख रहे हैं। ऐसे लोगों से भी कालाबाजारी करने वाले कोई प्रेरणा नहीं ले पा रहे, तो इसे क्या कहेंगे। दरअसल, यह प्रवृत्ति भारत में नई नहीं है। आपदा के ऐसे अनेक दिनों में अमानवीय ढंग से सिर्फ अपने लाभ की चिंता करने वालों को सक्रिय देखा जाता रहा है। उन्हें इस बात की कोई परवाह नहीं होती कि उनकी इस प्रवृत्ति से लोगों की जान पर बन आती है। कितना विचित्र है कि इस वक्त में कई ऐसे बड़े दुकानदार पकड़े गए हैं, जिन्हें न तो पैसे की कोई कमी है और न उनके कारोबार में मंदी है। फिर भी जरूरी दवाओं और ऑक्सीजन सांद्रक जैसे उपकरणों की जमाखोरी और उन्हें ऊंची कीमत पर बेचकर वे कमाई करने की अपनी भूख शांत करने में जुटे हैं। अब हालांकि दूसरे देशों से भारी मात्रा में चिकित्सीय सामग्री उपलब्ध कराई जा रही है, केंद्र और राज्य सरकारें भी अपनी पहल पर जरूरी सामग्री की किल्लत को दूर करने में कामयाब होती देखी जा रही हैं। जल्दी ही इस समस्या पर काबू पाने की उम्मीद जगी है। मगर इस आपदा में जो लोग दूसरों की जान की कीमत पर अपनी तिजोरी भरने में जुटे हैं, उन्हें मानवीय मूल्यों का पाठ पढ़ाने के बजाय कानून से ही सबक सिखाया जा सकता है। राज्य सरकारों को ऐसे लोगों के खिलाफ किसी भी प्रकार की रियायत नहीं बरतनी चाहिए। तभी दूर-दराज के इलाकों में फैल रही इस महामारी को रोकने में भी मदद मिल सकती है।

- राजेन्द्र आगाल

पाक्षिक अक्स

वर्ष 19, अंक 15, पृष्ठ-48, 1 से 15 मई, 2021

प्रकाशक एवं संपादक : राजेन्द्र आगाल

सम्पादकीय कार्यालय :
प्लाट नम्बर 150, जोन-1 मनोरमा कॉम्पलेक्स,
एफ-03, 04, प्रथम तल, एम.पी. नगर
भोपाल- 462011 (म.प्र.),
फोन नं. 0755-2557777, टेलीफेक्स - 0755-4017788
email : akshmagazine@gmail.com
Website : www.akshnews.com
RNI NO. HIN/2002/8718 MPBPL/642/2021-23

ब्यूरो
मुंबई :- ऋतेन्द्र माथुर, **कोलकाता:-** इंद्रकुमार,
जयपुर:- आर.के. बिन्नानी, **छत्तीसगढ़:-** संजय शुक्ला, मार्केण्डेय तिवारी, टी.पी. सिंह, **लखनऊ :-** मधु आलोक निगम।

प्रदेश संवाददाता
094251 25096 (इंदौर) विकास दुबे
098276 18400 (जबलपुर) धर्मेन्द्र कथूरिया
094259 85070, (उज्जैन) श्यामसिंह सिकरवार
098934 77156, (विदिशा) ज्योत्सना अनूप यादव

क्षेत्रीय कार्यालय
नई दिल्ली : ईसी 294 माया इंक्लेव मायापुरी-फोन : 9811017939
जयपुर : सी-37, शांतिपथ, श्याम नगर (राजस्थान) मोबाइल-09829 010331
रायपुर : एमआईजी 1 सेक्टर-3 शंकर नगर, फोन : 0771 2282517
भिलाई : नेहरू भवन के सामने, सुपेला, रामनगर, भिलाई, मोबाइल 094241 08015
इंदौर : 39 श्रुत्रि सिलटर निपानिया, इंदौर मोबाइल - 7000123977

स्वत्वाधिकारी, मुद्रक व प्रकाशक, राजेन्द्र आगाल द्वारा आगाल प्रिंटर्स, प्लाट नं. 150, जोन-1, प्रथम तल, एफ-03, मनोरमा काम्पलेक्स, एम.पी. नगर भोपाल 462011 (म.प्र.), से मुद्रित एवं प्रकाशित

इस अंक में प्रकाशित सामग्री लेखकों के अपने विचार हैं इनसे सम्पादक का सहमत होना अनिवार्य नहीं हैं समस्त विवादों के लिए न्याय क्षेत्र भोपाल होगा।

पत्र–संपादक के नाम

aksnews.com

फिजूलखर्ची की मार

कोई बेरोजगारी तो कोई व्यापार न चलने के कारण जान गवां रहे हैं। मनुष्य ने यह स्थितियां खुद बनाई हैं। आज व्यक्ति ने अपने खर्चे बहुत बढ़ा कर रखे हुए हैं। जरूरी है इन खर्चों की पूर्ति के लिए आय भी हो। लेकिन पिछले कुछ समय से रोजगार के हालात ठीक नहीं हैं।

● **कातिलाल मांडोत,** सागर (म.प्र.)

पृथ्वी का अस्तित्व

हम जिस थाली में खाएं उसी में छेद करना शुरू कर दें तो यह हमारी सबसे बड़ी नासमझीहोगी? पृथ्वी हमें निस्वार्थ भाव से जीने के लिए सब कुछ देती है, लेकिन हम इसे ही नुकसान पहुंचाते हैं और अपने स्वार्थ के लिए आंखें बंद किए रहते हैं। क्या यह हमारी नासमझी नहीं है?

● **राजेश कुमार चौहान,** जबलपुर (म.प्र.)

संकट के बीच

पूरे देश में कोरोना की मार अपने उफान पर है। मरीज ऑक्सीजन और दवाइयों के लिए दर-दर भटक रहे हैं। अस्पतालों में बिस्तर नहीं है। इससे दुर्भाग्य की क्या बात होगी कि कहीं दवाइयां चोरी हो रही हैं तो कहीं टीके। यह बहुत ही चिंताजनक और निराश करने वाली बात है।

● **आशीष,** इंदौर (म.प्र.)

हिंसा का चुनाव

पश्चिमी बंगाल में इस वर्ष का चुनाव हिंसक वारदात के बीच चल रहा है। चुनाव आयोग की सतर्कता की बाद भी बंगाल में निर्दोष मतदाताओं के खून से तारीख लिखी जा रही है। इस बार भी हिंसक झड़पों में मतदाता घायल हुए। पार्टियों की ओर से प्रचारित लालच में मतदाता पिसता चला जा रहा है। दोनों पक्ष एक दूसरे पर हमला करने के आरोप लगा रहे हैं। हिंसक टकराव से इतर देखें तो इस बार बंगाल का चुनाव रस्साकशी से भरा है। आगामी दो चरण का मतदान बाकी है। दो मई को चुनाव परिणाम घोषित होंगे। सुरक्षा की दृष्टि से चप्पे-चप्पे पर पुलिस के जवान खड़े हुए हैं। उसके बाद भी हिंसक झड़पों से पुराने दौर के हिंसक चुनावों की याद ताजा हो रही है।

● **दिलीप गुप्ता,** कोलकाता (प. बंगाल)

महामारी से इतर

सही है कि यह दौर बहुत मुश्किल है। लेकिन यह भी सच है कि महामारी की तमाम चुनौतियों के बावजूद मरीजों के स्वस्थ होने की दर संतोषजनक है। पनचानबे फीसदी लोग घर पर रह कर ही स्वस्थ हो रहे है। यह महामारी शरीर से अधिक मस्तिष्क पर प्रहार कर रहा है। आज कल चारों ओर कोरोना संबंधी समाचारों की बाढ़ आ गई है। बार-बार एक ही तरह का समाचार सुन और पढ़ कर लोगों के मस्तिष्क में महामारी का खौफ बैठ गया है। बार-बार नकारात्मक विचारों से शरीर के अंदर नकारात्मक ऊर्जा का प्रवाह होने लगता है।

● **हिमांशु शेखर,** नई दिल्ली

रोजगार की समस्या

गांवों में रोजगार नहीं मिलने और कमाई घटने से प्रवासी मजदूर शहर की ओर रुख कर रहे हैं। सेवानिवृत्त सांख्यिकी और आर्थिक सेवा अधिकारियों और शिक्षाविदों के सर्वे से यह जानकारी मिली है। सर्वे से पता चला है कि नियमित वेतन या मजदूरी पाने वाले प्रवासी मजदूरों का गांव में मन ही नहीं लग रहा है। शहरों से पलायन करने के चलते मप्र में प्रवासी मजदूरों की आय 85 फीसदी कम हो गई। इसलिए मजदूर पलायन को मजबूर हैं।

● **रघुनंदन सिंह,** उज्जैन (म.प्र.)

पाठकों से निवेदन

कृपया अपनी प्रतिक्रियाएं पक्ष या विपक्ष जो भी संभव हो इस पते पर भेजें

अक्स

150 जोन-1, मनोरमा काम्पलेक्स,
एफ-02, 03, एमपी नगर, भोपाल

चुनाव प्रचार नहीं समाज सेवा कहिए

कोरोना की दूसरी लहर से जनता हालाकान है तो नेता भी कम परेशान नहीं हैं। इन सबके बीच सबसे बड़ा सच है चुनाव। इस कारण नेताओं में राजनीति का तो पता नहीं पर समाज सेवा का गजब का जज्बा जरूर नजर आ रहा है। हिमाचल में आने वाले दिनों में दो उपचुनाव हैं। एक है कांगड़ा में फतेहपुर विधानसभा का और दूसरा मंडी संसदीय हलके का। इसके बाद दिसंबर 2022 में विधानसभा के चुनाव हैं। उधर, कोरोना है कि जाने का नाम ही नहीं ले रहा है। पाबंदियां लग गई हैं। ऐसे में नेताओं के पास लोगों तक पहुंचने का कोई जरिया ही नहीं रह गया। लेकिन लोगों का दिल भी तो जीतना है। हालात को देखते हुए हिमाचल में भाजपा और कांग्रेस दोनों दल लोगों की मदद करने के लिए तत्परता दिखा रहे हैं। कांग्रेस पार्टी ने गांधी हेल्पलाइन चालू कर दी है। इसे देशभर में किया गया तो हिमाचल में भी कर दिया है। दो सेवानिवृत्त डाक्टरों को जिम्मा भी दे दिया गया। कांगड़ा में कांग्रेस के एक पूर्व मंत्री हैं सुधीर शर्मा। उन्होंने पहले ही मोर्चा मार लिया। उन्होंने अपने आलीशान भवन को कोरोना मरीजों के लिए देने का ऐलान कर दिया। जयराम सरकार में मंत्री हैं राकेश पठानिया। वह भी पीछे कैसे रहते। उन्होंने भी आनन-फानन में ऐलान कर दिया कि उनका नर्सिंग संस्थान कोरोना मरीजों के लिए इस्तेमाल हो सकता है।

पटनायक बने नायक

कोरोनावायरस की दूसरी लहर से सामना करने के लिए जिस तरह से ओडिशा की नवीन पटनायक सरकार ने काम किया है उसे कई मंचों पर सराहा जा रहा है। राष्ट्रीय पटल पर भाजपा के एकक्षत्र जैसे नेतृत्व के बीच नवीन पटनायक वैसे क्षेत्रीय क्षत्रप हैं जो जनकल्याणकारी योजनाओं के लिए केंद्र के साथ ईमानदारी से कदमताल की कोशिश करते हैं। जब महाराष्ट्र, दिल्ली, उप्र, आंध्र प्रदेश तेलंगाना जैसे राज्य ऑक्सीजन की कमी से पस्त हो गए तो पटनायक ने केंद्र से बात की और उन राज्यों को ऑक्सीजन भिजवाया जहां इसकी कमी की वजह से तबाही मची हुई थी। महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे ने संकट के इस समय में एक देश के रूप में खड़े होने और मदद करने के लिए पटनायक का आभार जताया। कोरोनारोधी टीके को 18 से 44 साल तक के लोगों को लगाने पर इसकी अलग-अलग कीमतों को लेकर विवाद शुरू हुआ तो पटनायक ने ऐलान किया कि राज्य के सभी लोगों को मुफ्त टीका लगाया जाएगा।

गुणा-भाग तेज

राष्ट्रीय जनता दल के नेता लालू प्रसाद यादव को जमानत मिल चुकी है। साथ ही उनको लेकर बिहार में सियासी सरगर्मी खूब दिख रही है। अटकलें हैं कि क्या लालू के पटना लौटने पर कोई बड़ा राजनीतिक उलटफेर देखने को मिल सकता है। उनकी जमानत के बीच दो राजनीतिक घटनाएं घटीं। पूर्व मुख्यमंत्री जीतनराम मांझी की पार्टी हिंदुस्तानी आवाम मोर्चा (हम) ने लालू को जमानत मिलने पर खुशी जताई है। मांझी की पार्टी नीतीश के नेतृत्व वाले बिहार राजग गठबंधन में है। लेकिन पिछले महीने विधान परिषद् के लिए 12 सदस्यों के मनोनयन के बाद से नाराज है। भाजपा और जद (एकी) के छह-छह सदस्य मनोनीत किए गए। मांझी अपनी पार्टी के लिए कम से कम एक सीट चाहते थे। वहीं राजद के वरिष्ठ नेता शिवानंद तिवारी ने अपने फेसबुक खाते पर अपनी एक फोटो डाल दी, जिसमें वे मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के साथ दिख रहे हैं। यूं तो यह फोटो चैती छठ का प्रसाद ग्रहण करने के दौरान औपचारिक मुलाकात की है, लेकिन राजनीति में इशारों का महत्व माना जाता है। इसलिए इस तस्वीर पर चर्चा का बाजार गर्म होना स्वभाविक है। अब देखना यह है कि लालू यादव के पटना पहुंचते ही क्या गुल खिलता है।

साधने की जुगत

उत्तराखंड के कुमाऊ मंडल के सल्ट विधानसभा क्षेत्र सियासत के दो खिलाड़ियों के लिए परीक्षा का केंद्र बना हुआ है। यहां मुख्यमंत्री तीरथ सिंह रावत और कांग्रेस के दिग्गज नेता व पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत की राजनीतिक इज्जत दांव पर लगी है। हरीश रावत ने बड़ी जद्दोजहद के बाद अपनी पसंदीदा उम्मीदवार गंगा पंचोली को टिकट दिलवाया। गंगा पंचोली को टिकट का विरोध हरीश रावत के एक जमाने में खास रहे रणजीत सिंह रावत ने किया। रणजीत रावत अपने बेटे के लिए टिकट चाहते थे। हरीश रावत ने रणजीत रावत के बेटे को टिकट का खूब विरोध किया। इसके बाद रणजीत रावत के समर्थकों ने भाजपा के उम्मीदवार महेश जीना का समर्थन किया। महेश जीना सल्ट विधानसभा क्षेत्र से विधायक रहे दिवंगत सुरेंद्र जीना के भाई हैं। वे अपने भाई का चुनाव प्रबंधन देखते थे। इस कारण उनका क्षेत्र में संपर्क बना हुआ है। सल्ट के समीकरणों के साथ ही नए मुख्यमंत्री तीरथ सिंह रावत की संभावित सीट को लेकर चर्चा चल निकली है।

वसुंधरा की नसीहत

कोरोना संक्रमण के बढ़ते मामलों को लेकर राजस्थान की पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे ने राजनीतिक दलों को एकजुटता की नसीहत दी है। उन्होंने कहा है कि यह समय राजनीति का नहीं, राज्य नीति पर चलने का है। भाजपा की राष्ट्रीय उपाध्यक्ष वसुंधरा राजे ने एक बयान में कहा, यह ऐसा समय है जब हमें राजनीति नहीं, राज्य नीति पर चलना है, तो आओ साथ चलें। राजे ने कहा कि कोरोना विषाणु संक्रमण के कारण सिर्फ कोई एक राज्य नहीं, पूरा देश संकट से गुजर रहा है। डरने की नहीं, सावधानी बरतने की जरूरत है। आपसी सहयोग बढ़ाने की जरूरत है। अभी हाल में राजस्थान में भाजपा ने तीन विधानसभा क्षेत्रों के उपचुनाव के दौरान स्टार प्रचारकों की सूची से वसुंधरा राजे का नाम गायब कर दिया। प्रचार के लिए वसुंधरा के भतीजे ज्योतिरादित्य सिंधिया को मैदान में उतारा। इसके बाद राजनीतिक गलियारों में कयास लगाए जा रहे हैं कि इस निर्णय के पीछे भाजपा कुछ बड़ी योजना बना रही है।

वेटिंग सीएम की कतार

2020 में जब प्रदेश में सत्ता परिवर्तन हुआ था, उससे पहले जो घटनाक्रम घटित हुए थे उस दौरान नई सरकार में सीएम के कई दावेदार थे। लेकिन सीएम की कुर्सी जिनको मिलनी थी, उन्हें मिल गई। इसके बाद भी वेटिंग सीएम की कतार कम होने का नाम नहीं ले रही। एक बार फिर से कई नेता सीएम बनने का सपना देखने लगे थे। इसकी वजह यह है कि सत्तारूढ़ पार्टी के गलियारे में यह चर्चा चल रही थी कि आलाकमान कोरोना संक्रमण कंट्रोल होने के बाद प्रदेश में बड़ा बदलाव कर सकता है। फिर क्या था, मप्र में पिछले एक साल से जो नेता स्वयं को वेटिंग सीएम कहलवाने में गर्व महसूस कर रहे हैं, वे फिर से सक्रिय हो गए हैं। पहले अटकलें चल रही थीं कि बंगाल चुनाव के बाद प्रदेश में फेरबदल हो सकता है। अटकलों के बीच वेटिंग सीएम की कतार में शामिल नेताओं ने अपनी सक्रियता खूब दिखाई। राजनीतिक सूत्रों के अनुसार प्रदेश में इस समय कम से कम चार नेता स्वयं को मुख्यमंत्री का दावेदार मान रहे हैं। प्रदेश के एक मंत्री के समर्थक तो पूरी तैयारी करके बैठे थे कि बंगाल चुनाव के बाद नेताजी का मुख्यमंत्री के रूप में शपथ लेना तय है। बंगाल चुनाव परिणाम के बाद अब प्रदेश में वेटिंग सीएम का पद पूरी तरह समाप्त माना जा रहा है। कल तक जो दावे और तैयारी कर रहे थे वे अब लगभग खामोश हो गए हैं। इसकी वजह यह है कि उन्हें विश्वास नहीं हो रहा है कि आलाकमान कोई परिवर्तन करेगा।

मैं हनुमान हूं, मुझे किसी की जरूरत नहीं

प्रदेश में फैले कोरोना संक्रमण के बीच कई राजनेता अपनी शिक्षा के अनुसार सेवाएं दे रहे हैं। ऐसे ही एक राजनेता इन दिनों चर्चा में हैं। डॉक्टर की डिग्रीधारी ये महाशय कोरोना संक्रमितों का मुफ्त में इलाज कर रहे हैं। उनकी सक्रियता को देखते हुए पिछले दिनों सरकार की तरफ से उन्हें सुझाव दिया गया कि वे स्वास्थ्य विभाग के अधिकारियों के साथ मिलकर काम करें। इस सुझाव पर माननीय ने तपाक से जवाब दे दिया कि मैं हनुमान हूं, मुझे काम करने के लिए किसी की जरूरत नहीं है। दरअसल, सूत्रों का कहना है कि उक्त नेताजी स्वास्थ्य विभाग के एक वरिष्ठ अधिकारी की कार्यप्रणाली से संतुष्ट नहीं हैं। उनका कहना है कि कोरोना संक्रमणकाल में स्वास्थ्य विभाग में डॉक्टर की डिग्रीधारी अधिकारियों को पदस्थ करना चाहिए, ताकि वे चिकित्सीय मापदंडों के अनुसार रणनीति बनाकर काम कर सकें। लेकिन इस विभाग में तो एक ऐसे अधिकारी को बड़ी जिम्मेदारी दी गई है, जिसे मैनेजमेंट के अलावा कुछ और नहीं आता है। इसलिए अच्छा है कि मैं अकेले ही अपनी हैसियत के अनुसार कोरोना संक्रमितों का इलाज करता रहूं।

अब रामकथा का वाचन करेंगे साहब

शिक्षा का अपना ही महत्व है। इस बात को मप्र कैडर के 1987 बैच के एक पूर्व आईएएस से बेहतर कौन जान सकता है। अपने सेवाकाल में सरकार के लिए संकटमोचक की भूमिका निभा चुके ये साहब अब सेवानिवृत्ति के बाद क्या करेंगे, इसको लेकर तरह-तरह के कयास लगाए जा रहे हैं। इसकी वजह यह है कि साहब प्रदेश में काफी लोकप्रिय, मिलनसार और सक्रिय अधिकारी रहे हैं। वे जहां भी रहे उन्होंने अपनी छाप छोड़ी है। वे लंबे समय से लेखन कार्य भी कर रहे हैं। उन्होंने कई धार्मिक आख्यानों पर पुस्तकें लिखी हैं। उनकी पठन-पाठन में तो रूचि है ही, साथ ही वे एक अच्छे वक्ता भी हैं। इसलिए कुछ लोग कयास लगा रहे हैं कि वे अब रिटायरमेंट के बाद किताबें लिखेंगे तो कुछ लोग कह रहे हैं कि वे बड़े वक्ता बन जाएंगे। इन तमाम कयासों पर उस समय विराम लग गया जब उक्त अफसर ने विगत दिनों एक कुछ सेकेंड का वीडियो जारी किया। यह वीडियो दरअसल उनकी भविष्य की रणनीति का प्रोमो है। यानी साहब अब राम चरितमानस के रहस्यों पर सारगर्भित व्याख्यान देंगे। उनका मूल विषय सुंदरकांड रहेगा। इस विषय पर वे पुस्तकें भी लिख चुके हैं। यानी यह तय है कि साहब खाली हाथ बैठने वाले नहीं हैं। वे यदि रामकथा बाचते नजर आएं तो आश्चर्य नहीं होगा। गौरतलब है कि साहब की साहित्य और धर्म पर मजबूत पकड़ तो है ही, साथ ही भारतीय संस्कृति के भी वे ज्ञाता हैं।

छवि के लिए आंकड़ेबाजी

देश में कोरोना की दूसरी लहर इस कदर जानलेवा हो गई है कि श्मशान और कब्रिस्तान लाशों से पटे हुए हैं। लेकिन अफसर आंकड़ेबाजी करके सरकार को गुमराह कर रहे हैं। वहीं जब यह मामला सुर्खियों में आया तो आंकड़ेबाजी करने वाले विभाग की महिला अधिकारी ने कहा कि हम तो सरकार की छवि बचाने के लिए ऐसा कर रहे हैं। गौरतलब है कि उक्त महिला अधिकारी की गिनती ईमानदार अफसरों में होती है। लेकिन इन्हें अपनी ईमानदारी के कारण कई बार सरकार के कोप का सामना करना पड़ा है। अब उक्त महिला आईएएस अधिकारी द्वारा कोरोना के मनमाफिक आंकड़ों को लेकर स्वास्थ्य विभाग में काफी चर्चा है। दरअसल मुख्यमंत्री की समीक्षाओं के दौरान एक आला आईएएस के इशारे पर यह आईएएस केवल वे ही आंकड़े और जानकारियां सामने ला रही हैं जिससे सरकार की छवि बनी रहे और मुखिया भी खुश रहें। मप्र में कोरोना के आंकड़ों के इस खेल को लेकर देश-दुनिया के अखबारों में खबरें छपने लगी हैं। इस आईएएस को वास्तविकता की नहीं सरकार की छवि की चिंता है।

दान या रिश्वत

प्रदेश की राजनीतिक और प्रशासनिक वीथिका में इन दिनों एक दान काफी चर्चा में है। यह दान संस्कारधानी के एक अस्पताल संचालक द्वारा रेडक्रॉस संस्था को दिया गया है। दरअसल इस अस्पताल पर लापरवाही से कोरोना के 5 मरीजों को मारने का आरोप है। अस्पताल में देर रात ऑक्सीजन खत्म हुई तो डॉक्टर सहित पूरा अस्पताल भाग खड़ा हुआ। एक-एक कर मरीज मरते गए तो पुलिस वालों ने दौड़ लगाकर सिलेंडर अस्पताल पहुंचाए और लोगों को बचाया। अस्पताल की लापरवाही की जांच घोषित की गई। इसी बीच अस्पताल प्रबंधन ने जिला प्रशासन से संबंध सुधारने की नीयत से 25 लाख का दान रेडक्रॉस को दे दिया। रेडक्रॉस के चेयरमैन कलेक्टर होते हैं। इस दान की खबर के साथ ही अस्पताल की लापरवाही की जांच रिपोर्ट भी सामने आ गई है, जिसमें अस्पताल प्रबंधन के खिलाफ एफआईआर करने की अनुशंसा की गई है। देखना है कि कलेक्टर एफआईआर करते हैं या 25 लाख के दान से प्रभावित होते हैं। फिलहाल संस्कारधानी में इस दान को रिश्वत बताया जा रहा है।

देश में हर तरफ कोरोना संक्रमण भयावह रूप ले चुका है। इसे हम मिलजुल कर ही हरा सकते हैं। दिल्ली में इस समय भगवान ढूंढना आसान है लेकिन अस्पताल में बेड ढूंढना मुश्किल। लेकिन ढूंढ ही लेंगे, बस हिम्मत मत हारना।

● **सोनू सूद**

सिद्धू को प्रदेश का प्रधान कैसे बना दें? मेरे सारे मंत्री उससे सीनियर हैं। अगर आप एक अच्छे वक्ता हैं तो क्या आप इन सभी के ऊपर लग जाओगे? यह फैसला पार्टी हाईकमान के हाथ में है, लेकिन अगर मुझसे पूछा जाएगा तो मैं कभी भी इसे स्वीकृति नहीं दूंगा। सिद्धू साढ़े चार साल पहले पार्टी में आए हैं। सुनील जाखड़ प्रदेश की कमान अच्छी तरह संभाल रहे हैं।

● **अमरिंदर सिंह**

पृथ्वी शॉ ने वह कर दिखाया जो मैं नहीं कर सका। सभी छह गेंदों पर 6 चौके लगाने का मतलब है कि हर गेंद को सही तरीके से गैप में खेलना, जो आसान नहीं है। मैं अधिकतम ओवर में 18 या 20 रन ही हासिल कर पाया था। मैं 6 चौके या 6 छक्के नहीं लगा सका। इसके लिए आपकी शॉट खेलने की टाइमिंग का सही होना जरूरी है। पृथ्वी में काफी क्षमता है।

● **वीरेंद्र सहवाग**

कोरोना महामारी से पूरे विश्व को मुक्त करने के लिए सभी को एक साथ आना होगा। पूरे विश्व के देशों को वैक्सीनेशन पर जोर देना होगा। भारत में वैक्सीनेशन कम होने के कारण संक्रमण तेजी से फैला है। हम भारत के साथ इस महामारी का मुकाबला करने को तैयार हैं।

● **जो बाइडेन**

देश में कोरोना संक्रमण के इस दौर में संक्रमितों को सहायता की जरूरत है। इस वक्त में हम सब साथ हैं। देश के हालात देखते हुए मेरे परिवार और मैंने बेड्स और जरूरी सामान उपलब्ध कराने में योगदान दिया है। हर दिन यह देखना दर्दनाक है कि हमारा देश किस दौर से गुजर रहा है। यह मैसेज पढ़ने वालों और उनके परिवार वालों की हेल्दी लाइफ के लिए मेरी दुआ है। सोशल मीडिया से दूर जा रही हूं। लेकिन प्लीज सही जानकारी साझा करना जारी रखें। ताकि मेरी टीम इसे आप सभी के साथ शेयर कर सके। प्लीज अपना ध्यान रखें और एक-दूसरे के प्रति आभारी और दयालू रहें। यह समय हमें कुछ करने के लिए प्रेरित कर रहा है। इसलिए आप से निवेदन है कि कोविड की गाइडलाइन का पालन करें और जरूरतमंदों की मदद करें।

● **ईशा गुप्ता**

वाक्युद्ध

इस महामारी के दौर में भी केंद्र की भाजपा सरकार राजनीति कर रही है। केंद्र एक तरफ वैक्सीनेशन पर जोर दे रहा है। वहीं दूसरी तरफ राज्यों को वैक्सीन नहीं मिल रही है। छत्तीसगढ़ ने 18 वर्ष से अधिक उम्र वालों को वैक्सीन लगाने की पूरी तैयारी कर ली है, लेकिन हमें जुलाई में वैक्सीन देने की बात कही जा रही है।

● **भूपेश बघेल**

राज्यों के पास पर्याप्त मात्रा में वैक्सीन है। कांग्रेस शासित राज्य लोगों की जान से खिलवाड़ कर रहे हैं। पहले वैक्सीनेशन पर सवाल उठाते रहे, अब वैक्सीन की कमी का रोना रो रहे हैं। जिन राज्यों ने वैक्सीन का ऑर्डर दिया है उन्हें कंपनियां डोज पहुंचा रही हैं। राज्य अपना काम इमानदारी से करें। यह वक्त राजनीति का नहीं है।

● **डॉ. हर्षवर्धन**

हंसते हुए रुलाकर चली गईं रेणु

21 अप्रैल 2021 भारतीय पत्रकारिता के लिए वह काला दिन था जब जानी-मानी पत्रकार और दि प्रिंट हिंदी की संपादक रेणु आगाल ब्रह्माण्ड में लीन हो गईं। इसके साथ ही पत्रकारिता जगत ने एक ऐसे पत्रकार को खो दिया जो बहुत खुशमिजाज, संजीदा और समझदार व्यक्तित्व की मालिक थीं। रेणु का इस दुनिया से जाना मेरे लिए व्यक्तिगत क्षति है। वह मेरी बहन तो थी ही साथ ही एक ऐसी दोस्त थी जो हर अच्छे-बुरे वक्त में मेरे साथ खड़ी रहीं। वह जब भी व्यथित होती थी या मैं जब भी थकता था, आपस में बात करते ही हमारी समस्याएं दूर हो जाती थीं। रेणु आगाल की पत्रकारिता की यात्रा पर बस यही कहा जा सकता है...

एक सोचता पत्रकार
एक लिखता पत्रकार
व्यवस्था से लड़ता पत्रकार
औरों के लिए समर्पित पत्रकार
विसंगतियों के भंवर में जलता पत्रकार
या मरने की राह पर चलता पत्रकार!

यानी अपनी पत्रकारिता की यात्रा में रेणु ने एक ऐसी मिसाल पेश की है जिसका लोहा देश के धुरंधर पत्रकार भी मानते हैं। दूसरों को न्याय दिलाने के लिए कलमतोड़ मेहनत करने वाली रेणु नई दिल्ली में एक सड़क दुर्घटना में घायल हो गई थीं और उपचार के दौरान अस्पताल में उनका निधन हो गया।

दि प्रिंट हिंदी की संपादक रेणु 25 मार्च को दिल्ली में एक सड़क दुर्घटना में गंभीर रूप से चोटिल हो गई थीं। दुर्घटना के बाद उन्हें दिल्ली स्थित अपोलो अस्पताल में भर्ती कराया गया था। दुर्घटना की खबर मिलते ही मैं भी भोपाल से फ्लाइट पकड़कर दिल्ली पहुंचा। मैं वहां कुछ कर तो नहीं सकता था, लेकिन मेरे जाने से परिवार को सपोर्ट मिला। इस दौरान जब रेणु के लिए खून की जरूरत पड़ी तो मेरे एक मित्र आईपीएस अधिकारी ने 4 यूनिट ब्लड की व्यवस्था की। 12 अप्रैल को जब मैं दोबारा दिल्ली गया तो रेणु स्वस्थ थी। मुंह में पाइप लगे होने के कारण वह बोल तो नहीं पा रही थी, लेकिन इशारों में हमारी बातचीत भी हुई। इस दौरान मैंने उससे कहा था कि तुम जल्द ही स्वस्थ हो जाओ तो हम पचमढ़ी घूमने चलेंगे।

जब अपोलो अस्पताल को कोविड अस्पताल बनाने के बाद उन्हें नोएडा स्थित कैलाश अस्पताल में शिफ्ट किया जा रहा था, उस दौरान रेणु ने मेरे साथ हाथ भी मिलाया। लेकिन मुझे क्या पता था कि फिर कभी ये हाथ नहीं मिल पाएंगे। कुछ दिन बाद उन्होंने अपनी अंतिम सांस ली। उनके निधन से पत्रकारिता जगत में शोक की लहर दौड़ गई। दुख की बात यह रही कि अंतिम समय में मैं अपनी बहन के पास नहीं था। दरअसल, कोरोना संक्रमण बढ़ने के बाद परिजनों ने कहा था कि पहले आप भोपाल में कोविड की जांच करा लो, फिर आना। कोविड जांच में देरी होने और रिपोर्ट आने में विलंब होने के कारण मैं उनकी अंतिम यात्रा में भी शामिल नहीं हो पाया। रेणु आज भले ही इस लोक में नहीं रही, लेकिन उनकी यादें और मुस्कुराता चेहरा हमेशा मेरे मस्तिष्क में रहेगा।

रेणु में बचपन से ही कुछ कर गुजरने का जज्बा था। दिल्ली विश्वविद्यालय के मिरांडा हाउस कॉलेज से स्नातक करने के बाद भारतीय जनसंचार संस्थान (आईआईएमसी) से पढ़ीं रेणु समाचार एजेंसी यूनीवार्ता और फाइनेंशियल एक्सप्रेस में काम करने के बाद 1996 में बीबीसी की हिंदी सेवा में बतौर प्रोड्यूसर शामिल हुईं और जल्द ही उन्होंने एक प्रभावशाली पहचान स्थापित कर ली। बीबीसी के बाद उन्होंने पेंग्विन इंडिया और जगरनॉट प्रकाशन समूहों में हिंदी की एडिटर के रूप में काम किया। इस समय वह वेबसाइट दि प्रिंट के हिंदी संस्करण की एडिटर थीं।

2018 में दि प्रिंट से जुड़ी रेणु ने अपने कैरियर की शुरुआत फाइनेंशियल एक्सप्रेस से की। जिसके बाद उन्होंने बीबीसी में लंबे समय तक काम किया। उन्होंने समाचार एजेंसी यूएनआई और एसियन ऐज में भी अपनी सेवाएं दी थीं। बतौर बीबीसी वर्ष 1996 में रेणु ने बीबीसी लंदन में प्रोड्यूसर के तौर पर शुरुआत की और जल्द ही प्रमुख समाचार कार्यकर्मों के अलावा युवाओं के लिए प्रसारित होने वाले लोकप्रिय कार्यक्रम 'नई पीढ़ी' को भी प्रस्तुत किया। बता दें कि रेणु अगाल ने बीबीसी के लिए लंदन और दिल्ली स्थित दोनों जगहों पर काम किया था।

● **राजेंद्र आगाल**

तुम्हारी बहुत याद आएगी रेणु

रेणु का जाना मेरे लिए व्यक्तिगत क्षति भी है। एक तो मैंने बहन खोई ही, साथ ही एक अच्छा दोस्त भी खोया है। परिवार के प्रति रेणु का समर्पण अतुलनीय रहा। जब बड़े भाई अनिल का देहांत मात्र 37 साल की उम्र में मोटर न्यूरॉन डिसीस से हुआ, तो उसने संकल्प लिया कि वह मां-पिताजी के लिए शादी नहीं करेगी। उसके बाद उसने मां-पिताजी के लिए एक पुत्री ही नहीं बल्कि दोस्त के साथ ही अभिभावक का भी रोल अदा किया। बहन और उनके दो बच्चों के साथ ही रेणु ने पूरे परिवार को समेटे रखा। वह जहां भी जाती अपनी छाप छोड़ देती थी। वह मुझे अपना भाई के साथ ही मार्गदर्शक भी मानती थी। इसलिए वह जो कुछ भी करती या जहां भी जाती मुझसे सलाह लेती-रहती थी। हम लोग अक्सर यात्राओं पर साथ जाते थे। पाक्षिक अक्स की नियमित स्तंभकार होने के कारण वह देश-विदेश के घटनाक्रमों से लेकर राजनीतिक और प्रशासनिक मुद्दों पर मुझसे चर्चा करती रहती थी। रेणु के जाने के बाद आज मेरी जिंदगी तथा मेरे परिवार में एक खालीपन आ गया है। इस खालीपन को और कोई नहीं भर सकता है। इसलिए रेणु तुम बहुत याद आओगी।

संगठन मजबूत नहीं होने के कारण राज्य में कांग्रेस और गुटबाजी एक-दूसरे के पर्याय बन चुके हैं। मौका कोई भी हो गुटों में बंटी कांग्रेस के नेता अपनों को ही शिकस्त देने में विरोधियों से भी हाथ मिलाने से गुरेज नहीं करते। इसलिए मप्र में कांग्रेस संगठन लगातार कमजोर होता जा रहा है, वहीं नेता दिन पर दिन मजबूत होते जा रहे हैं।

नेता मजबूत, संगठन कमजोर

वर्ष 2018 के विधानसभा चुनाव में पड़े 3,81,38,186 वोट में से 40.89 फीसदी यानी 1,55,95,154 वोट पाकर 114 सीटें जीतने वाली मप्र कांग्रेस आज देश में सबसे कमजोर स्थिति में है। दरअसल, सत्ता से बेदखल होने के बाद से मप्र कांग्रेस संगठन पूरी तरह क्षत-विक्षत हो गया है। पिछले एक साल में मप्र कांग्रेस संगठन न तो राज्य सरकार और न ही केंद्र सरकार के खिलाफ कोई बड़ा आंदोलन खड़ा कर सका और ना ही जनता के बीच अपनी पैठ बढ़ा पाया। प्रदेश कांग्रेस की इस स्थिति ने आलाकमान को चिंता में डाल दिया है। कांग्रेस की गुटबाजी और बिखराव का ही नतीजा है कि कोरोना संकट के इस दौर में विपक्ष को प्रदेश की जनता के साथ जिस तरह कंधे से कंधा मिलाकर खड़ा होना चाहिए, वैसा नजर नहीं आ रहा है। कुछ नेताओं को छोड़ दें तो अधिकांश नदारद हैं या फिर सिर्फ सोशल मीडिया पर सक्रिय हैं। सेवादल, महिला कांग्रेस, अनुसूचित जाति-जनजाति विभाग सहित अन्य अनुषांगिक संगठन भी सक्रिय दिखाई नहीं दे रहे हैं।

एआईसीसी के सूत्रों से मिली जानकारी के अनुसार देश की सबसे पुरानी यानी 136 साल पुरानी राजनीतिक पार्टी कांग्रेस की साल दर साल कमजोर होती स्थिति का आंकलन कराने के लिए दिसंबर 2020 से फरवरी 2021 के बीच एक सर्वे कराया गया। यह सर्वे एक दर्जन हिंदी भाषी राज्यों महाराष्ट्र, राजस्थान, मप्र, छत्तीसगढ़, उप्र, बिहार आदि में करवाया गया। इनमें सबसे अधिक कमजोर मप्र कांग्रेस का संगठन पाया गया। अब इस रिपोर्ट के आधार पर आलाकमान राज्यों के कांग्रेस संगठन में बदलाव करने जा रहा है।

अग्निपरीक्षा में पिछड़े नाथ

जानकारों का कहना है कि एआईसीसी की सर्वे रिपोर्ट में यह भी कहा गया है कि सत्ता जाने के बाद से कमलनाथ की लोकप्रियता लगातार गिर रही है। खासकर 28 सीटों पर हुए उपचुनाव में पार्टी की हार ने नाथ का ग्राफ तेजी से गिरा दिया। उपचुनाव में तीन नेताओं शिवराज सिंह चौहान, ज्योतिरादित्य सिंधिया और कमलनाथ की लोकप्रियता दांव पर थी। शिवराज-सिंधिया की जोड़ी ने 19 सीटें जीतकर न केवल अपनी सरकार को मजबूत कर लिया है, बल्कि अपनी लोकप्रियता भी सिद्ध कर दी है। अब दमोह उपचुनाव में कमलनाथ की साख दांव पर है। 2 मई को साफ हो जाएगा कि कमलनाथ कितने पानी में हैं। 15 साल बाद सत्ता में वापस आने के बाद भी कांग्रेस अपनी सरकार 15 माह ही चला पाई। माना जाता है कि कमलनाथ के कारण ही सिंधिया समर्थक मंत्री और विधायक पार्टी से बाहर हुए और सरकार गिर गई। इसलिए कमलनाथ के ऊपर सबसे बड़ी जिम्मेदारी है कि वे दमोह उपचुनाव जीतकर भाजपा के सामने बड़ी चुनौती खड़ी करें। मप्र में अपनी साख जमाने का कमलनाथ के सामने शायद यह आखिरी मौका है। दमोह उपचुनाव में भी जहां शिवराज सिंह चौहान के नेतृत्व में पूरी भाजपा जीतने के अभियान में जुटी हुई थी, वहीं कांग्रेस केवल कमलनाथ पर निर्भर थी।

15 साल बाद सरकार में आने के बाद मप्र में 15 माह में ही सत्ता से दूर हुई कांग्रेस भले ही दिन पर दिन कमजोर होती जा रही है, लेकिन उसके नेताओं की स्थिति में कोई अंतर नहीं आया है। वे अब भी मजबूत हैं। पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ मप्र में मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान के बाद दूसरे मजबूत और लोकप्रिय नेता हैं। वहीं पूर्व मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह इन दोनों नेताओं से किसी भी मायने में कम नहीं हैं। आज भी मप्र कांग्रेस में दिग्विजय सिंह के सबसे अधिक समर्थक कार्यकर्ता हैं। इनके अलावा पूर्व नेता प्रतिपक्ष अजय सिंह, पूर्व प्रदेश अध्यक्ष सुरेश पचौरी, अरूण यादव और कांतिलाल भूरिया भी दमदार हुए हैं। इनके अलावा जीतू पटवारी, डॉ. गोविंद सिंह भी अपने क्षेत्र के बड़े नेता हैं और सत्तारूढ़ भाजपा को लगातार चुनौती दे रहे हैं। इसके बावजूद प्रदेश कांग्रेस लगातार कमजोर होती जा रही है। इसकी वजह है संगठन का मजबूत आधार नहीं है।

संगठन मजबूत नहीं होने के कारण राज्य में कांग्रेस और गुटबाजी एक-दूसरे के पर्याय बन चुके हैं। मौका कोई भी हो गुटों में बंटे कांग्रेस के नेता अपनों को ही शिकस्त देने में विरोधियों से भी हाथ मिलाने से गुरेज नहीं करते। एक तरफ जहां सत्ताधारी दल भाजपा एकजुट होकर काम करती है, वहीं कांग्रेस में बिखराव साफ नजर आता है। इसी का नतीजा रहा है कि 15 साल बाद सत्ता में वापसी के बाद भी कांग्रेस 15 माह में ही सत्ता से दूर हो गई है। गौरतलब है

कि मप्र में कांग्रेस में अंदरूनी गुटबाजी किसी से छिपी नहीं है। हालांकि, मप्र कांग्रेस का कोई नेता गुटबाजी की बात स्वीकारता नहीं लेकिन राजनीतिक हलकों में यह बात आम है कि मप्र में कांग्रेस के सभी बड़े चेहरे कमलनाथ, दिग्विजय सिंह, अरुण यादव, सुरेश पचौरी, अजय सिंह और कांतिलाल भूरिया अलग-अलग गुटों में बंटे रहते हैं। प्रदेश कांग्रेस के एक नेता कहते हैं कि देश की सबसे पुरानी राजनीतिक पार्टी कांग्रेस में जो उथल-पुथल मच रही है उससे निराश होने की इसलिए कोई जरूरत नहीं है क्योंकि इसके 136 साल से भी लंबे इतिहास में जब भी ऐसा हुआ है उसके बाद यह पार्टी और अधिक मजबूत होकर खड़ी हुई है।

मप्र कांग्रेस के एक पूर्व विधायक कहते हैं कि 2018 में सरकार बनाने के बाद कमलनाथ ने एकला चलो की जो नीति अपनाई है उससे पार्टी में गुटबाजी और बिखराव तेजी से बढ़ा है। उनकी इसी नीति के कारण कांग्रेस के हाथ से सत्ता निकल गई। फिर 28 विधानसभा सीटों पर हुए उपचुनाव में भी वे कांग्रेस को एकजुट करके चुनाव नहीं लड़ पाए। इसका ही परिणाम है कि कांग्रेस मात्र 9 सीट ही जीत पाई। वह कहते हैं कि जिस सियासी संतुलन से कमलनाथ ने 2018 में मप्र में कांग्रेस को सत्ता दिलाई थी, उसके प्रभावहीन होने से पार्टी में गुटबाजी और नाराजगी फिर से सतह पर है। कभी मुखर, कभी मौन। नतीजा संख्या बल में मजबूत विपक्ष होकर भी कांग्रेस असरकारक नहीं दिखती और नतीजे निराशाजनक रहे हैं।

विधानसभा की 28 सीटों पर उपचुनाव में सत्ता की वापसी का मौका हाथ से जाने के बाद अब दमोह में कांग्रेस के हाथ भाजपा से हिसाब चुकाने का मौका है, लेकिन चुनावी प्रबंधन से लेकर चुनाव प्रचार तक में पार्टी की गुटबाजी खुलकर सामने आई है। दमोह उपचुनाव के लिए कांग्रेस ने जो स्टार प्रचारकों की सूची जारी की थी उसमें पूर्व मंत्री गोविंद सिंह, बृजेन्द्र सिंह राठौर और एनपी प्रजापति के नाम गायब थे। सूत्र बताते हैं कि वे नाराज हैं। ऐसी ही नाराजगी 28 सीटों के उपचुनाव में देखी गई थी, जिसे बाद में हार की वजह माना गया। दरअसल, 2018 में

प्रदेश कांग्रेस और फिर सरकार की कमान हाथ में लेकर कमलनाथ पहली बार मप्र में छिंदवाड़ा लोकसभा सीट से बाहर पूरी ताकत से दिखाई दे रहे थे। मप्र कांग्रेस में एक भी पत्ता बिना उनकी मर्जी के नहीं हिल सकता था, लेकिन सरकार को लेकर धारणा मजबूत होने लगी थी कि एक रिमोट दिग्विजय सिंह के हाथ में भी है। यही बारीक लकीर बाद में इस कदर दरार में बदली कि ज्योतिरादित्य सिंधिया ने अपने समर्थक मंत्री-विधायकों के साथ पार्टी छोड़ दी और सरकार गिर गई। यही नुकसान है, जिसके लिए कमलनाथ अपनों के निशाने पर नहीं आए, लेकिन इसके बाद हर फैसलों के लिए पार्टी में अंदरूनी तौर पर उन्हें निशाने पर लिया जाने लगा, बयान आने लगे और सदन से चुनावी समर तक एक तरह के असहयोग की तस्वीर उभरने लगी। 28 सीटों के उपचुनाव में कांग्रेस की हार का ठीकरा भी कमलनाथ के सिर फोड़ा गया। 2018 की तस्वीर की तुलना सरकार जाने के बाद के हालातों से करें तो पूर्व नेता प्रतिपक्ष अजय सिंह और पूर्व प्रदेश अध्यक्ष अरुण यादव, सुरेश पचौरी जैसे वरिष्ठ नेताओं की सक्रियता बेहद कम हुई है। पिछले दिनों गोडसे समर्थक बाबूलाल चौरसिया को कांग्रेस में शामिल करने पर भी नाथ अपनों से घिर गए थे। इस मामले में वरिष्ठ नेता मानक अग्रवाल को छह साल के लिए निष्कासित किया गया।

एआईसीसी ने अपने सर्वे रिपोर्ट में कहा है कि मप्र कांग्रेस संगठन की स्थिति क्षेत्रीय दलों से भी बदतर हो गई है। बीते विधानसभा चुनाव में कांग्रेस का प्रदर्शन काफी बेहतर रहा था। 2003 से लेकर अभी तक मप्र में जो चार विधानसभा चुनाव (2008, 2013 और 2018) चुनाव हुए हैं उनमें से 2018 के विधानसभा चुनाव में कांग्रेस ने सैकड़ा को पार करते हुए 114 सीटें जीती थी। वर्ष 2003 में कांग्रेस ने 38 सीट, 2008 में 71 सीट और 2013 में 58 सीट जीता था। आंकड़े के अनुसार वर्ष 2018 में कांग्रेस सबसे मजबूत स्थिति में थी। लेकिन करीब दो साल में ही आज मप्र कांग्रेस इतनी कमजोर हो गई है कि उसे देश के सबसे कमजोर संगठन का ताज मिल गया है। मप्र कांग्रेस के एक सक्रिय पदाधिकारी कहते हैं की केवल मप्र कांग्रेस संगठन में ही नहीं बल्कि राष्ट्रीय स्तर पर सुधार की जरूरत है। वह कहते हैं कि राष्ट्रीय स्तर पर पार्टी में सुधार की आवाज उठाने वाले 23 वरिष्ठ नेताओं के समूह जी-23 जैसा ही हाल पूरे देशभर की कांग्रेस में बनता दिख रहा है।

● **कुमार राजेन्द्र**

कांग्रेस संगठन भगवान भरोसे

कांग्रेस पार्टी की कार्यशैली को लेकर अंदर-बाहर चर्चाओं का दौर भी शुरू हो गया था। आलाकमान के सामने सबसे बड़ा सवाल यह है कि मप्र कांग्रेस में गुटबाजी कब और कैसे खत्म होगी। मप्र कांग्रेस के अब तक जितने प्रभारी बने हैं सबने शुरू में यही दावा किया कि पार्टी के भीतर जो गुटबाजी है वह जल्द खत्म हो जाएगी। लेकिन देखा यह गया है कि आज तक कांग्रेस की गुटबाजी को कोई रोक नहीं पाया है। कांग्रेस की बदहाल स्थिति पर कांग्रेस के नेता और पूर्व केंद्रीय मंत्री कपिल सिब्बल ने कहा था कि सच को स्वीकार करने के लिए कांग्रेस को अब बहादुर होना ही पड़ेगा और ये जितना जल्दी हो जाए उतना अच्छा है। दरअसल, आलाकमान ने केंद्र की राजनीति से कमलनाथ को लाकर मप्र कांग्रेस की कमान सौंपी थी तो उन्होंने सभी दिग्गज नेताओं के साथ समन्वय बनाकर काम करना शुरू किया। जिसका परिणाम यह हुआ कि वर्ष 2018 में हुए विधानसभा के आम चुनाव में भाजपा ने अपनी पंद्रह साल पुरानी सरकार गंवा दी थी। इसकी मुख्य वजह थी कांग्रेस में एकता। लेकिन सरकार बनते ही कांग्रेस में वर्चस्व की जंग शुरू हो गई। कांग्रेस के एक वरिष्ठ पदाधिकारी कहते हैं कि कमलनाथ मौके की नजाकत का आंकलन नहीं कर पाए।

मप्र का तेंदूपत्ता देश में सबसे अच्छी क्वालिटी का होता है। देशभर के तेंदूपत्ता व्यावसायियों की कोशिश रहती है कि वे मप्र के तेंदूपत्ते को अधिक से अधिक खरीदें। इसके लिए तेंदूपत्ता संग्रहण से पहले ही वे मप्र में सक्रियता बढ़ा देते हैं। लेकिन इस बार कोरोना और पत्ता तैयार नहीं होने के कारण तेंदूपत्ते के संग्रहण पर संकट मंडरा रहा है। उस पर मौसम भी खराब हो रहा है, जिसने समितियों की परेशानी बढ़ा दी है।

हरे सोने के संग्रहण पर ग्रहण

मप्र में हरा सोना यानी तेंदूपत्ता के संग्रहण पर इस बार कोरोना का साया मंडरा रहा है। प्रदेशभर के जंगलों में तेंदूपत्ता लहलहा रहा है। वहीं उसके संग्रहण के लिए आदिवासी और श्रमिक तैयार हैं। लेकिन सरकार ने अभी तक तेंदूपत्ता संग्रहण की तिथि घोषित नहीं की है। आशंका जताई जा रही है कि इस बार जिस तरह कोरोना गांव-कस्बों में पहुंचा है इसका असर तेंदूपत्ता संग्रहण पर पड़ सकता है। राज्य लघु वनोपज संघ ने तेंदूपत्ता संग्रहण पारिश्रमिक दर 2500 रुपए प्रति मानक बोरा निर्धारित कर दी है। संभावना जताई जा रही है कि इस बार प्रदेश में 19 लाख मानक बोरा से अधिक तेंदूपत्ता संग्रहण का लक्ष्य निर्धारित होगा। लेकिन मई की शुरुआत में ही आसमान में बादलों के जमघट के साथ आंधी-तूफान और बारिश का मौसम बन जाने से जंगलों में तेंदूपत्ता संग्रहण पर ग्रहण लगता नजर आ रहा है। वन अधिकारियों ने संकेत दिए कि तेंदूपत्ता इस समय लाल है और परिपक्व नहीं हो पाया है। इसकी तुड़ाई 8 से 10 मई के बीच शुरू हो सकती है।

वन विभाग के अधिकारी मानते हैं कि मई माह में कुछ समय पर्याप्त धूप मिल जाए तो तेंदूपत्ता का लक्ष्य जून से पहले ही पूरा हो सकता है। विभागीय जानकारी के अनुसार दो माह पहले मार्च के अंतिम सप्ताह में जंगलों में तेंदूपत्ता का शाखकर्तन कराया गया था। 45 दिन बाद मई में तेंदूपत्ता आ गया है, लेकिन अभी लाल होने से परिपक्व नहीं हो पाया है। इसका कारण आसमान में बादलों का होना है। इससे कड़ी धूप पत्ते को मिल नहीं पा रही है। वन विभाग के अनुसार जैसे ही आसमान साफ होगा, स्थानीय समितियां तेंदूपत्ता तुड़ाई की शुरुआत करेंगी।

पिछला साल 2020 तेंदूपत्ता संग्रहण के हिसाब से ठीक नहीं रहा। बेमौसम बारिश होने से तेंदूपत्ता पर्याप्त मात्रा में नहीं आ पाया था और तेंदूपत्ता की गुणवत्ता भी प्रभावित हुई थी। दरअसल मार्च के शाखकर्तन के बाद अप्रैल में पेड़ में तेंदूपत्ता आने के लिए तीव्र गर्मी चाहिए। बारिश का मौसम फिर से बनने पर तेंदूपत्ता को नुकसान पहुंचता है। कहा जाता है कि जितनी तेज गर्मी होगी, पत्ता उतना ही गुणवत्तायुक्त खिलेगा।

कोरोना संक्रमण की वजह से वन विभाग इस साल तेंदूपत्ता की मजदूरी का नकद भुगतान नहीं करेगा, बल्कि मजदूरों के बैंक खातों में यह राशि जमा की जाएगी। राज्य शासन से कोविड नियम का पालन करने के आदेश आ गए हैं। गांवों से बाहर तेंदूपत्ता संग्रहित कराया जाएगा। सोशल डिस्टेंसिंग और मास्क अनिवार्य होगा। बाहर से आने वाले ठेकेदारों के कर्मचारियों को अपनी नेगेटिव रिपोर्ट लानी होगी। स्थानीय स्तर पर भी टेस्ट कराने होंगे। फिलहाल संग्रहण की तैयारियां शुरू कर दी गई हैं।

इस वर्ष तेंदूपत्ता संग्रहण में कोरोना संक्रमण का साया नजर आएगा। इसके लिए तैयारियों का जो समय होता है, उसी दौरान लॉकडाउन की घोषणा हो गई, इस वजह से कई प्रमुख तैयारियां ठप रह गईं। इसमें सबसे बड़ी अड़चन बोरे की आएगी। अब तक सरकार की ओर से बोरे उपलब्ध नहीं कराए गए हैं। साथ ही ठेकेदारों के पास भी व्यवस्था नहीं है, इस संबंध में लघु वनोपज संघ एवं वन विभाग के अधिकारियों को ठेकेदारों की ओर से अवगत कराया गया है।

प्रदेश के अधिकांश जिलों में तेंदूपत्ता का संग्रहण तो स्थानीय श्रमिक ही करते हैं लेकिन पत्तों को बोरे में भरने का काम कराने के लिए महाराष्ट्र के गोदिया एवं अन्य जिलों के श्रमिकों से कराया जाता रहा है। इस बार कोरोना संक्रमण की वजह से इसका विरोध शुरू हो गया है। कई जगह से श्रमिकों ने कहा है कि महाराष्ट्र में कोरोना का संक्रमण अधिक है। ऐसे में वहां से आकर यहां में संक्रमण फैला सकते हैं। वन विभाग के अधिकारियों ने भी इस मामले में ठेकेदारों को आगाह किया है।

● **राजेश ग्रोवर**

कोरोना से बचाने एडवाइजरी जारी

प्रदेश सरकार ने कोरोना संक्रमण के कारण जारी लॉकडाउन के दौरान लघु वनोपज, संग्रहण प्रसंस्करण, उपचरण, परिवहन, भंडारण और विपणन कार्यों में संलग्न श्रमिकों और ग्रामीणों को संक्रमण से बचाने के निर्देश दिए हैं। वनोपज संग्रहण के दौरान किसी संग्राहक अथवा वनकर्मी में कोरोना वायरस के लक्षण दिखते हैं तो उसे तुरंत निकटतम अस्पताल पहुंचाने के लिए कहा गया है। लघु वनोपज के संग्रहण में संलग्न कर्मचारी, क्रेता और प्रतिनिधि श्रमिक और ग्रामीण अनिवार्य रूप से चेहरे को मास्क, फेसकवर, गमछा, रुमाल, दुपट्टे से ढंककर रखेंगे। तेंदूपत्ता क्रेताओं और उनके प्रतिनिधियों के लिए वन मंडल अधिकारी अथवा प्रबंध संचालक जिला यूनियन द्वारा पूर्व से निर्धारित परिचय पत्र जारी किए जाएंगे। प्रत्येक संग्रहण एवं भंडारण केंद्र और गोदाम पर आवश्यक रूप से सैनिटाजर और साबुन रखा जाएगा। यहां सभी संबंधित के लिए आने और जाने, दोनों समय 20 सैकंड तक हाथ धोकर हाथ सैनिटाइज करना जरूरी होगा। वनोपज संग्रहण आदि कार्यों में संलग्न सभी व्यक्ति आपस में कम से कम 2 मीटर की दूरी बनाए रखते हुए काम करेंगे। प्रत्येक संग्रहण केंद्र पर 2-2 मीटर की दूरी पर चूने का घेरा बनेगा। इन केंद्रों पर रात में कार्य के लिए उचित प्रकाश व्यवस्था होगी।

मप्र में मेडिकल माफिया सक्रिय

अस्पतालों में हाई एंटीबायोटिक की जोर आजमाइश

कोरोनाकाल के चलते न केवल मरीज बल्कि डॉक्टर भी बेहद डरे हुए हैं। बड़े अस्पतालों में भी मरीजों के दाखिल होते ही हाई एंटीबायोटिक के डोज शुरू किए जा रहे हैं। अस्पतालों में मरीज के परिजन तो दूर डॉक्टर भी कोई रिस्क नहीं लेना चाहते। इसलिए सामान्य रूप से पहुंचे मरीज भी गंभीर मरीजों की तरह ट्रीट किए जा रहे हैं। आलम यह है कि इन बड़े-बड़े अस्पतालों में मौजूद मेडिकल स्टोर तक में दवाइयां उपलब्ध नहीं हैं। वहीं डाक्टरों की नासमझी के चलते शहर के सारे मेडिकल स्टोर दवाओं के अभाव से जूझ रहे हैं। जो मेडिकल रिप्रजेंटेटिव अस्पतालों में घंटों डॉक्टरों के इंतजार में कतार लगाते थे अब दवाइयों के लिए डॉक्टर उन्हें फोन लगा रहे हैं। शहर में हाई एंटीबायोटिक दवाइयों के डोज जहां अनुपलब्ध हैं, वहीं शरीर में इम्युन सिस्टम बढ़ाने वाले इम्युसिन जैसे इंजेक्शन भी मरीजों को नहीं मिल पा रहे हैं जिनकी कभी डिमांड नहीं रही है। इसके अलावा भूख बढ़ाने वाले, डिप्रेशन मिटाने वाले इंजेक्शन भी या तो उपलब्ध नहीं है या उनकी कीमतें मरीजों की पहुंच से बाहर है।

राजधानी भोपाल ही क्या पूरे प्रदेश में मेडिकल माफिया कुछ इस तरह सक्रिय हो गया है कि जिन मरीजों का इलाज दवाओं से संभव हैं, उन्हें इंजेक्शन और बाटल ड्रिप लगाई जा रही है और जिन्हें साधारण एंटीबायोटिक ड्रग्स की आवश्यकता है, उन्हें जीवन रक्षक दवाओं के हाईडोज से लेकर रेमडेसिविर और टोसी इंजेक्शन में झोंका जा रहा है। आलम यह है कि बड़े अस्पताल में जहां मरीज महंगी और अनुपलब्ध दवाइयों के लिए परिजनों को झोंका जा रहा है, वहीं फर्जी और नकली झोलाछाप डॉक्टर भी मरीजों का इलाज कर पैसा ऐंठने में लगे हैं। कुल मिलाकर कुछ डॉक्टरों द्वारा ही मरीजों के लिए डरावनी व पैनिक स्थितियां बनाई जा रही है कि वह गंभीर स्थिति में पहुंचकर जान गंवा रहे हैं।

बढ़ते मरीज... डर का माहौल... बीमार होते ही अस्पताल की चिंता और अस्पताल पहुंचते ही डॉक्टरों का मानसिक दबाव... कोरोना के इस काल में साधारण मरीजों को भी गंभीर स्थिति में पहुंचा रहा है। कोरोना का प्राथमिक उपचार तयशुदा दवाइयों के साथ समय पर शुरू होने से स्थितियां संभल जाती है, लेकिन वर्तमान हालात में दवाइयां लेते मरीजों के जेहन में कोरोना का डर कुछ इस कदर विकराल बनाया जा रहा है कि जैसे ही उसे अस्पताल की सुविधा मिलती है, वह वहां जाकर स्वयं को सुरक्षित करने में जुट जाता है, लेकिन डॉक्टर उसका बिल बढ़ाने के लिए ओरल दवाइयां बंद कराकर उन्हें आरवी ट्रीटमेंट यानी इंजेक्शन और ड्रिप की ओर धकेल देते हैं, फिर शुरू होता है महंगी दवाइयों का दौर... कई एंटीबायोटिक के डोज और इन दवाइयों के साइड इफेक्ट मरीजों को जब बेचैन करने लगते हैं तो उन्हें बीमारी गंभीर लगने लगती है।

बस यहीं से शुरू हो जाता है अस्पतालों से लेकर डॉक्टरों का खेल, सबसे पहले रेमडेसिविर के इंतजाम में परिजनों को झोंका जाता है, जिसके 5 डोज लगाए जाते हैं, लेकिन परिजन 2-3 डोज का भी इंतजाम मुश्किल से कर पाते है और अस्पताल मरीज के परिजनों को डोज की कमी को गंभीर स्थिति का जिम्मेदार बताकर स्वंय की जिम्मेदारी से मुक्त होने का क्रम करने लगते हैं। इसके साथ ही कई गंभीर एंटीबायोटिक के हाई डोज के चलते मरीज की मानसिक और शारीरिक स्थिति बिगड़ जाती है। घबराए मरीज इसी दौरान ऑक्सीजन लेवल खोने के साथ ही अपनी आत्मशक्ति यानि विलपॉवर भी खो देते हैं और बात आईसीयू तक पहुंच जाती है। कोविड के इन वर्तमान हालातों में डॉक्टरों की इस प्रेक्टिस पर नियंत्रण का तो कोई उपाय है नहीं, स्वास्थ्य विभाग कोई मेडिकल प्रोटोकाल भी लागू नहीं कर पा रहा है और मरीज जान गंवा रहे हैं। वहीं परिजन मानसिक और आर्थिक संत्रास भोग रहे हैं। वर्तमान हालातों में जिन अस्पतालों में कोविड का इलाज किया जा रहा है वहां केवल अस्पताल के नाम पर बिस्तर उपलब्ध होते हैं। इन नर्सिंग होम या अस्पतालों में सिटी चेस्ट जैसी सुविधा तो बहुत दूर की बात है ब्लड टेस्ट के लिए पैथालाजी तक उपलब्ध नहीं होती है। जबकि कोरोना के इलाज के मानक निर्धारित करने के लिए फेफड़ों में फैले संक्रमण की स्थिति जानने के लिए सिटी स्कैन जहां जरूरी है वहीं ब्लड में फेरेटिन की मात्रा जानने के लिए ब्लड टेस्ट जैसी सुविधाएं आवश्यक हैं। लेकिन इन अस्पतालों में इन दोनों सुविधाओं के साथ ही ऑक्सीजन की सुविधा के लिए उन्हीं सिलेंडरों का इस्तेमाल किया जा रहा है जिनके जरिए फिलहाल मरीज घरों पर ही इलाज करने में जुटे हुए हैं। वर्तमान हालातों में इन अस्पतालों को कोविड केयर का नाम तो दिया जा सकता है लेकिन यहां पूर्ण इलाज की सुविधा उपलब्ध नहीं होने पर भी डाक्टरों द्वारा महंगे इंजेक्शनों और इंटीबायोटिक से इलाज किया जा रहा है।

देशभर में कोरोना का कहर तो जारी है ही, वहीं मप्र में भोपाल और इंदौर भी पिछले डेढ़ माह से इसकी चपेट में है और पिछले 15-20 दिनों से तो कोरोना कर्फ्यू और लॉकडाउन में सख्ती भी की गई और उम्मीद थी कि मई के इस पहले हफ्ते से मरीजों की संख्या में तेजी से गिरावट आएगी। मगर सूत्रों के मुताबिक बीते 24 घंटे में भी बड़ी संख्या में मरीज मिले हैं। जबकि उसके दो-तीन दिन पहले अवश्य कुछ कमी आई थी। 10 हजार से अधिक सैम्पलों की जांच भी रोजाना कराई जा रही है। बावजूद इसके डेढ़ हजार से भी अधिक मरीज मिल जाते हैं। विशेषज्ञों-डॉक्टरों का कहना है कि नया स्ट्रैन अत्यंत घातक तो है ही, वहीं सुपर स्प्रेडर यानी तेजी से फैलने वाला भी है। यही कारण है कि पूरे परिवार के साथ आसपास के लोगों को भी संक्रमित कर रहा है। अब मई अंत तक राहत मिलने और उसके बाद धीरे-धीरे कमी आने की बात कही जा रही है। फिलहाल तो संक्रमण की रफ्तार तेज ही है।

● **अरविंद नारद**

200 रोज भी नहीं कमा पाते 117 लाख मजदूर

कोरोना के कारण जहां शहरों से पलायन हो रहा है, वहीं गांवों में बेरोजगारी सबसे बड़ी समस्या बनी हुई है। सरकार मनरेगा से बेरोजगारी दूर करने की बात कह रही है, लेकिन मजदूरी इतनी कम है कि उससे पेट पालना मुश्किल हो रहा है।

सरकार ने व्यवस्था संभालने वाले शासकीय कर्मचारियों के वेतन में जहां बेतहाशा वृद्धि की है, वहीं दूसरी ओर अपने श्रम से देश या प्रदेश को संवारने वाले मजदूरों की मजदूरी बढ़ाने पर विचार नहीं किया है। 100 दिन रोजगार की गारंटी देने वाली मनरेगा योजना इसका सबसे बड़ा उदाहरण है। यह इसलिए भी आश्चर्यजनक लगता है क्योंकि यहां पंजीकृत 117 लाख मजदूरों को बढ़ती महंगाई के इस दौर में 200 रुपए रोज भी नहीं मिल पा रहे हैं।

यह स्थिति तब सामने आ रही है, जबकि मप्र में अकुशल कर्मचारियों के लिए भी न्यूनतम मजदूरी जिलाधीश द्वारा 280 रुपए निर्धारित किया गया है। यह बात दूसरी है कि कोरोना संक्रमण के इस दौर में महंगाई भत्ते के साथ कोई नई मजदूरी दर अभी निर्धारित नहीं की गई है। बावजूद इसके भारत सरकार द्वारा मनरेगा श्रमिकों को दी जाने वाली प्रतिदिन मजदूरी के मुकाबले अभी भी 87 रुपए ज्यादा है। क्योंकि इस योजना के तहत मप्र में काम करने वाले मजदूरों को रोजाना 193 रुपए से ज्यादा नहीं दिए जा रहे हैं। जबकि यह तथ्य किसी से छिपा नहीं है कि साढ़े सात करोड़ की आबादी वाले इस प्रदेश में 117 लाख यानी प्रति 7 व्यक्ति में एक बेरोजगारी दूर करने के लिए मनरेगा में काम कर रहा है। पड़ोसी राज्यों के मुकाबले मप्र में भारत सरकार द्वारा निर्धारित की गई 193 रुपए की यह सबसे कम मजदूरी दर है। हालांकि कभी अभिन्न अंग रहे छत्तीसगढ़ में भी इसी दर से मजदूरों को भुगतान किया जा रहा है। बावजूद इसके महाराष्ट्र में 238, गुजरात में यह 224, राजस्थान में 220 और उप्र में यह 201 रुपए के हिसाब से भुगतान की जा रही है। जबकि देशभर में सबसे ज्यादा मजदूरी 309 रुपए हरियाणा, 308 रुपए सिक्किम और 280 रुपए गोवा जैसे छोटे राज्यों में मिल रही है।

मप्र में उच्च कुशल श्रमिकों के दिनभर का पारिश्रमिक का निर्धारण सरकार ने 400 भी नहीं किया है। श्रम विभाग के निर्देशानुसार इनकी प्रतिदिन की मजदूरी 398 रुपए से ज्यादा नहीं है। वहीं कुशल श्रमिक के मामले में यह 354 रुपए में अटक जाती है। जबकि अर्धकुशल 309 और अकुशल अभी भी कानूनन 280 रुपए ही पाने के हकदार हैं। वहीं दूसरी ओर सरकार ने संविदा और दैवेभो कर्मचारियों से इतर शासकीय कर्मचारियों के लिए सातवें वेतनमान के तहत दिया जाने वाला वेतन 2 हजार प्रतिदिन से कम नहीं किया है। जबकि राज्य में संविदा, कार्यभारित, आकस्मिक निधि से वेतन प्राप्त करने वाले कर्मचारियों से इतर नियमित कर्मचारियों की संख्या 6 लाख 47 हजार 795 ही है। प्राप्त जानकारी के अनुसार प्रदेश में करीब 70 लाख लोग खेतिहर मजदूरी पर निर्भर हैं। यह प्रदेश की कुल जनसंख्या का करीब 10 फीसदी है। इनकी मजदूरी भी बमुश्किल 300 रुपए से ज्यादा नहीं होती है। कोरोना संक्रमण के इस दौर में बढ़ती महंगाई को देखते हुए सरकार ने इनकी मजदूरी बढ़ाने पर भी ध्यान नहीं दिया है। यह अभी भी 228 रुपए है।

राज्य में 2 करोड़ लोग असंगठित क्षेत्र में काम कर रहे हैं। इनमें सीमांत लघु कृषक व कृषक श्रमिकों को छोड़ दिया जाए तो खनिकर्म में 0.64 लाख, विनिर्माण में 14.95 लाख, संनिर्माण में 8.97, व्यापार, होटल रेस्टोरेंट में 17.47, परिवहन में 3.95 लाख और अन्य में 11.78 लाख लोग कम मजदूरी के बाद भी अपनी आजीविका चलाने के लिए मजबूर हैं। परिश्रम के बाद भी वाजिब मजदूरी नहीं मिलने के कारण प्रदेश के करीब सात लाख मजदूर रोजगार के लिए दूसरे राज्यों पर निर्भर हैं। बीते साल कोरोना संक्रमण में वापस लौटे इन श्रमिकों की संख्या सरकार ने 7 लाख 37 हजार बताई है। महाराष्ट्र, गुजरात, हरियाणा, तेलंगाना, पंजाब, कर्नाटक, गोवा, केरल, राजस्थान और दिल्ली जैसे राज्यों से लौटे इन प्रवासी श्रमिकों व उनके परिवार के सदस्यों को लेकर सरकार ने दावा किया है कुल 13,10,186 हितग्राहियों को भारत आत्मनिर्भर योजना के अंतर्गत निशुल्क राशन उपलब्ध कराया गया है। वहीं 3,24,715 श्रमिकों को संबल योजना और 15,722 श्रमिकों को मप्र भवन संनिर्माण मंडल की योजनाओं से लाभ दिलवाने का प्रयास किया गया है।

● **जितेन्द्र तिवारी**

मनरेगा पर बढ़ा दबाव

अप्रैल यानी मौजूदा वित्त वर्ष के पहले महीने में मनरेगा के तहत काम मांगने वालों में परिवारों और लोगों की संख्या पिछले सात साल में सबसे ज्यादा रही। गांवों में काम की मांग बढ़ने की सबसे बड़ी वजह कोविड के चलते मार्च-अप्रैल के दौरान बड़ी संख्या में मजदूरों की घर वापसी हो सकती है। मनरेगा के डैशबोर्ड से मिली जानकारी के मुताबिक, इस साल अप्रैल में 2.6 करोड़ परिवार और 3.7 करोड़ लोग रोजगार ढूंढ रहे थे। प्रतिशत के हिसाब से देखें तो पिछले साल से 91 प्रतिशत ज्यादा परिवारों और 85 प्रतिशत ज्यादा लोगों को रोजगार की जरूरत थी। दो साल पहले यानी अप्रैल 2019 में दो करोड़ परिवार और तीन करोड़ लोग इस ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना के तहत काम तलाश रहे थे। इसका नेगेटिव पहलू यह है कि इस रोजगार गारंटी योजना के तहत काम मांगने वाले हर शख्स को काम नहीं मिल पाया। आंकड़ों के मुताबिक, पिछले महीने सिर्फ 1.52 करोड़ परिवारों और 2.07 करोड़ लोगों को ही काम मिल पाया था। यानी मनरेगा में रोजगार मांगने वाले हर 100 परिवार में से सिर्फ 58 और हर 100 लोगों में 56 को ही काम मिला। इसी तरह अप्रैल में मनरेगा के तहत 18.87 करोड़ श्रम दिवस (एक व्यक्ति के लिए इतने दिन का काम) हुआ। औसत के हिसाब से देखें तो जिन परिवारों को काम मिला वे सिर्फ 12.41 दिन काम कर पाए।

अवैध खनन लॉक नहीं

लॉकडाउन के दौरान प्रदेश में नर्मदा सहित अन्य नदियों में रात के अंधेरे में जमकर रेत का खनन किया जा रहा है। हाइवा-डंपरों के जरिए खाली पड़े खेतों में रेत का भंडारण किया जा रहा है। भंडारण ऐसी जगह किया जा रहा है, जहां प्रशासन की नजर न पड़े। रेत माफियाओं पर नकेल कसने में प्रशासन नाकाम साबित हो रहा है। रेत माफिया द्वारा क्षेत्र के ग्रामीणों को धमकाया जाता है, जिससे वे चुप रहते हैं। इस तरह रात में डंपर-हाइवा से रेत का परिवहन और भंडारण किया जा रहा है। रेत माफिया बड़े पैमाने पर रेत का भंडारण इसलिए कर रहे हैं ताकि बरसात में उसको ऊंचे दाम पर बेचा जा सके।

हर क्षेत्र के एसडीएम, तहसीलदार और खनिज विभाग के अधिकारी भी पिछले एक माह से रेत के अवैध खनन की सुध नहीं ले सके हैं। उनकी ड्यूटी कहीं चेक पोस्ट के निरीक्षण करने तो किसी क्वारैंटाइन सेंटर की व्यवस्था में लगी है। इससे वे खनन माफियाओं पर ध्यान नहीं दे पा रहे हैं। रेत माफिया इसी का फायदा उठा रहे हैं। हालांकि, कुछ नेता प्रशासन पर यह आरोप जरूर लगा रहे हैं कि कहीं-कहीं तो अधिकारी माफिया से सांठगांठ कर उन्हें जानबूझकर मौका दे रहे हैं।

रेत खदानों में खनन की स्वीकृति के बाद रेत निकासी करने वाली कंपनी की मशीनें बेलगाम हो गई हैं। जहां औने-पौने रूप में नदी के सीने पर भारी मशीनों को चलाकर रेत का खनन करने में जुटी है। इसके लिए नदियों में मोटी चौड़ी बांध रूप में बेड (रास्ता) बनाकर रेत का खनन किया जा रहा है। इसमें जहां जलीय जीवन प्रभावित हो रहा है, वहीं रेत खनन कंपनी की मौजूदगी के बाद जिले में बहने वाली छोटी-छोटी नदी-नालों के अस्तित्व पर खतरा मंडराने लगा है। रेत के अवैध कारोबार से जुड़े रेत माफिया अब वनीय, राजस्व क्षेत्र में बहने वाली छोटी-छोटी नदियां और नालों पर अपनी नजरें जमा उसका खनन कर रहे हैं। इससे पर्यावरण को जहां नुकसान हो रहा है वहीं शासकीय राजस्व की चोरी भी हो रही है। लेकिन इन सब में रेत खनन करने वाली कंपनी द्वारा सबसे अधिक राजस्व की चोरी से इंकार नहीं किया जा सकता।

नदियों से रेत खदान की आड़ में कंपनी द्वारा खदानों की सीमाओं को लांघकर निर्धारित सीमा से अधिक रेत का खनन कर रहे हैं। यही नहीं कुछ स्थानों पर बिना विभागीय प्रक्रियाओं को पूर्ण किए खनन भी आरंभ कर दिया था। जिस पर विभाग में हुई शिकायत पर खनिज विभाग ने सीतापुर, मानपुर, और बकही रेत खदानों में कार्रवाई करते हुए सीमा से अधिक खनन करने का मामला दर्ज करते हुए 68 हजार घन मीटर रेत खनन में 36 करोड़ से अधिक का जुर्माना अपेक्षित किया है। खनिज विभाग का कहना है कि नदियों में सीमा रेखा खींचना असंभव है, लेकिन कंपनी को इस बात की जानकारी दी जाती है कि कहां से लेकर कहां तक खनन किया जाना है। खनन में नदियों की धारा को प्रभावित किए बिना निर्धारित मात्रा में भी खनन किया जाना है। लेकिन विभागीय निर्देशों की अनदेखी करते हुए कंपनी कर्मी रेत का खनन आंखें मूंदकर कर रहे हैं। जानकारों का मानना है कि जिला मुख्यालय की सोन, तिपान, चंदास, केवई, गोडारू, अलान सहित अन्य नदियों से रेत अवैध तरीके से निकाले जा रहे हैं। इनमें विभागीय परिमाप किया जाएं तो रेत के अवैध उत्खनन के दर्जनों प्रकरण सामने आ सकते हैं।

नदियों में मशीन से खुदाई के दिए गए निर्देश में नियमों की अनदेखी की जा रही है। ठेकेदार अपने तरीके से नदियों में बांध बनाकर मशीनों को उतार रहे हैं। नदियों में खुदाई के दौरान कितनी चौड़ाई में रास्ता बनाकर पानी रोकना और फिर कितनी गहराई में खुदाई करना है, इसका पालन नहीं किया जा रहा है। इससे नदी की धारा भी प्रभावित हो रही है। पेट्रोल-डीजल, गैस सिलेंडर के बढ़े दामों के साथ लोगों को अब रेत भी महंगी खरीदनी पड़ रही है। सरकार नई रेत नीति में भी लोगों को सस्ती रेत नहीं दिला पा रही है। रेत संपदा से भरपूर होशंगाबाद जिले में लोग दोगुने दाम में रेत खरीदने को मजबूर हैं। इस साल जिले का ठेका 262 करोड़ रुपए में गया, जो प्रदेश का सबसे महंगा ठेका था। सरकार अधिक राजस्व देने के कारण नई ठेका कंपनी एक ट्रॉली रेत पर 1800 रुपए रॉयल्टी ले रही है। इसका फायदा उठाकर रेत चोर 3 हजार रुपए तक में एक ट्रॉली रेत बेच रहे हैं। लोगों को निर्माण के लिए मजबूरी में महंगी रेत लेनी पड़ रही है। करबला, नर्मदापुल के नीचे, सहित नर्मदा के कई घाटों से रेत की चोरी लगातार हो रही है।

● **नवीन रघुवंशी**

ठेका निरस्त होने पर भी नर्मदा से हो रहा रेत का अवैध उत्खनन

रायसेन जिले में रेत का ठेका निरस्त होने के बाद भी नर्मदा से अवैध रेत उत्खनन बदस्तूर जारी है। रायसेन जिले में अवैध रेत का परिवहन करने के लिए मालनबाड़ा खदान की जा रही रॉयल्टी नरसिंहपुर जिले की सीमा से लगे होशंगाबाद के सर्रा किशोरी घाट पर किया जा रहा रेत का अवैध उत्खनन। जिले की रेत खदानों के पूर्व ठेकेदार के द्वारा ठेका राशि पूर्ण रूप से जमा न करने पर ठेका निरस्त कर दिया गया है। इसके बाद भी रेत का अवैध कारोबार अधिकारियों की मिलीभगत से जारी है। रायसेन, नरसिंहपुर, सीहोर और होशंगाबाद जिले की सीमा क्षेत्र में पोकलेन मशीनों से रेत का अवैध उत्खनन किया जा रहा है। रायसेन और भोपाल सहित अन्य जिलों में रेत अवैध रूप से पहुंचाई जा रही है। नर्मदा से रेत के अवैध कारोबारी बगैर किसी डर के सरकार को करोड़ो रुपए का नुकसान पहुंचा रहे हैं। रेत के अवैध कारोबारी होशंगाबाद जिले के गैर चिन्हित सर्रा किशोरी घाट से पोकलेन मशीनों से रेत का खनन कर रहे हैं। यहां से डंपर में भरकर रेत मांगरोल पुल पार कर रायसेन जिले में आ रही है। रायसेन में रेत का अवैध परिवहन करने के लिए होशंगाबाद और नरसिंहपुर जिले की सीमा क्षेत्र पर चल रही मालन बाड़ा खदान की रॉयल्टी का उपयोग किया जा रहा है। सर्रा किशोरी के बहुत बड़े गैर चिन्हित क्षेत्र में चौबीसों घंटे पोकलेन मशीनों से अवैध खनन किया जा रहा है। आश्चर्य की बात तो यह है कि खनिज विभाग की सूची में सर्रा किशोरी खदान नहीं है। सर्रा किशोरी खदान विभाग की सूची में दर्ज नहीं होने के बावजूद कई वर्ष से इस खदान से अवैध रूप से रेत का खनन किया जा रहा है।

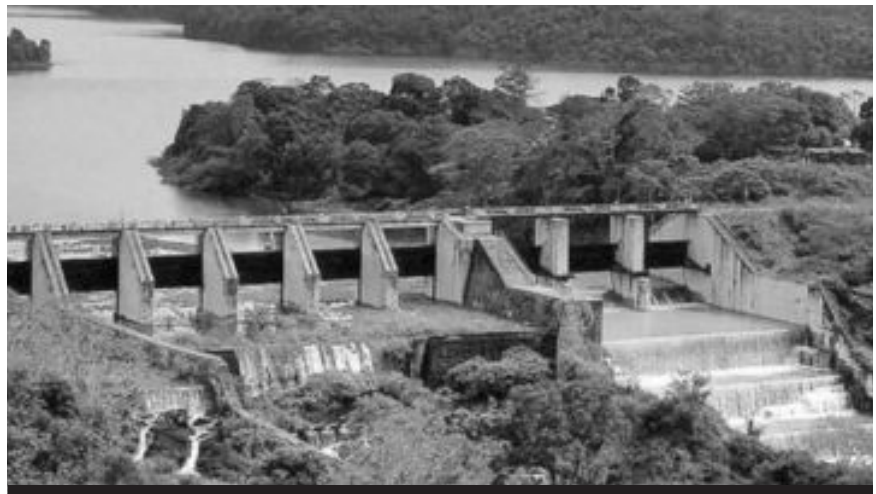

जवान होंगे मप्र के उम्रदराज बांध!

भूगर्भशास्त्रियों और वैज्ञानिकों की चेतावनी के बाद केंद्रीय जल आयोग ने जुलाई 2019 को मप्र के 59 बांधों सहित देशभर के 100 साल पुराने 220 बांधों के पुनरुद्धार की कार्ययोजना बनाई थी। अब करीब 2 साल बाद सरकार को अपनी कार्ययोजना की याद आई है और मप्र के दरक रहे उम्रदराज बांधों को जवान बनाने (पुनरुद्धार करने) के लिए करीब 600 करोड़ रुपए खर्च किए जाएंगे। प्रदेश के 23 बांध तो ऐसे हैं जो जर्जर हो गए हैं। उनमें से अधिकांश खतरे की जद में हैं। अहमदाबाद स्थित भूकंप अनुसंधान संस्थान का कहना है कि अगर इनके आसपास 7.9 मैग्नीट्यूट तीव्रता वाला भूकंप आता है तो हर तरफ जलजला हो जाएगा क्योंकि मप्र के कई बांधों की स्थिति इतना तेज झटका बर्दाश्त करने की नहीं है। भूगर्भशास्त्रियों और वैज्ञानिकों के मुताबिक, मप्र अपेक्षाकृत कम खतरे वाले हिस्से जोन-3 में आता है। इस कारण यहां के बांधों के निर्माण में भूकंपरोधी क्षमता की ओर अधिक ध्यान नहीं दिया गया है। जानकारी के अनुसार, जिन बांधों का इस राशि से पुनरुद्धार किया जाएगा उनमें से अधिकांश सफेद हाथी बने हुए हैं। यानी न उनसे सिंचाई होती है और न ही बिजली बनती है।

गौरतलब है कि 2019 में केंद्रीय जल आयोग ने 100 साल से पुराने देश के 220 बांधों को चिन्हित कर उनका पुनरुद्धार करने के लिए रजिस्टर किया था। इनके पुनरुद्धार और सुधार के लिए 3,466 करोड़ रुपए स्वीकृत भी किए गए थे। साथ ही राज्यों को निर्देश दिया गया था कि बांधों के संरक्षण के लिए आपदा प्रबंधन योजना और आपातकालीन कार्ययोजना बनाएं। उसके बाद मप्र सरकार और बांध से जुड़ी उसकी एजेंसियों ने बांधों की कार्ययोजना तैयार की थी, लेकिन करीब दो साल तक मामला लटका रहा। अब प्रदेश की शिवराज सरकार इस दिशा में आगे बढ़ रही है। सिंचाई विभाग के सूत्रों के मुताबिक पहले चरण में जिन पुराने बांधों का रखरखाव किया जाना है उनमें भगवंत सागर, चंदिया तालाब, वीरपुर तालाब, गांधी सागर बांध, हथसाई खेड़ा बांध, चोरल परियोजना, चंदोरा परियोजना, गाडगिल सागर परियोजना, केरवा बांध, माही परियोजना, नंदनवारा तालाब, वीर सागर, बहोरी बांध परियोजना, राजघाट परियोजना, यसाकाल्दा तालाब, मनसूरवारी परियोजना आदि शामिल है। इसमें भी सबसे अधिक राशि 286 करोड़ से अधिक गांधी सागर परियोजना पर खर्च किया जाना प्रस्तावित है।

एक पंथ दो काज की तर्ज पर सरकार बांधों के पुनरुद्धार करने के साथ ही सिंचाई सुविधा बढ़ाने पर जोर दे रही है। प्रदेश सरकार द्वारा लगातार किए जा रहे सिंचाई सुविधा में वृद्धि के प्रयासों के तहत अब बूढ़े हो चुके करीब दो दर्जन से अधिक बाधों का नए सिरे से रखरखाव किए जाने की तैयारी की गई है। इन पर कुल मिलाकर 600 करोड़ रुपए की राशि खर्च होने का अनुमान है। यह राशि सिंचाई विभाग कर्ज के माध्यम से जुटाएगा। यह वे बांध हैं जिनका निर्माण हुए करीब पांच दशक से अधिक का समय हो चुका है। इन बाधों का रखरखाव करने के साथ ही नए सिरे से कुछ इलाकों में नहरों का निर्माण भी किया जाएगा।

सिंचाई विभाग के सूत्रों के मुताबिक इसके लिए सरकार द्वारा विश्व बैंक से 455 करोड़ का कर्ज लेने की तैयारी की जा रही है। इसके अतिरिक्त इसमें 20 फीसदी राशि का हिस्सा राज्य सरकार द्वारा दिया जाएगा। माना जा रहा है कि इस 551 करोड़ के खर्च के बाद प्रदेश में करीब 5 लाख हैक्टेयर जमीन में नए सिरे से सिंचाई सुविधा बढ़ जाएगी। दरअसल लंबे समय से रखरखाव न होने की वजह से इन बांधों के गेट से लेकर पाल तक जर्जर अवस्था में पहुंच चुके हैं। इन सभी का सुधारकार्य किया जाना जरूरी हो चुका है। इस कर्ज के लिए विश्व बैंक द्वारा प्रदेश सरकार को स्वीकृति दी जा चुकी है। गौरतलब है कि करीब डेढ़ दशक पहले भी प्रदेश सरकार ने इसी तरह के कई बेहद पुराने बांधों की मरम्मत पर कर्ज लेकर 1900 करोड़ व्यय किए थे। उस समय भी अधिकांश पैसा नहरों के निर्माण पर खर्च किया गया था। यही वजह है कि अब प्रदेश में सिंचाई विभाग के पास 33 लाख हैक्टेयर इलाके में सिंचाई की सुविधा मौजूद है।

नर्मदा नदी पर जो पांच बांध बने हैं, उनमें से कुछ से ही बिजली मिल पा रही है। सरदार सरोवर बांध से बनने वाली 21 हजार मेगावाट में से करीब 1450 मेगावाट बिजली प्रदेश को मिलनी थी। इस 56 फीसदी बिजली में से एक यूनिट भी बिजली नहीं मिल पाई है। इंदिरा सागर

कई बांध सफेद हाथी

प्रदेश में एक तरफ सरकार पुराने बांधों का पुनरुद्धार कर सिंचाई क्षमता बढ़ाने का प्रयास कर रही है, वहीं दूसरी तरफ मप्र की लाइफ लाइन नर्मदा नदी पर बने पांच बांध सफेद हाथी साबित हो रहे हैं। इन बांधों के जरिए बिजली और सिंचाई के दावे सिर्फ दावे बनकर रह गए हैं। जबकि इन बांधों के कारण हजारों लोग विस्थापन, बाढ़, बेरोजगारी, भूखमरी का दंश झेल रहे हैं। नर्मदा नदी पर कुल 30 बड़े बांध और उसकी सहायक 45 नदियों पर 135 मझोले और 3000 छोटे बांधों का निर्माण किया जाना है। अब तक नर्मदा नदी पर सरदार सरोवर बांध को मिलाकर पांच बांध बन चुके हैं। लेकिन एक बारगी इन बांधों के लाभों पर गौर करें तो समझ आ जाएगा कि ये बांध बस खड़े हो गए हैं। इससे मिलने वाला लाभ नाकाफी है। 49 साल पहले यानी 1972 में प्रदेश सरकार ने नर्मदा नदी पर 30 बड़े बांध बनाने की योजना बनाई थी। लेकिन अब तक 5 बांध बरगी, इंदिरा सागर, महेश्वर, ओंकारेश्वर और सरदार सरोवर बांध बने हैं। बांधों के निर्माण के समय बिजली उत्पाद और सिंचाई के बड़े-बड़े दावे किए गए थे। लेकिन इन बांधों से न बिजली मिल पा रही है और न ही पर्याप्त सिंचाई की व्यवस्था हो पाई है। सूत्रों के अनुसार, नर्मदा न्यायिक प्राधिकरण द्वारा मप्र को 18.25 मिलियन एकड़ फीट (एमएएफ) नर्मदा कछार जल का बंटवारा किया था। प्रदेश द्वारा अपने हिस्से का पानी उपयोग के अनुसार 29 बांधों की योजना बनाई गई। लेकिन अब तक जो बांध बने हैं, उनसे नुकसान ज्यादा हुआ है। लाभ कम हुआ।

बांध से 1 हजार मेगावाट बिजली उत्पादन होना बताया गया। लेकिन यह कितने समय में बनती है, इसे समय के सापेक्ष देखना व पानी की उपलब्धता पर निर्भर है। ओंकारेश्वर बांध से 520 मेगावाट बिजली उत्पादन क्षमता है। बिजली भी बनाई जा रही है। वहीं महेश्वर बांध से अब भी बिजली उत्पादन शुरू नहीं हुआ है। ऐसे में इन बांधों की उपयोगिता पर सवाल उठने लगा है। नर्मदा नदी पर बने पांचों बांधों से अधिकृत रूप से 6.69 लाख हैक्टेयर सिंचाई किया जाना था। लेकिन इसका औसत केवल 23 फीसदी ही अब तक सिंचाई हो पा रही है। बरगी बांध बड़वानी, सिवनी और जबलपुर जिले में साढ़े चार लाख हैक्टेयर में सिंचाई का दावा था। अभी 60-70 हजार हैक्टेयर में ही सिंचाई हो रही है। रीवा व सतना के 855 गांवों को पानी मिलना था, जो अभी तक नहीं मिला। इंदिरा सागर बांध से 1.93 लाख हैक्टेयर में सिंचाई होना है। मुख्य नहरें व उप नहरों का निर्माण करीब 90 फीसदी हुआ है। वितरण नहरों का निर्माण शेष है। वहीं ओंकारेश्वर बांध से 2.46 लाख हैक्टेयर में सिंचाई होना थी। लोगों को इसका लाभ मिला। पांच बांधों के निर्माण से प्रदेश को प्रस्तावित लाभ तो नहीं हो पाए, लेकिन इन परियोजनाओं में 702 गांवों को डुबो दिया गया। ध्यान रखने वाली बात यह कि ये डुबोए गए गांव अधिकृत थे। इसके अलावा भी हर बांध में जलस्तर अधिक होने के कारण सैकड़ों और डूबे लेकिन उनका रिकॉर्ड सरकार के पास नहीं है।

मप्र में जिन बांधों का पुनरुद्धार होना है उनमें से अधिकांश जर्जर अवस्था में हैं। सरकार भी इस बात को लेकर चिंतित है, क्योंकि प्रदेश के 23 बांध 100 साल से भी अधिक पुराने हो गए हैं और अधिकांश खतरे की जद में हैं। वैज्ञानिक डॉ. अशोक कुमार कहते हैं कि जिस तरह टिहरी बांध 9 से 10 मैग्निट्यूड के भूकंप को भी झेलने में सक्षम है उस तरह की क्षमता मप्र के बांधों में नहीं है। वैसे भी मप्र के बांध पिछले कुछ सालों से जर्जर अवस्था में पहुंच गए हैं। गत वर्षों में बारिश के दौरान डिंडौरी का गोमती बांध, हमेरिया बांध, रामगढ़ी, सिमरियानग, चांदिया, गोरेताल, लोकपाल सागर, भरोली सहित करीब दर्जनभर बांधों में रिसाव और दरार आने से आसपास के क्षेत्रों में दहशत फैल गई थी। हालांकि समय पर इन बांधों के रिसाव और दरार को दुरुस्त कर दिया गया, लेकिन ये घटनाएं इस बात का संकेत दे गईं हैं कि अगर बांधों की लगातार देखरेख और मरम्मत नहीं की गई तो ये कभी भी जानलेवा बन सकते हैं। प्रदेश के करीब 91 बांध उम्रदराज हैं और ये कभी भी दरक सकते हैं। वाटर रिसोर्स डेवलपमेंट के आंकडों के अनुसार प्रदेश में पेयजल उपलब्ध कराने, सिंचाई और बिजली उत्पादन के लिए 168 बड़े और सैकड़ों छोटे बांध बनाए गए हैं।

गेट से ज्यादा खतरा

बांधों में सबसे ज्यादा खतरा गेट के खराब होने का रहता है। हर साल गेट की मरम्मत होनी जरूरी है। ज्यादातर गेट के रबर-सील कट जाते हैं, जिन्हें नहीं सुधारने पर बगैर गेट खोले ही पानी बहने लगता है। इसके अलावा चोक नालियां भी खतरा बन सकती हैं। पिछले चार साल से करीब दो दर्जन बांध जब बारिश के दिन में लबालब होते हैं तो उनके गेट से पानी बहने लगता है। लेकिन मप्र वाटर रिसोर्स डेवलपमेंट इस ओर ध्यान नहीं दे रहा है। बताया जाता है कि हर साल सैकड़ों एकड़ खेती तो बांध से निकले पानी से ही खराब हो जाती है। विभागीय अधिकारियों का कहना है कि तीन साल पहले एक रिपोर्ट तैयार की गई थी, जिसमें बांधों की बदहाल स्थिति को बताया गया था। लेकिन रिपोर्ट फाइलों में ही दब कर रह गई थी। प्रदेश के कई बांधों में रिसाव की समस्या आम है। आए दिन रिसाव वाली जगह से बांधों के आशिंक रूप से टूटने की खबरें आती रहती हैं।

नर्मदा बचाओ आंदोलन की नेत्री मेधा पाटकर कहती है कि देखरेख और मेंटेनेंस के अभाव में कई छोटे-बड़े बांध बूढ़े और जर्जर हो चुके हैं। इनमें से कुछ की उम्र 100 साल से ज्यादा है। इन उम्रदराज बांधों को लेकर बेपरवाह प्रशासन ने न तो इन्हें डेड घोषित किया और न ही मरम्मत की कोई ठोस पहल की। ऐसे में लबालब होने पर अगर ये बांध दरक गए या टूट गए तो कभी भी बड़ी तबाही ला सकते हैं। इन बांधों की वजह से नदियां भी अपनी दिशा बदल सकती हैं। इससे भी बड़ा खतरा पैदा हो सकता है। लेकिन इस ओर कभी किसी का ध्यान नहीं गया है। प्रदेश के लगभग आधा सैकड़ा बांधों की उम्र 50 साल पूरी हो चुकी है। जबकि 23 बांध तो 100 साल से भी ज्यादा पुराने हैं। ऐसे में इन बांधों की ठोस मरम्मत नहीं होने से इनके आधार कमजोर हो चले हैं। विशेषज्ञों के मुताबिक बड़े बांधों की उम्र 100 वर्ष व छोटे बांधों की उम्र लगभग 50 वर्ष मानी जाती है। इस उम्र तक इन बांधों की मजबूती बनी रहती है। बाद में ये धीरे-धीरे कमजोर होने लगते हैं। साथ ही नदियों के साथ आने वाले गाद भी बांधों को प्रभावित करते हैं। इससे बांधों की क्षमता कम होने लगती है। वाटर रिसोर्सेज से जुड़े एक्सपर्ट इंजीनियर बांधों की उम्र 50 और 100 साल बताते हैं। छोटे बांधों को 50 वर्ष के हिसाब से डिजाइन किया जाता है, जबकि बड़े बांधों की उम्र 100 साल बताई जाती है। बांधों के सिलटेशन और मजबूती दोनों के आधार पर उम्र तय होती है। वर्तमान में ज्यादातर बांधों की उम्र बहुत ज्यादा हो चुकी है। जानकारों का कहना है कि जब बांध बने थे तब ज्यादातर स्थान जंगल थे।

जानकारों का कहना है कि नर्मदा में आने वाली बाढ़ से पर्वत चारों तरफ से कट रहा है। पर्वत पर कभी जंगल हुआ करता था, लेकिन क्षेत्र में गिनती के पेड़ रह गए हैं। पर्वत पर मठ, आश्रम, दुकान, मकान बन गए हैं। पर्वत की तलहटी में ज्योतिर्लिंग मंदिर है, यह क्षेत्र अवैध भवन निर्माणों से घिरता जा रहा है। पर्वत पर अतिक्रमण हो रहे हैं। उल्लेखनीय है कि नर्मदा हाइड्रोइलेक्ट्रिक डेवलपमेंट कार्पोरेशन लिमिटेड द्वारा बनाई गई ओंकारेश्वर जल विद्युत परियोजना में बांध द्वारा 520 मेगावाट बिजली बनाने की क्षमता है। बांध में कुल 23 गेट लगे हैं। यहां पर 189 मीटर जलस्तर तक (समुद्र तल से) पानी भरा जाता है। अगर यह बांध दरकता है तो बड़ी जन हानि होगी। वहीं संजय सरोवर परियोजना के तहत बनाए गए एशिया के सबसे बड़े मिट्टी के बांध पर खतरा मंडरा रहा है।

● **रजनीकांत पारे**

गोचर भूमि गायब

मप्र में सरकारी रिकार्ड से जमीनों के गायब होने की पड़ताल के दौरान ग्वालियर जिले में साल 2004 के बाद से 15 हजार हैक्टेयर चरनोई यानि की गोचर की भूमि गायब पाई गई है। आनन-फानन में कलेक्टर ने इसकी जांच बैठा दी है लेकिन मामला रसूखदार भूमाफियों से जुड़ा हुआ है, तो प्रशासन भी कुछ नहीं कर पा रहा है क्योंकि उसके ही लैंड रिकार्ड विभाग में इन जमीनों की 552 फाइलें गायब हैं। जिनकी बढ़ी शिद्दत से तलाश की जा रही है। वहीं कांग्रेस और भाजपा एक-दूसरे पर हमला कर रही है। लेकिन इस बीच यही सवाल है कि क्या 15 हजार हैक्टेयर जमीन शासन को वापस मिल पाएगी।

जानकारी के अनुसार मप्र में 1968 के बाद भू-अभिलेख विभाग में रिसायतकालीन जमीन को चरनोई यानि की गोचर की भूमि के लिए हर एक ग्राम पंचायत में आरक्षित किया गया था। लेकिन आज वो जमीन सरकारी नक्शे से गायब हो गई है। आनन-फानन में इसकी जांच बैठाई गई है तो चौकानें वाले खुलासे हो रहे हैं। जिसमें 552 फाइलें गायब हैं तो वहीं 15 हजार हैक्यटेर चरनोई यानि की गोचर की भूमि तो वहीं 23 हजार हैक्यटेर पड़त (सरकारी उपजाऊ) भूमि पर दंबगों का कब्जा मिला है। ये जो आंकड़े हैं, वो चौंकाने वाले हैं। ऐसे में कांग्रेस और भाजपा दोनों इस मुद्दे पर आमने-समाने आ गए है। कांग्रेस कह रही है ये सारी जमीनें 2004 के बाद से गायब हुई है। ग्वालियर जिला प्रशासन और भू-अभिलेख विभाग की जांच में चौंकाने वाले आंकड़े सामने आ रहे हैं। जांच में जो आकड़े प्रशासनिक अफसरों को मिले है, उसमें 10 हजार हैक्टेयर जमीन पर दबंगों का कब्जा है। ऐसे में अफसर उन जमीनों को लिस्टेड कर रहे हैं जिन पर कब्जाधारी दंबगों पर बेदखली की कार्रवाई करने के साथ-साथ प्रशासन के निचले राजस्व के अधिकारियों को राउंडअप कर रहे हैं जिनकी शह पर जमीनों का ये फर्जीवाड़ा हुआ है।

सूत्रों का कहना है कि प्रदेश में विकास के नाम पर जमीनों की ऐसी बंदरबांट की गई है कि अफसरों ने रसूखदारों को पड़त और चरनोई भूमि बांट दी है। पिछले एक दशक में प्रदेश में करीब 25,000 हैक्टेयर चरनोई भूमि पर या तो अतिक्रमण हो गया है या फिर रसूखदारों को आवंटित कर दी गई है। मार्च 2010 में विधानसभा में मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने यह आश्वासन दिया था कि प्रदेश में यदि किसी कलेक्टर ने किसी व्यक्ति के लिए चरनोई भूमि की अदला-बदली की है तो ऐसे मामलों की जांच कर उसे निरस्त किया जाएगा। लेकिन आज 10 साल बाद स्थिति यह है कि प्रदेश के 22,000 गांवों में चरनोई भूमि ही नहीं बची है। मप्र भू-राजस्व संहिता 1959 की धारा 237 (1) के तहत चरनोई भूमि को पृथक रखा जाना है और इस पर शासन का अधिकार रहता है। लेकिन मुख्यमंत्री के आश्वासन को राजस्व अमले ने गंभीरता से नहीं लिया था।

दरअसल प्रदेश में भू-माफिया, दलाल, पूंजीपतियों और राजस्व अधिकारियों की मिलीभगत से चरनोई भूमि को लूटा जा रहा है। प्रदेश में सर्वाधिक चरनोई भूमि की बंदरबांट उन जिलों में हुई है जहां तेजी से विकास हुआ है। कटनी, सतना, रीवा, शहडोल, छतरपुर, ग्वालियर, भिंड सहित करीब दो दर्जन जिलों में करोड़ों रुपए की चरनोई भूमि पर प्रशासन की ढुलमुल नीति और लचर व्यवस्था के चलते असरदार भू-माफिया के कब्जे में चली गई है। सरकारी जमीन को अतिक्रमणकारियों के कब्जे से मुक्त कराने के नाम पर अधिकारी कागजी कार्रवाई में उलझे रहते हैं। चौतरफा हो रहे सरकारी जमीन पर अतिक्रमण को रोक पाने में प्रशासन बौना साबित हो रहा है। शासकीय संपत्ति का किस प्रकार दोहन किया जा रहा है और इसकी देखभाल करने के लिए रखे गए जिम्मेदार अधिकारी, कर्मचारी किस प्रकार अपनी जिम्मेदारी निभा रहे हैं इसका अंदाजा इसी से लगाया जा सकता है कि सरेआम भू-स्वामित्व और राजस्व रिकार्ड की बेशकीमती सरकारी भूमि भू-माफिया के कब्जे जा रही है, किंतु शासन और प्रशासन हाथ पर हाथ धरे बैठा है। पट्टे की भूमि को हड़पने का खेल राजस्व रिकार्ड में अहस्तांतरणीय के 'अ' पर सफेदा लगाकर कई एकड़ भूमि को खुर्दबुर्द करने का अधिकारियों व कर्मचारियों ने किया था। अधिकारियों व कर्मचारियों ने अहस्तांतरणीय का 'अ' विलोपित कर उसे हस्तांतरणीय बना दिया जिससे पट्टा व चरनोई की हजारों एकड़ भूमि निजी फैक्ट्रियों के कब्जे में चली गई है और वहां बेजा निर्माण कार्य भी करा लिए गए।

● **विकास दुबे**

3200 हैक्टेयर वन भूमि पर अतिक्रमण

मप्र में भू-माफिया किस कदर पावरफुल है इसका अंदाजा इसी से लगाया जा सकता है कि जिस दौरान पूर्ववर्ती कांग्रेस सरकार माफिया मुक्त मप्र का अभियान चला रही थी, उसी दौरान में माफिया ने वन विभाग की करीब 3200 हैक्टेयर से ज्यादा भूमि पर कब्जा कर लिया। इसमें से ज्यादातर भूमि पर रसूखदारों ने वन्य संपदा को नष्ट किया है। वन मुख्यालय भोपाल से मिले आंकड़े के अनुसार प्रदेश में 1 जनवरी 2019 से 31 दिसंबर 2019 तक 3201 हैक्टेयर भूमि पर नया अतिक्रमण किया है। जिसमें सबसे ज्यादा अतिक्रमण इंदौर वन वृत्त के अंतर्गत खंडवा, खरगौन, बुरहानपुर जिले में हुए हैं। इंदौर वन वृत्त में 492 हैक्टेयर वन भूमि पर माफिया ने अतिक्रमण किया है। खास बात यह है कि सरकार सिर्फ 9 हैक्टेयर भूमि से ही कब्जा हटाने में कामयाब हो पाई है। इसी तरह इसी अवधि में खंडवा वन वृत्त में 801 हैक्टेयर, शिवपुरी वन वृत्त में 868 हैक्टेयर, बैतूल में 154 हैक्टेयर, सागर में 131 हैक्टेयर और ग्वालियर 108 हैक्टेयर वन भूमि पर माफिया ने अतिक्रमण किया है। एक साल की अवधि में वन भूमि पर अतिक्रमण से जुड़े 1828 प्रकरण दर्ज किए गए हैं। वैसे देखा जाए तो मप्र में भू-माफिया की नजर सबसे अधिक वन भूमि पर रहती है। सरकारी सूत्रों से मिली जानकारी के अनुसार मप्र में पिछले 30 साल में रसूखदारों ने 5,747 वर्ग किमी वन भूमि पर कब्जा जमा लिया है। इतनी वन भूमि को कब्जाने के लिए हजारों वन्य प्राणियों और पेड़ों की बलि दी गई है। सबसे बड़ी चिंता की बात यह है कि वन क्षेत्र में लगातार अतिक्रमण हो रहा है।

दोगुनी आमदनी का लक्ष्य पहुंच से दूर

प्रधानमंत्री की घोषणा के बाद ही कुछ विशेषज्ञों का अनुमान था कि किसानों की आमदनी दोगुनी करने के लिए 14.86 फीसदी सालाना कृषि विकास दर की जरूरत पड़ेगी। लेकिन बाद में यह स्पष्ट किया गया कि सरकार किसानों की आमदनी का आधार वर्ष 2015-16 मानेगी और कृषि वर्ष 2022-23 में यह लक्ष्य हासिल किया जाएगा। इसका मतलब था कि सरकार को सात साल का समय मिलेगा। नीति आयोग के सदस्य रमेश चंद ने मार्च 2017 में एक पॉलिसी पेपर जारी किया, जिसमें कहा गया कि सात साल में किसानों की आमदनी दोगुनी करने के लिए कृषि क्षेत्र की सालाना विकास दर 14.86 प्रतिशत की नहीं, बल्कि 10.4 प्रतिशत की जरूरत पड़ेगी।

इस पॉलिसी पेपर में रमेश चंद ने कहा था कि 2001 से 2014 के बीच कृषि उत्पादन में 3.1 प्रतिशत की दर से वृद्धि हुई थी। इस हिसाब से अगले सात साल (2014 से 2021 तक) में कृषि से होने वाली आय में 18.7 प्रतिशत वृद्धि रहेगी। इसलिए सरकार किसानों की दोगुनी आमदनी का लक्ष्य हासिल करने के लिए पशुपालन से होने वाली आय को भी शामिल करना चाहती है, इससे किसानों की आमदनी में 27.5 प्रतिशत की वृद्धि हो सकती है। रमेश चंद के मुताबिक, पशुपालन और डेरी की आमदनी को भी बढ़ाया जाए तो सब मिलाकर 2025 तक किसानों की आमदनी में 107.5 प्रतिशत की वृद्धि की जा सकती है। लेकिन अब तक क्या कुछ हुआ है? हकीकत क्या है?

15 सितंबर 2020 को लोकसभा में वाईएसआर कांग्रेस पार्टी के सांसद मारगनी भरत और टीआरएस पार्टी के सांसद रणजीत रेड्डी द्वारा पूछे गए एक सवाल के जवाब में कृषि एवं किसान कल्याण मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने जानकारी दी कि किसानों की आय का आंकलन राष्ट्रीय नमूना सर्वेक्षण संगठन (एनएसएसओ) के द्वारा किया जाता है। एनएसएसओ ने पिछला अनुमान कृषि वर्ष 2012-13 में तैयार किया था और नए अनुमान अभी उपलब्ध नहीं हुए हैं। हालांकि तोमर ने दावा किया कि किसानों के कल्याण के लिए चलाई जा रही विभिन्न गतिविधियां व योजनाओं का जो असर दिख रहा है, उससे संकेत मिलता है कि किसानों की आय दोगुनी करने संबंधी कार्यनीति सही दिशा में चल रही है। अपने इस जवाब में तोमर ने स्पष्ट तौर पर कहा था कि ऐसी कोई भी आय मूल्यांकन रिपोर्ट उपलब्ध नहीं है, जिससे किसानों की आमदनी दोगुनी करने के लक्ष्य पर कोरोनावायरस से पड़ने वाले असर का मूल्यांकन किया जा सके। इसका मतलब है कि सरकार आय दोगुनी करने की बात तो कर रही है, लेकिन साल दर साल इस तरह का कोई आंकलन नहीं किया जा रहा है, जिससे पता चल सके कि सरकार अपने लक्ष्य से कितनी दूर है। 3 मार्च 2020 को कृषि पर बनी स्थायी समिति की रिपोर्ट संसद के दोनों सदनों में प्रस्तुत की गई, जिसमें बताया गया कि किसानों की आमदनी दोगुनी करने के लक्ष्य को हासिल करने के लिए कई स्तर पर काम चल रहा है। सरकार ने सभी संबंधित विभागों को इस काम में जुटने के निर्देश दिए थे। इसके मद्देनजर भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद् (आईसीएआर) ने किसानों की आय दोगुना करने के लिए राज्यों के लिए अलग-अलग कार्यनीति दस्तावेज तैयार कर राज्य सरकारों को भेजा है। इस कार्यनीति को सही मायने में लागू करने के लिए आईसीएआर ने हर जिले में मॉडल के तौर पर दो गांवों के किसानों की आमदनी दोगुनी करने का बीड़ा उठाया है और हर जिले में कृषि विज्ञान केंद्र को यह जिम्मेवारी सौंपी गई कि वे दो गांव को गोद ले लें। लेकिन ऐसा नहीं हो पाया है।

मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने प्रदेश के किसानों के हित में खेती को लाभप्रद बनाने और किसानों की आय दोगुनी करने के लिए कई क्रांतिकारी कदम उठाए गए हैं। कृषि मंत्री कमल पटेल कहते हैं कि आत्मनिर्भर मप्र के निर्माण में कृषि क्षेत्र की महत्वपूर्ण भागीदारी होगी। कृषि उत्पादन को बढ़ाना, उत्पादन की लागत को कम करना, कृषि उपज के उचित दाम दिलाना और प्राकृतिक आपदा या अन्य स्थिति में उपज को हुए नुकसान में किसान को पर्याप्त क्षतिपूर्ति देना, सरकार के प्रयासों में शामिल हैं। प्रदेश के किसानों को सरकार से मिल रहे संबल से किसानों ने प्रमुख रूप से गेहूं उत्पादन में रिकार्ड कायम किया। मप्र गेहूं उपार्जन में पूरे देश में अव्वल रहा। किसानों के हित में कृषि उपज मंडी अधिनियम में संशोधन करते हुए ई-ट्रेडिंग का प्रावधान किया गया और किसानों को उपार्जन केंद्र के साथ ही मंडी के अधिकृत निजी खरीदी केंद्र और सौदा-पत्रक व्यवस्था के माध्यम से भी फसल बेचने की सुविधा प्रदान की गई।

● प्रवीण कुमार

कृषि अधोसंरचना विकास फंड में मप्र सबसे आगे

कृषि मंत्री कमल पटेल ने बताया कि कृषि अधोसंरचना विकास फंड में मप्र देश में सबसे आगे है। अधोसंरचना विकास के लिए आत्मनिर्भर कृषि मिशन का गठन किया गया है। पिछले 10 माह में कृषि विकास एवं किसान-कल्याण के लिए विभिन्न योजनाओं पर 83 हजार करोड़ रुपए से अधिक के हितलाभ दिए गए हैं। किसानों के हित में मंडी नियमों में ऐतिहासिक सुधार भी किया गया है। मंडी टैक्स 1.50 प्रतिशत से घटाकर 0.50 प्रतिशत किया गया। कृषि की लागत कम करने, उपादन बढ़ाने तथा उपज का सही दाम किसानों को दिलाने के लिए कृषि उत्पादक संगठनों (एफपीओ) को मजबूत किया जा रहा है। आगामी वर्षों में एक हजार नए कृषि उत्पादक संगठनों का गठन किया जाएगा। सरकार द्वारा किसानों के हित में महत्वपूर्ण निर्णय लेते हुए फसल नुकसानी पर न्यूनतम मुआवजा राशि 5 हजार रुपए की गई है। इस संबंध में राजस्व पुस्तक परिपत्र में संशोधन भी किया गया है। प्रदेश के किसानों को उत्तम गुणवत्ता के खाद-बीज उपलब्ध कराए जा रहे हैं। इस वर्ष किसानों को पर्याप्त खाद उपलब्ध कराए जाने के बाद यूरिया का सरप्लस भंडारण रहा। नकली खाद-बीज बेचने वालों के विरूद्ध सख्त कार्रवाई करते हुए उनके लाइसेंस निलंबित और निरस्त भी किए।

10 हजार करोड़ की जमीन माफिया मुक्त

शासन और प्रशासन का इकबाल तभी बुलंद होता है, जब अपराध और अपराधियों में कानून का खौफ दिखे। मप्र में इन दिनों माफिया की दुनिया में शासन-प्रशासन का खौफ दिखाई दे रहा है। प्रदेश में भूमाफिया, गुंडा तत्वों और सरकारी जमीन पर अतिक्रमण करने वालों पर पुलिस-प्रशासन ने शिकंजा कस दिया है। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान के निर्देश पर पिछले 11 माह में ऐसे लोगों के कब्जे से करीब 9,986 करोड़ रुपए की जमीन मुक्त कराई गई है। भोपाल, इंदौर, खरगौन, टीकमगढ़, पन्ना, देवास, रायसेन और बड़वानी जिलों में जमकर कार्यवाही की गई।

प्राकृतिक सौंदर्य और खनिज संपदा से भरपूर मप्र का जितना अवैध दोहन हुआ है उतना किसी और राज्य का नहीं हुआ है। 3,08,252 वर्ग किलोमीटर क्षेत्रफल में फैले मप्र में लाखों हैक्टेयर जमीन भू-माफिया और रसूखदारों ने सीलिंग एक्ट की आड़ में कब्जा कर रखी है। वहीं दूसरी तरफ प्रदेश की एक बड़ी आबादी आज भी भूमिहीन है। भू-माफिया ने वन भूमि, चरनोई भूमि, ग्रीन बेल्ट, मरघट, कब्रिस्तान, खेल मैदान, नदी, तालाब आदि पर कब्जा कर रखा है। शासकीय अधिकारियों की मिलीभगत से बड़े स्तर पर गोलमाल किया गया है। सरकार अब सरकारी भूमि पर अतिक्रमण करने वालों की जिलावार सूची बनवाकर उनके कब्जे से जमीन छुड़वा रही है।

प्रदेश में अपने रसूख के दम पर सरकारी जमीनों पर अवैध रूप से बड़े होटल, रेस्टोरेंट, गोदाम, घर बनाकर ठप्पे से रहने वाले भू-माफिया, ड्रग माफिया, शराब माफिया और अवैध कामों में लिप्त लोगों पर सख्त कार्यवाही की जा रही है। आपराधिक तत्वों को पनाह देने वाले इन असामाजिक तत्वों का साम्राज्य नेस्तनाबूत करने अब पुलिस और प्रशासन मिलकर सख्त कार्यवाही कर रहे हैं। ऐसे मामलों में राजनीतिक सिफारिशों को नजरअंदाज करने और पुलिस और प्रशासन को फ्री हैंड देने के अच्छे नतीजे सामने आए हैं। हालांकि बालाघाट, निवाड़ी, राजगढ़, नरसिंहपुर, विदिशा, गुना, अशोकनगर, श्योपुर, भिंड, विदिशा, अलीराजपुर, खरगौन, होशंगाबाद, ग्वालियर, आगर-मालवा, उज्जैन, छिंदवाड़ा, धार, रतलाम, शाजापुर, कटनी, मंडला, सीधी, अनूपपुर में सरकार की मंशानुसार माफिया के खिलाफ कार्यवाही नहीं हो पाई है।

मप्र में एक तरफ सरकार माफिया पर अंकुश लगाने के लिए कायदे-कानून सख्त करती है, वहीं अधिकारियों के साथ मिलकर रसूखदार माफिया अपना अवैध कारोबार बेरोकटोक बढ़ाते रहते हैं। खासकर सरकारी भूमि पर कब्जा करने का कालाकारोबार यहां बेरोकटोक चल रहा है। सरकारी आंकड़ों के अनुसार, मप्र में 231.34 लाख हैक्टेयर भूमि कृषि उपयोग की है। वहीं वन क्षेत्रफल 85.89 लाख हैक्टेयर, काश्त उपयोगी पड़त भूमि 10.02 लाख हैक्टेयर, कुल पड़त भूमि 9.81 लाख हैक्टेयर है। लेकिन हकीकत में वन भूमि, चरनोई और पड़त भूमि पर बड़े स्तर पर भू-माफिया ने कब्जा किया है। सरकारी भूमि को कब्जाने का यह खेल सुनियोजित तरीके से किया गया है। इसे कब्जाने वाले रसूखदार लोग हैं। अत: प्रशासन इनके खिलाफ कार्रवाई करने से हिचकता है। लेकिन अपनी चौथी पारी में मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने माफिया के कब्जे से सरकारी जमीनों को मुक्त कराने का अभियान शुरू कर दिया है। मंत्रालयीन सूत्रों का कहना है कि गत वर्ष आयुक्त भू-अभिलेख की पड़ताल में प्रदेश में बड़े पैमाने पर भू-माफिया का खेल उजागर हुआ था। भू-माफिया ने अधिकारियों के साथ मिलीभगत करके प्रदेशभर में 3.32 लाख हैक्टेयर सरकारी जमीन कब्जाई है। अनुमानत: भू-माफिया के कब्जे में वाली इन जमीनों की कीमत कम से कम 250 अरब रुपए होगी। अब उसी रिपोर्ट के आधार पर सरकार एक-एक माफिया से सरकारी जमीनों को मुक्त करवा रही है।

● **लोकेंद्र शर्मा**

162 के नाम पर 3.32 लाख हैक्टेयर जमीन

मंत्रालयीन सूत्रों का कहना है कि आयुक्त भू-अभिलेख की पड़ताल में कई चौकाने वाले तथ्य सामने आए हैं। बताया जा रहा है कि माफिया और अधिकारियों की मिलीभगत से प्रदेश में 162 निजी खातेदारों के नाम पर लगभग 3.32 लाख हैक्टेयर जमीन दर्ज कर दी गई है। इस सूची के आने के बाद भू-अभिलेख विभाग में हड़कंप मच गया था। काफी जद्दोजहद के बाद ये सारा खेल उजागर होने के बाद सत्यापन कार्य हुआ। जीआई सर्वे भी कराया गया तब जाकर इतने बड़े पैमाने पर भूमि घोटाले का पर्दाफाश हुआ था। अकेले सतना में ही कुल 18 खसरों का रकबा 12479 हैक्टेयर पाया गया है। इसमें से 4 निजी खातेदारों को नाम पर 2976 हैक्टेयर जमीन दर्ज है। इसी तरह से 14 शासकीय खसरों में 9503 हैक्टेयर जमीन दर्ज है। जानकारी के अनुसार, मामले का खुलासा सतना जिले में माफिया द्वारा किए गए कब्जे की जांच पड़ताल में हुआ है। इस सूची के आने के बाद भू-अभिलेख के अधिकारियों ने इसका सत्यापन कर खसरा सुधार कराया। सतना जिले में जिन चार निजी खातेदारों के खसरों में 500 हैक्टेयर से अधिक जमीन दर्ज थी उनमें उचेहरा तहसील के पथरहटा हल्के के कुशली गांव के खसरा नंबर 109/2, रामनगर तहसील के सुहौला हल्का के मुनगहा गांव के खसरा नंबर 12/2/क, रामनगर तहसील के झिन्ना आरआई सर्किल के जिगना पटवारी हल्के के हिनौता गांव के खसरा नंबर 441 और मैहर तहसील के बदेरा आरआई सर्किल के धनवाही पटवारी हल्का के धनवारी गांव के खसरा नंबर 2506/1/क शामिल थे।

वर्चस्व की लड़ाई में खूंखार हुए नक्सली

छत्तीसगढ़ के बीजापुर में 3 अप्रैल को 22 जवानों को शहीद करने के बाद नक्सली इस कदर खूंखार हो गए हैं कि अब वे मप्र सहित झारखड़, महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश और तेलंगाना में भी बड़ी घटना को अंजाम देने की तैयारी में हैं। इसका खुलासा झारखंड के कोल्हान प्रमंडल में खुफिया विभाग को मिली रिपोर्ट से हुआ है। रिपोर्ट के मुताबिक प्रदेश के बालाघाट, सीधी, सिंगरौली और मंडला जिले में नक्सलियों का जमावड़ा है। नक्सली नगरीय निकाय और पंचायत चुनाव में बड़ी वारदात करने की तैयारी करके बैठे हैं।

खुफिया विभाग का कहना है कि छत्तीसगढ़ और महाराष्ट्र के करीब 100 नक्सली पिछले साल मप्र की सीमा में घूसे थे। अब उन्होंने बालाघाट, सीधी, सिंगरौली और मंडला के साथ ही इनके आसपास के जिलों में अपना विस्तार कर दिया है। सूत्र बताते हैं कि छत्तीसगढ़ में हमले के बाद अब नक्सली संगठन मप्र सहित झारखड़, महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश और तेलंगाना में भी हमले की साजिश रच रहे हैं। छत्तीसगढ़ के सुकमा, बीजापुर, दंतेवाड़ा इलाके में सुरक्षा बलों ने कई नए कैंप खोले हैं। ऐसे में आने वाले समय में नक्सली एक्टिविटी कम होनी चाहिए, लेकिन इन जगहों से लगे हुए दंडकारण्य में बहुत बड़े इलाके हैं, जहां नक्सली अपने छिपने का नया ठिकाना आसानी से ढूंढ लेंगे। अबूझमाढ़ में तो नक्सली पहले से ही बहुत मजबूत स्थिति में हैं। 2 मार्च 2021 की एक रिपोर्ट में दावा किया गया कि नक्सली महाराष्ट्र, मप्र और छत्तीसगढ़ में काम करने के लिए अमरकंटक के जंगलों में नया बेस कैंप तैयार करने में जुटे हुए हैं। सीपीआई माओइस्ट ने अपनी 21 मेंबर्स की सेंट्रल कमेटी फिर से बना ली है, जो उनके पोलित ब्यूरो के बाद सबसे अहम है। ये सब संकेत हैं कि नक्सली खुद को दोबारा मजबूत करने की कोशिश कर रहे हैं। उनका सबसे अधिक फोकस मप्र के आठ जिलों बालाघाट, सीधी, सिंगरौली, मंडला, डिंडौरी, शहडोल, अनूपपुर और उमरिया पर है।

झारखंड के खुफिया विभाग ने अपनी रिपोर्ट में कहा है कि मप्र में नक्सली छोटे-छोटे दल में सक्रिय हैं, ताकि पुलिस की नजर में न आ सकें। नक्सली एके-47 और रॉकेट लॉन्चर जैसे घातक हथियारों से लैस हैं। झारखंड और छत्तीसगढ़ में नक्सली सुरक्षा बलों में रॉकेट लॉन्चर का इस्तेमाल कर चुके हैं। मप्र में सबसे अधिक नक्सली बालाघाट में सक्रिय हैं। विगत दिनों बालाघाट में नक्सलियों ने सड़क निर्माण कार्य में लगे दो ट्रैक्टर समेत एक ट्रक को जला दिया था और ठेकेदार व मजदूरों से मारपीट की थी। इसके अलावा विस्फोटक भी बरामद हुआ था। खुफिया विभाग का दावा है कि झारखंड, बिहार और छत्तीसगढ़ में लगातार चलाए जा रहे अभियान से नक्सलियों को जान बचाने के लिए नए ठिकानों की तलाश में इधर-उधर भागना पड़ रहा है। ऐसे में मप्र उनके लिए सुरक्षित जगह है। छत्तीसगढ़ के बीजापुर में हुई नक्सली वारदात के बाद छिपने की गरज से नक्सली बालाघाट का रुख कर सकते हैं। इसलिए जिले के सीमावर्ती थाना व चौकियों में पुलिस ने हाई अलर्ट जारी कर दिया है। साथ ही चौकसी बढ़ा दी गई है। नक्सलियों को रोकने के लिए हॉक फोर्स, सीआरपीएफ, जिला पुलिस बल को तैनात किया गया है। छत्तीसगढ़ से भागकर बालाघाट के जंगल में घुसने वाले नक्सलियों के संभावित रास्तों पर पुलिस ने एंबुश लगा दिए हैं। बालाघाट में छह नक्सली दलम सक्रिय हैं। टांडा दलम, मलाजखंड दलम, दर्रेकसा समेत विस्तार दलम-2, विस्तार दलम-3 और खटिया मोचा दलम में 300 नक्सली हैं। इनमें 15-20 महिला सदस्य भी हैं। बालाघाट के पुलिस अधीक्षक अभिषेक तिवारी कहते हैं कि छत्तीसगढ़ में हुई नक्सली वारदात के बाद से ही जिले में हाई अलर्ट घोषित कर दिया गया है। नक्सल प्रभावित क्षेत्र के थाना व चौकियों में तैनात हॉक, सीआरपीएफ, एसएएफ व जिला पुलिस बल के जवान लगातार जंगलों में सर्चिंग कर रहे हैं। दंडकारण्य (मप्र, छत्तीसगढ़, महाराष्ट्र, झारखंड का क्षेत्र) जैसे नक्सल प्रभावित क्षेत्र से अक्सर नक्सलियों द्वारा बर्बरता, हत्या और शोषण की खबरें जंगलों से निकलकर बाहर आती रहती हैं। नक्सलियों पर नकेल कसने के लिए सुरक्षाबलों के जवान भी जुटे रहते हैं।

● **धर्मेन्द्र सिंह कथूरिया**

तेजी से सिकुड़ रहा नक्सली आंदोलन

दंडकारण्य समेत देशभर में तेजी से सिकुड़ रहा नक्सली आंदोलन 9 बड़े नक्सली नेताओं की मौत से और भी कमजोर हो गया है। दंडकारण्य में साढ़े तीन दशक तक नक्सलवाद की कमान संभालने वाले रावुलू श्रीनिवास उर्फ रमन्ना की मौत के आठ महीने बाद भी नक्सली उसकी जगह नया नेता नहीं तलाश पाए हैं। ऐसे में आधा दर्जन से अधिक बड़े नेताओं की मौत से नक्सल संगठन में बिखराव की आंशका जताई जा रही है। रमन्ना दंडकारण्य स्पेशल जोनल कमेटी का सचिव तथा सेंट्रल कमेटी का सदस्य था। उसकी मौत से नक्सली आंदोलन को बड़ा झटका लगा है। इसका खुलासा नक्सली संगठनों ने शहीदी सप्ताह के दौरान पर्चा जारी कर किया था। उसमें रमन्ना के अलावा आठ और बड़े नेताओं की मौत का ब्यौरा दिया गया है। नक्सलियों ने माना है कि बीते एक साल में बीमारी, मुठभेड़ और कथित मुठभेड़ों में उनके 105 साथी मारे गए हैं। यह आंकड़ा देशभर में मारे गए नक्सलियों से संबंधित है। बिहार-झारखंड के 4, दंडकारण्य के 67, आंध्र-ओडिशा बार्डर इलाके के 14, सेंट्रल रिजर्व कमेटी नंबर दो का एक सदस्य, महाराष्ट्र-मप्र-छत्तीसगढ़ (एमएमसी) जोन के नौ तथा पश्चिमी घाट इलाके के चार नक्सली बीते एक साल में मारे गए हैं। नक्सलियों ने मौत से हुए नुकसान के क्रम में रमन्ना की मौत को सबसे ऊपर रखा है। कहा है कि अपने 36 साल के क्रांतिकारी जीवन में रमन्ना ने दंडकारण्य के क्रांतिकारी आंदोलन में महत्वपूर्ण योगदान दिया। रमन्ना की मौत सात दिसंबर को गंभीर बीमारी के चलते हुई।

बाघ प्रदेश में मौत का साया

मप्र में अवैध शिकार और दूसरी वजहों से बाघों की मौत में काफी बढ़ोतरी हुई है। हाल में मप्र के वन मंत्री विजय शाह ने विधानसभा में जानकारी दी कि प्रदेश में एक जनवरी 2018 से एक जनवरी 2021 के बीच 93 बाघों की मौत हुई, जिसमें 25 की मौत का कारण अवैध शिकार था। मतलब यह कि तीन साल में करीब 27 फीसदी बाघों का शिकार हुआ। लेकिन प्रदेश के प्रधान मुख्य वन संरक्षक (वन्यजीव) आलोक कुमार के मुताबिक, बाघों की कुल मौतों में 90 फीसदी सामान्य है। 10 फीसदी ही अवैध शिकार के कारण मरे हैं, उसके लिए आवश्यक कदम उठाए जा रहे हैं। पिछली बाघ गणना में प्रदेश में बाघों की संख्या में इजाफे और अवैध शिकार पर नियंत्रण का दावा करने वाले वन विभाग के अधिकारी यह मानने को तैयार नहीं कि बाघों की मौत चिंता का विषय है।

मप्र में बाघों पर संकट केवल अवैध शिकार की वजह से नहीं है। विकास के नाम पर खत्म हो रहे जंगल भी उनके अस्तित्व के लिए बड़ा संकट है। केन-बेतवा लिंक परियोजना के लिए पन्ना टाइगर रिजर्व का बड़ा भू-भाग डूबने वाला है। इस परियोजना में दोधन बांध बनाया जा रहा है। इससे बुंदेलखंड को सिंचाई के लिए पानी तो मिलने का दावा है, लेकिन रिजर्व का करीब 4141 हैक्टेयर जंगल डूब जाएगा जिसमें 900 हैक्टेयर का कोर क्षेत्र भी है। पहले ही जंगलों की अवैध कटाई से वन क्षेत्र तेजी से कम हो रहा है। ऐसे में इस तरह की परियोजनाएं संकट को और बढ़ा रही हैं। पन्ना टाइगर रिजर्व में हाल के कुछ वर्षों में बाघों की संख्या तेजी से बढ़ी है, ऐसे में इस परियोजना से बाघों पर विपरीत असर पड़ना तय है। पर्यावरणविदों ने परियोजना का काफी विरोध किया मगर केंद्र के दबाव में सारे विरोधों को दरकिनार कर दिया गया है। तर्क दिया जा रहा है कि परियोजना में रिजर्व का 41 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र डूब रहा है। इसका कुल क्षेत्रफल 576 वर्ग किलोमीटर है।

जानकारों को इससे भी बढ़कर हैरानी वन विभाग के रवैये पर है, जो बाघों की ज्यादातर मौत को स्वाभाविक मानकर अवैध शिकार के आंकड़ों को भी खारिज करता है। एक तथ्य यह भी है कि अवैध शिकार के अलावा बाघों की आपसी लड़ाई (टेरीटोरियल फाइट) में भी काफी मौत हुई हैं। इसे भी बाघों की बढ़ती संख्या से जोड़कर स्वाभाविक ही माना जा रहा है। राज्य में 90 फीसदी बाघों की मौत इन्हीं दो वजहों से हो रही है। 2012 से अभी तक राज्य में करीब 200 बाघों की मौत हो चुकी है। इसके उलट कर्नाटक में यह संख्या करीब 132 है, जो कुल बाघों की संख्या में मामले में मप्र के बाद दूसरे स्थान पर है। हालांकि बाघों की मौत के मामले में दूसरे स्थान पर महाराष्ट्र का नंबर आता है। जानकारों का मानना है कि मप्र में बाघों की मौत की मूल वजहों पर सरकार ध्यान नहीं दे रही है। वर्ष 2018 में राज्य में कुल 13 बाघों की मौत हुई, तो 2019 में यह आंकड़ा 28 पहुंच गया। 2020 में मरने वाले 26 बाघों में 21 के मौत संरक्षित वन क्षेत्र में ही हुई है। इससे स्पष्ट है कि मौतें लगातार बढ़ रही हैं लेकिन राज्य सरकार के कान पर जूं नहीं रेंग रही है। केंद्र का काफी पुराना सुझाव है कि बाघों की सुरक्षा के लिए विशेष बल का गठन किया जाए, जिसका सारा खर्च केंद्र वहन करेगा, लेकन मप्र में आज तक इस मामले में कुछ नहीं किया गया। आलोक कुमार इस सवाल पर कहते हैं कि बल के गठन को लेकर फिलहाल कोई फैसला नहीं किया गया है। सरकार का यह जवाब तब है जब राज्य में बाघों की मृत्यु दर कई साल से देश में सबसे अधिक बनी हुई है।

वन प्रबंधन पर फॉरेस्ट मैनेजमेंट विदाउट टियर्स नामक किताब लिखने वाले और भारतीय वन सेवा से सेवानिवृत्त अधिकारी राम गोपाल सोनी का मानना है कि मौतों की एक वजह बाघों के लिए पर्याप्त खाना-पानी न मिल पाना भी है। वे कहते हैं, 'इस ओर वन विभाग कोई काम नहीं कर रहा है और आधारहीन तर्क दे रहा है। केवल दो वजहें दूर कर दी जाएं तो बाघों की मौत को काफी कम किया जा सकता है। एक, सभी रिजर्व में बाघों के लिए खाने और पानी की पर्याप्त व्यवस्था हो। दूसरे, स्थानीय लोगों को जोड़कर सूचना तंत्र मजबूत किया जाए। यह काम पेंच में हुआ है, जिसकी वजह से यह कई साल से देश में सबसे बेहतर बना हुआ है। 2018 में भी इसे सभी टाइगर रिजर्व में पहला स्थान दिया गया है।'

● **श्याम सिंह सिकरवार**

खाना-पानी का भी संकट

पेंच को छोड़ दिया जाए तो सभी रिजर्व में खाना-पानी का संकट है। केवल नदी के कुछ किमी में ही पानी और खाना मिलता है, जिससे सभी बाघ वहीं रहना चाह रहे हैं। इस वजह से क्षेत्राधिकार के लिए आपसी लड़ाई हो रही है। रिजर्व के कोर क्षेत्र ही समृद्ध नहीं है। इसकी मूल वजह पानी का संकट है। पानी न होने की वजह से घास के मैदान नहीं हैं और घास चरने वाले जानवर भी थोड़े हैं। ये जानवर ही बाघों का खाना होते हैं। वन विभाग को चाहिए कि सभी रिजर्व में बड़ी संख्या में पानी के लिए तालाब बनाए। इसके अलावा पिछले कुछ साल में वन विभाग ने रिजर्व के कोर क्षेत्र से बड़ी संख्या में आबादी को हटाया है। इससे उनके साथ रहने वाले जानवर भी वहां से हट गए। इसके बाद बाघों के लिए खाने का और भी संकट पैदा हो गया। पहले बाघ इन गांवों से जानवरों का शिकार कर भूख मिटा लेते थे। सोनी कहते हैं कि पेंच अभयारण्य का उदाहरण वन विभाग के सामने है, उसके बाद भी वह कोई सीख नहीं लेना चाहता। आज बाघों की मौत पन्ना और बांधवगढ़ में ही ज्यादा हो रही है। पेंच में स्थिति बिल्कुल उलट है। इसकी मूल वजह वहां के कोर क्षेत्र में बड़ी संख्या में तालाब बनाए गए हैं। इससे वहां बड़ी संख्या में शाकाहारी जानवर हैं, जो बाघों का खाना बनते हैं। यह रिजर्व दूसरों की तुलना में काफी छोटा है, इसके बावजूद यहां बड़ी संख्या में जानवर हैं। उनको यहां से दूसरे रिजर्व में स्थानांतरित किया जा रहा है। पेंच के अलावा सभी रिजर्व में इनकी संख्या काफी कम है।

हीरा खदानों से निकलती बीमारी

मप्र का पन्ना जिला हीरे के लिए विख्यात है। इस हीरे की चमक में खदानों में काम करने वाले मजदूरों की कहानी कहीं खो जाती है। पन्ना में वनोपज, पत्थर और हीरा खनन के अलावा रोजगार का कोई दूसरा विकल्प मौजूद नहीं है। इस वजह से स्थानीय लोग या तो पलायन करते हैं या पत्थर के खदानों में काम कर सिलिकोसिस जैसी बीमारी झेलते हैं। पन्ना जिला मप्र के उन कुछेक जिलों में आता है जहां बच्चों और महिलाओं में कुपोषण और एनीमिया सबसे अधिक है। खदानों में काम करने वाली महिलाएं सामान्यत: एनीमिया से ग्रसित हैं। यानी खून की कमी से। पर्यावरण के सख्त नियमों की वजह से वैध खदान बंद हो रहे हैं। रोजी-रोटी के लिए कुछ मजदूरों को अवैध खदानों में वन विभाग और पुलिस की कार्रवाई के खतरों के बीच काम करना पड़ता है।

मप्र की राजधानी भोपाल से 400 किमी दूर पन्ना की ख्याति हीरा खदानों को लेकर विश्व के कोने-कोने तक है, लेकिन पन्ना जिले के चमकदार हीरा-खनन के पीछे ऐसे लाखों कहानियां छिपी हैं जो कम ही उजागर हो पाती हैं। तीन हजार वर्षों से भारत विश्व में हीरे का एकमात्र उत्पादक बना हुआ था। बाद में दक्षिण अफ्रीका और ब्राजील के खदानों की खोज हुई। देश में नेशनल मिनरल डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन (एनएमडीसी) की पन्ना में एक हीरा खदान सरकार के द्वारा संचालित है। इंडियन ब्यूरो ऑफ माइंस की इंवेंटरी रिपोर्ट कहती है कि भारत में मप्र, आंध्र प्रदेश और छत्तीसगढ़ में ही हीरे की खदानें हैं, जिसमें 28,709,136 कैरेट (90.17) प्रतिशत हीरों के साथ पन्ना के खदान सबसे समृद्ध हैं।

एनएमडीसी के मुताबिक पन्ना के खदान से 84,000 कैरेट प्रतिवर्ष की क्षमता के साथ हीरे निकल रहे हैं। अब तक 1,005,064 कैरेट हीरे निकाले जा चुके हैं। एनएमडीसी के पास 74 एकड़ में मैकेनाइज्ड खनन (मशीन से खनन) की सुविधा है, लेकिन उथली खदानों में यह संभव नहीं है। यहां हाथ से ही काम होता है। हालांकि, इस इलाके की एक त्रासदी भी है। सालों-साल इन खदानों में काम करने वाले खनन मजदूर की स्थिति अब भी नहीं बदली है। यहां मजदूर आज भी गरीबी, कुपोषण, बेरोजगारी और पलायन की चपेट में फंसे हुए हैं। खदान में काम करने वाले किशोरी यादव बताते हैं कि हाथ से खनन के लिए पहले पत्थर की शीलाओं को तोड़ा जाता है। उनके नीचे छोटे-छोटे मिट्टी से सने कंकड़ होते हैं, जिनमें हीरा मौजूद होने की संभावना होती है। पानी से इन कंकड़ों को धोया जाता है। इसके बाद एक साफ जगह पर इसे बिछाकर एक-एक कंकड़ को बारीकी से परखते हैं। कांच जैसा चमकता पत्थर मिले तो समझिए भाग्य खुल गया, हीरा खोजने की प्रक्रिया बताते हुए किशोरी की आंखे चमक उठती हैं। इस एक चमक में पन्ना जिले की तमन्ना छिपी है जहां अनगिनत लोग सालों-साल इन खदानों में गुजारते हैं। इस उम्मीद में कि अगर एक हीरा मिल जाए तो जिंदगी संवर जाए। पर मजदूरों के जीवन में ऐसा दिन लगभग नहीं के बराबर आता है।

उदाहरण के तौर पर पन्ना से 40 किमी दूर खजुराहो के गोंविद रायकवाड़ को ही लीजिए। करीब 37 साल के युवा गोविंद पहले अपने जिले में ऑटोरिक्शा चलाते थे। कोविड-19 से जुड़े लॉकडाउन में काम बंद हुआ तो कर्ज लेकर भाग्य आजमाने आ गए। हीरा पाने की चाह में। गोविंद कहते हैं कि मैं पिछले कई सप्ताह से खोद रहा हूं लेकिन अब तक कुछ हाथ नहीं लगा है। इसी बीच पानी खत्म हो गया तो अब कंकड़ धुल नहीं पाएंगे। मैं कंकड़ इकट्ठा करता हूं और बारिश के बाद इसे साफ करूंगा। हीरे की खदानों में रात में भी कुछ मजदूर रहते हैं। पॉलीथिन और आसपास के झाड़ियों से वे झोपड़ी बनाते हैं। यहां सुबह-शाम खाना बनाने का इंतजाम भी रहता है। हीरे के खुले खदान खतरों से खाली नहीं हैं। जगह-जगह पर पत्थर, गड्ढे और ऊबड़-खाबड़ जमीन। एक छोटी सी चूक से सीधे कई फीट गहरे गड्ढे में गिरकर चोटिल होने का खतरा बना रहता है। लेकिन हीरा खोजने वाले इसकी परवाह नहीं करते। खजुराहो से आए गोविंद ने यहीं एक अस्थायी घर बना लिया है। वे कहते हैं, मैंने इसी खदान में एक छोटा झोपड़ा बनाया है, जिसमें रात बिताता हूं।

● **सिद्धार्थ पांडे**

सिलिकोसिस बीमारी सबसे बड़ी समस्या

नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे-4 के आंकड़ों की ओर देखें तो पन्ना जिले में 49 प्रतिशत महिलाओं (15 से 49 वर्ष) में खून की कमी है। पांच साल से कम उम्र के करीब 68 फीसदी बच्चों में खून की कमी है। सर्वे के मुताबिक यहां के 42 फीसदी बच्चों में ठिगनापन है और 24 फीसदी बच्चों का वजन कम है। ये सभी कुपोषण के लक्षण हैं। खून की कमी ही नहीं बल्कि पत्थर के धूल से मजदूरों को सिलिकोसिस जैसी लाइलाज बीमारियां होती हैं। सिलिकोसिस के मरीजों की जांच और उपचार की सुविधा मौजूद नहीं है। सरकार के द्वारा उन्हें पेंशन भी नहीं दी जाती, जिससे वे काम न कर पाने की स्थिति में घर चला सकें। पत्थर खनन मजदूरों के लिए काम करने वाले समाजिक कार्यकर्ता युसुफ बेग इलाके की समस्या पर कहते हैं कि वर्ष 2010-11 में पत्थर खदान मजदूर संघ नें इन्विरानिक्स ट्रस्ट दिल्ली के सहयोग से पन्ना जिले के पत्थर खदान मजदूरों की जांच कराई थी जिसमें 162 मजदूरों के सिलिकोसिस बीमारी से पीड़ित होने की पुष्टि की गई थी। हालांकि, अधिकृत तौर पर बुंदेलखंड मेडिकल कॉलेज सागर और जिला चिकित्सालय पन्ना ने मात्र 39 मजदूरों को सिलिकोसिस पीड़ित माना है। इन चिन्हित मजदूरों में से अब तक 25 मरीजों की मौत हो चुकी है। मानव अधिकार आयोग के दखल के बाद सरकार ने 11 मजदूरों के परिवार को मृत्यु के बाद 3-3 लाख की सहायता राशि दी है। पन्ना के कृष्ण कल्याणपुर गांव स्थित हीरा खदान में कोई खुदाई में लगा है तो कोई अपनी झुग्गी के पास आराम कर रहा है।

ये नरसंहार ही तो है...!

तंत्र की चूक से घातक होती महामारी

किसी भी देश के शासक का पहला कर्त्तव्य होता है अपने देश की जनता को सुरक्षित रखना। लेकिन कोरोना महामारी के बीच भारत में शासन और शासक दिग्भ्रमित दिखे। इसका असर यह हुआ कि देश में कोरोना संक्रमण की दूसरी लहर आउट ऑफ कंट्रोल हो गई है। देश के श्मशानों, कब्रिस्तानों, नदी-नालों में लाशों का अंबार लगा हुआ है। मरीज ऑक्सीजन, दवा और इलाज के बिना मर रहे हैं। इलाहाबाद हाईकोर्ट ने इसे नरसंहार माना है।

● राजेंद्र आगाल

इलाहाबाद हाईकोर्ट ने ऑक्सीजन के अभाव में हो रही मौतों को जब नरसंहार कहा तो लोग थोड़ा विचलित हुए। लेकिन अगर सैद्धांतिक रूप से देखा जाए तो देश में हो रही असंख्य मौतें किसी नरसंहार से कम नहीं हैं। नरसंहार इसलिए कि जब देश में कोरोना की दूसरी लहर का संक्रमण फैलने के दौरान सरकार को इसकी रोकथाम के लिए कोशिश करनी चाहिए थी, उस समय 5 राज्यों में चुनाव और कुंभ का जलसा सजा हुआ था। एक तरफ देश में कोरोना पैर पसार रहा था। दूसरी तरफ चुनाव के नाम पर बड़े-बड़े जलसे, रैलियां हो रही थीं, वह भी कोरोना से बचने के लिए बनाए सारे नियमों को दरकिनार कर। देश के माननीय कोविड-19 के नियमों की धज्जियां उड़ा रहे थे। हैरानी की बात तो यह थी कि अपने आपको देश का चौकीदार कहने वाले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ऐतिहासिक भीड़ देखकर अह्लादित हो रहे थे। इसका परिणाम यह हुआ कि आज भारत मौतगाह बना हुआ है। यह किसी नरसंहार से कम नहीं है।

दरअसल, हमारी केंद्र और राज्यों की सरकार ने कोरोना की पहली लहर से कोई सबक लिया ही नहीं। देश में कोरोना की पहली लहर भी सरकार की लापरवाही का नतीजा थी। जब पूरे विश्व में कोरोना पैर पसार रहा था, उस समय तत्कालीन अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्प को खुश करने के लिए गुजरात में नमस्ते ट्रम्प कार्यक्रम का आयोजन किया गया। ट्रम्प की लापरवाही का नतीजा पूरा अमेरिका भुगत चुका है। लेकिन कोरोना की दूसरी लहर अमेरिका में कंट्रोल में है। इसकी वजह यह है कि अमेरिका के वर्तमान राष्ट्रपति जो बिडेन खुद कोरोना के नियमों का पालन करते हैं। जहां ट्रम्प कहते थे कि मैं मास्क नहीं पहनूंगा, वहीं बिडेन हमेशा मास्क पहने नजर आते हैं। इसका असर अमेरिका में दिखा है। वहां कोविड-19 गाइडलाइन का पालन हर कोई कर रहा है। जिससे वहां कोरोना नियंत्रण में है।

लालची राजनीति का असर

अगर यह कहा जाए कि भारत में कोरोना की दूसरी लहर का कोहराम लालची राजनीति का परिणाम है, तो इसमें अतिश्योक्ति नहीं होगी, क्योंकि देश की विभिन्न अदालतों ने कोरोना बढ़ने की वजह सरकार और चुनाव आयोग को माना है। मद्रास हाईकोर्ट ने तो चुनाव आयोग को हत्यारा मानते हुए उसके खिलाफ केस दर्ज करने तक की बात कह डाली थी। भारत में जारी कोरोना का नरसंहार एक अहंकारी, आत्मकेंद्रित और लालची राजनीतिक दल व सत्ता में मौजूद उसके नेता की वजह से ज्यादा तेज हुआ है। जिस तरीके से श्मशान घाट की तरफ जाती एंबुलेंसों में ठसाठस शव भरे होते हैं, वह गैस चैंबरों की याद दिलाते हैं। ऑक्सीजन के लिए तड़पते मरीज, अस्पतालों में बिस्तर ना मिलने के चलते ऑटोरिक्शा और निजी वाहनों के भीतर सड़कों पर दम तोड़ रहे हैं।

जब 2020 में फरवरी के अंत में मोदी, अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्प का स्वागत करने में लगे हुए थे, उससे पहले 30 जनवरी को विश्व स्वास्थ्य संगठन कोविड को अंतरराष्ट्रीय चिंता वाला वैश्विक आपात घोषित कर चुका था। 11 मार्च को विश्व स्वास्थ्य संगठन ने कोविड को महामारी घोषित कर दिया, जिससे तब तक पूरी दुनिया में 1,21,000 लोग संक्रमित हो चुके थे, वहीं 4,300 लोग मारे जा चुके थे। केंद्र को तभी डब्ल्यूएचओ की टेस्ट-ट्रेस-आइसोलेट का सूत्र अपना लेना था और कोविड के लिए विशेष अस्पताल और वार्ड बनाने शुरू कर देने चाहिए थे, जिनमें समुचित मात्रा में ऑक्सीजन आपूर्ति और पर्याप्त बिस्तर उपलब्ध होते। साथ ही अंतरराष्ट्रीय उड़ानों पर प्रतिबंध लगाकर, टीवी और रेडियो पर वायरस की गंभीरता के साथ-साथ मास्क लगाने और जरूरी सामाजिक दूरी बनाने के बारे में जागरूकता अभियान चलाना था।

सांसों की कालाबाजारी

कालाबाजारियों ने रातोरात पैसा बनाने का मौका देखकर सिलेंडरों की जमाखोरी शुरू कर दी और सिलेंडर की कीमत 64,000 रुपए तक मांगने लगे। दक्षिण-पश्चिम दिल्ली के दशरथपुरी में एक कालाबाजारी करने वाले के घर से 32 ऑक्सीजन सिलेंडर जप्त किए गए। उसने उन सिलेंडरों की गैस को छोटे सिलेंडरों में डाल दिया था और उन्हें 12,500 रुपए की दर से बेच रहा था। देशभर में कुछ जगहों पर ऑक्सीजन की आपूर्ति पूरी तरह से टूट चुकी थी। रिसाव और कम दाब के चलते बहुत से मरीजों की मौत हो गई थी। मरीजों के रिश्तेदार जब सोशल मीडिया पर सहायता की मांग करने लगे तो सिविल सोसायटी के लोग और स्वयंसेवी लोग सिलेंडरों और आईसीयू की व्यवस्था करने में लग गए। तनुजा विद्यार्थी के रिश्तेदारों ने देखा कि अस्पतालों में बिस्तर पाना बहुत कठिन काम हो गया है और यह तो उनकी परेशानी की बस एक शुरुआत है। यह तो नहीं बताया जा सकता है कि ऑक्सीजन के अभाव में कितने लोगों की जान जा चुकी है लेकिन समय पर अगर ऑक्सीजन मिल गई होती तो बहुत से लोगों की जान बचाई जा सकती थी। धीमी गति से काम करने वाली सरकारी नौकरशाही नींद से तब जागी जब संकट उसके मुंह के सामने आकर खड़ा हो गया। उसे एहसास हुआ कि देश के पूर्वी हिस्सों के औद्योगिक केंद्रों से अतिरिक्त आपूर्ति पहुंचने में अभी कई दिन लग जाएंगे। 27 अप्रैल को सुप्रीम कोर्ट में एक हलफनामे में केंद्र सरकार ने 30 अप्रैल तक कोविड से प्रभावित 6 राज्यों में आपूर्ति में कमी आने की आशंका बताई। उप्र, जहां मांग और आपूर्ति के बीच 400 टन का अंतर है, शायद सबसे ज्यादा प्रभावित था। ऑक्सीजन पहुंचाने वाले ट्रकों की आवाजाही की रफ्तार तेज करने के लिए हिंडन स्थित भारतीय वायुसेना के एयरलिफ्ट स्क्वाड्रन सी-17 ग्लोबमास्टर्स ने खाली ऑक्सीजन ट्रकों को पूर्वी भारत की ऑक्सीजन फैक्टरियों तक पहुंचाया।

किसी ने भी मोदी सरकार से यह सवाल पूछने की हिम्मत नहीं दिखाई कि 3 फरवरी को न्यूजीलैंड की तरह, चीन से आवागमन पर रोक लगाने जैसी कार्रवाई हमारे यहां क्यों नहीं की गई? जबकि उस वक्त तक न्यूजीलैंड में एक भी कोरोना का मामला सामने नहीं आया था। आखिर क्यों मोदी सरकार वियतनाम मॉडल को अपनाने में नाकामयाब रही, जिसकी अंतरराष्ट्रीय स्तर पर प्रशंसा हुई थी? लोवी इंस्टीट्यूट ने जनवरी में कोरोना से निपटने के लिए वैश्विक स्तर पर वियतनाम को दूसरे पायदान पर रखा था, जब वियतनाम डब्ल्यूएचओ की टेस्ट-ट्रेस-आइसोलेट निर्देशों का पालन कर, फरवरी में अपनी सीमाएं बंद कर सकता है, तो मोदी सरकार ने वैसा क्यों नहीं किया? साफ है कि यहां सरकार का घमंड बीच में आ गया।

इसके बजाय जब मोदी ने बहुत देर से 22 मार्च को किसी दिव्य पुरुष की तरह आकर, राष्ट्रीय टीवी पर जनता कर्फ्यू की घोषणा की, तब भारत की ज्यादातर आबादी मंत्रमुग्धता में खोई हुई लग रही थी। मोदी ने जनता से चिकित्सा बिरादरी का उत्साह बढ़ाने के लिए थाली बजाने की मांग की। यह पूरा कार्यक्रम बड़ा भद्दा नजर आया, जिसमें कई भारतीयों ने पागलपन के स्तर पर जाकर प्रदर्शन किया। बता दें जनता कर्फ्यू के ऐलान तक देश में कोरोना के मामलों की संख्या 350 पार कर चुकी थी। उसके बाद भी कई तरह के आयोजन कर लोगों को यह बताने की कोशिश की गई कि सबकुछ कंट्रोल में है। यानी सरकार जनता को विश्वास दिलाने में लगी रही कि भारत में कोरोना सरकार की मुट्ठी में है। फिर कोरोना की लहर कमजोर पड़ते ही जिस तरह पूरे देश को बिना तैयारी के खोल दिया गया, उसका परिणाम यह हुआ कि भारत में कोरोना की दूसरी लहर जानलेवा स्तर पर फैल गई है।

गांवों में मचेगा हाहाकार!

भारत में कोरोना की दूसरी लहर तबाही मचा रही है। वहीं तीसरी लहर की चेतावनी भी आ गई है। ऐसे में केंद्र सहित राज्य सरकारों के हाथ-पांव फुलने लगे हैं। इसकी वजह यह है कि दूसरी लहर में कोरोना ने शहरों से अधिक गांवों में कोहराम मचाया है। अकेले अप्रैल माह में कोरोना के कारण देशभर में हुई 46,000 मौतों में से आधी से अधिक गांवों में हुई है। अगर तीसरी लहर आती है तो गांवों में मौत का हाहाकार मच जाएगा। क्योंकि गांवों में चिकित्सा व्यवस्था न के बराबर है। जबकि शहरों से अधिक आबादी गांवों में रहती है। विश्व स्वास्थ्य संगठन के मुताबिक, भारत के लिए अप्रैल का महीना बहुत क्रूर साबित हुआ। देश ने अप्रत्याशित रूप से 46,000 मौतों के साथ कोरोनावायरस बीमारी (कोविड-19) के 66 लाख से ज्यादा नए मामले दर्ज किए। महीने के आखिरी दिन, भारत एक दिन में 4,00,000 से ज्यादा नए मामले दर्ज करने वाला एकमात्र देश बन गया, जो बताता है कि यह उफान बहुत जल्द नहीं थमने वाला है। इस महीने ने स्पष्ट संकेत दे दिया कि वायरस ग्रामीण जिलों में तेजी से फैल रहा है और पहली लहर के विपरीत यह इस वक्त बहुत ज्यादा लोगों की मौत का कारण बन रहा है। 24 अप्रैल को, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने स्वीकार किया कि कोविड-19 की चुनौती इस साल बड़ी है और गांवों को प्रभावित होने से बचाने के लिए प्रयास करने की जरूरत है। उन्होंने कहा, मुझे विश्वास है कि अगर कोरोनावायरस के खिलाफ इस लड़ाई में कोई सबसे पहले जीत हासिल करने जा रहा है, तो वह भारत के गांव और इन गांवों की अगुवाई करने वाले हैं। गांवों के लोग देश और दुनिया को रास्ता दिखाएंगे। लेकिन आंकड़े उनके इस आशावाद को झुठलाते हैं। अप्रैल में कम से कम 10 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के ग्रामीण जिलों में कोरोना संक्रमण और मौतों के अधिक मामले दर्ज किए गए। इस सूची में अन्य राज्यों के अलावा मप्र, छग, उप्र, बिहार और राजस्थान जैसे सबसे ज्यादा जोखिम वाले राज्य शामिल हैं। तेलंगाना और असम में भी ग्रामीण दबाव बहुत ज्यादा है। तीन अन्य राज्यों महाराष्ट्र, हरियाणा और पंजाब ने शहरी जिलों में ज्यादा मामले देखें हैं, लेकिन ग्रामीण जिलों में मौतों की संख्या ज्यादा है। महाराष्ट्र में, ग्रामीण जिलों में संक्रमण के लगभग 42 प्रतिशत और मौतों के लगभग 60 प्रतिशत मामले सामने आए हैं। उत्तराखंड और जम्मू-कश्मीर में, कहानी ठीक विपरीत है। यहां ग्रामीण जिलों में संक्रमण के मामले ज्यादा थे, जबकि शहरी जिलों में मौतों के मामले अधिक हैं।

फिलहाल सांसों को चाहिए आक्सीजन

मप्र में कोरोना की दूसरी लहर विकराल रूप धारण कर चुकी है। संक्रमित मरीजों की संख्या में प्रतिदिन असामान्य रूप से बढ़ोतरी हो रही है। कोरोना के नए म्युटेंट ने ऐसा रूप धारण किया है कि अंदाजा लगाना मुश्किल है कि कौन कितने खतरे में है। जब तक लोग समझें तब तक वह फेफड़े को काफी नुकसान पहुंचा चुका होता है। गंभीर मरीजों की तादाद बढ़ने से समय से अस्पतालों में बेड मिलना मुश्किल हो गया है। जिन्हें बेड मिल भी रहा है उनकी सांसों के लिए समय से ऑक्सीजन नहीं मिल पा रही है। शायद ही पहले कभी ऐसा हुआ हो कि मरीज को अस्पताल में छोड़कर स्वजन ऑक्सीजन की तलाश में भटक रहे हों। सांस चाहिए तो ऑक्सीजन का इंतजाम करना ही पड़ेगा। इसके लिए चाहे जो कीमत अदा करनी पड़े। यद्यपि सरकार ने ऑक्सीजन की उपलब्धता सुनिश्चित कराने के लिए कोई कोर-कसर नहीं छोड़ी है, लेकिन जिन राज्यों से इसकी आपूर्ति होनी है वहां भी कम मारामारी नहीं है। जितनी आपूर्ति मिलती है अगले दिन उससे अधिक की मांग बढ़ जाती है। मप्र के अंदर ऑक्सीजन बनाने के रिसोर्स लगभग सीमित हैं। वर्षों से इस तरफ किसी का ध्यान ही नहीं था। न इतनी मांग कभी हुई और न सरकारों ने इस पर ध्यान दिया। पिछले वर्ष कोरोनाकाल में जब ऑक्सीजन की किल्लत हुई थी तब सरकार ने जैसे-तैसे दूसरे राज्यों से मंगाकर जरूरत पूरी कर दी थी। तब तय किया गया था कि दूसरे राज्यों पर निर्भरता कम करने के लिए ऑक्सीजन के प्लांट लगाने पर जोर दिया जाएगा। कई कंपनियों को इसके लिए रजामंदी दी गई, लेकिन बीच में कोरोना के तेवर ढीले पड़ते ही मामला ठंडे बस्ते में चला गया।

स्वास्थ्य व्यवस्था धराशायी

हमारा पूरा तंत्र अंदर से खोखला है और अगर समय रहते इसे नहीं सुधारा गया तो कभी कोई महामारी या कभी कोई प्राकृतिक आपदा, हमारी तबाही की कहानी लिखती रहेगी। देश में कभी योजना आयोग था, अब नीति आयोग बन गया, नाम बदला लेकिन इन इमारतों में बैठकर देश की तरक्की के लिए बौद्धिक उछलकूद करने वालों में ज्यादातर लोग ऐसे हैं जिन्हें देश की बुनियादी समस्याओं की समझ नहीं है। ये लोग आंकड़ों का पावर पाइंट प्रेजेंटेशन बनाने में माहिर हैं, लेकिन जमीनी हकीकत से कोसों दूर हैं और ऐसे लोगों की तथाकथित दूरदर्शिता का दुष्परिणाम देश भुगत रहा है।

इसमें कोई दो मत नहीं कि 2014 के बाद देश की राजनीति में आए एक बड़े परिवर्तन के बाद आम जनमानस ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में सकारात्मक बदलाव को महसूस किया। नए भारत के निर्माण को लेकर नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में केंद्र सरकार के उठाए गए कदमों पर लोगों ने भरोसा जताया। बिना घोटाले की पांच साल की मोदी सरकार के कार्यकाल के लेखा-जोखा ने लोगों को यह तसल्ली दिलाई कि एक मजबूत इरादे के साथ देश में सकारात्मक बदलाव संभव है। जनता के इसी भरोसे की वजह से 2019 में देश का जनमानस मोदी सरकार के साथ खड़ा दिखाई दिया। वर्ष 2014 के बाद एक बड़े राजनीतिक बदलाव के बीच नए भारत के निर्माण की शुरूआत का देश साक्षी बना, कहीं गांव और शहरों को जोड़ने वाली देश की सड़कों के विस्तार पर विकास की नई इबारत लिखना शुरू हुई तो कहीं गांवों को बिजली और इंटरनेट से जोड़े जाने पर तेजी से काम होता दिखाई दिया।

प्रधानमंत्री आवास के माध्यम से गरीब के सिर पर छत मिलने का सिलसिला शुरू हुआ तो कहीं गरीब की रसोई में गैस सिलेंडर पहुंचाने का लक्ष्य हासिल किया गया। खुले में शौच से देश को मुक्ति दिलाने के लिए हर घर में शौचालय तैयार हुए तो देश में स्वच्छता को लेकर एक आंदोलन खड़ा हो गया जिसने देश के गांव और

शहरों में स्वच्छता को लेकर एक स्वस्थ प्रतिस्पर्धा शुरू कर दी। प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि के तहत किसानों के खाते में हर साल 6 हजार रुपए की राशि के अलावा सरकार ने खेती किसानी के क्षेत्र में कई बड़े सकारात्मक कदम भी उठाए। अब केंद्र सरकार ने 'हर घर में नल' का लक्ष्य अपने हाथ में लिया है और इस दिशा में तेजी से काम होता दिखाई दे रहा है। इतना ही नहीं, जम्मू-कश्मीर में अनुच्छेद-370 को हटाए जाने जैसा ऐतिहासिक निर्णय हो, कश्मीर में सकारात्मक बदलाव की मौजूदा पहल हो, राष्ट्रीय सुरक्षा को लेकर उठाए गए कदम हों या फिर आतंकवाद पर कसी नकेल, ऐसे तमाम कदमों ने हर भारतीय के मन में सशक्त राष्ट्र की कल्पना को साकार किया है।

आपदा में अवसर

अब सवाल यह उठता है कि गरीबी रेखा के नीचे रहने वाले लोगों के मन में जब उम्मीद की नई किरण जगना शुरू हुई है और हर भारतीय के मन में अब सशक्त राष्ट्र की कल्पना साकार होते दिख रही है तो फिर एक महामारी के बाद केंद्र से लेकर राज्यों तक फैला हमारा समूचा तंत्र स्वयं क्यों बीमार दिखाई देने लगा है? आखिर देश के हर राज्य में हमारी समूची स्वास्थ्य व्यवस्था क्यों धराशायी हो गई? चारों तरफ चीख-पुकार मची है, सरकारें मौत के आंकड़ों पर पर्दा डाल रही हैं। एक साल का वक्त मिलने के बाद भी केंद्र और राज्य मिलकर इस बीमारी से निपटने के लिए प्रभावी कदम क्यों नहीं उठा सके?

मार्च 2020 में कोरोना की दस्तक के बाद लंबे समय के लॉकडाउन ने अर्थव्यवस्था को भले ही नुकसान पहुंचाया, लेकिन उस वक्त इस बीमारी से निपटने को लेकर हम तैयार नहीं थे। लॉकडाउन ने न केवल केंद्र और राज्य सरकार को इस तैयारी से निपटने के लिए एक अवसर दिया, बल्कि महामारी के संक्रमण को रोकने में भी मदद मिली। केंद्र और राज्यों ने अपने-अपने स्तर पर कोरोना से निपटने के लिए कुछ कदम भी उठाए। अगर केंद्र की नरेंद्र मोदी सरकार की बात करें तो जहां इस तरह के वायरस की जांच के लिए पहले सिर्फ एक लैब थी, जो अब बढ़कर 2,400 से ज्यादा हो गई हैं। जीवन रक्षक दवाओं के उत्पादन से लेकर वेंटीलेटर की व्यवस्था को लेकर केंद्र सरकार ने पहल की। देश में कई जगह आइसोलेशन सेंटर बनाए गए। एन-95 मास्क और पीपीई किट तैयार किए जाने लगे। केंद्र सरकार ने इमरजेंसी कोविड रिस्पांस के लिए 15 हजार करोड़ रुपए के साथ ही 2021-22 के बजट में वैक्सीनेशन के लिए 35 हजार करोड़ रुपए भी दिए। सीरम इंस्टीट्यूट और भारत बायोटक के लिए फंड आवंटित किया। इसके साथ ही 2,084 अस्पतालों को कोविड के इलाज के लिए तैयार किया गया और कोविड मरीजों के लिए 4,68,974 आइसोलेशन बेड तैयार किए गए।

केंद्र और राज्य ने कोरोना को लेकर अगर कई कदम उठाए तो फिर चूक कहां हुई? दरअसल कोरोना के मुश्किल हालात में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 'आपदा में अवसर' का उल्लेख कर लोगों को सकारात्मक रहकर कुछ बेहतर करने का संदेश दिया था, लेकिन राज्य सरकारों से जुड़े कई विभाग, दवा उद्योग से जुड़ी कई कंपनियां, ड्रग माफियाओं और निजी अस्पतालों समेत कई लोगों ने 'आपदा में अवसर' के मायने कुछ और ही निकाल लिए। कई राज्यों ने निजी अस्पतालों को कोविड इलाज का सेंटर बना दिया, राज्य सरकारों ने दरियादिली दिखाते हुए सभी लोगों की मुफ्त कोरोना जांच और इलाज का ऐलान कर दिया। बहुत सारे प्रदेशों में निजी अस्पतालों के साथ हुई इस साठगांठ से आम जनता भी भली भांति परिचित है। पिछले साल कोरोना की जांच और उसके इलाज के नाम पर राज्य सरकारों ने निजी अस्पताल को कितना भुगतान किया है, यह भी जांच का विषय है।

जब कोरोना वायरस को लेकर अमेरिका, इटली और फ्रांस जैसे कई उदाहरण हमारे सामने थे तो पिछले एक साल में केंद्र और राज्य सरकारों ने ऑक्सीजन को लेकर तत्काल कदम क्यों नहीं उठाए? आंकड़े बताते हैं कि योग, आयुर्वेद, होम्योपैथी और प्राकृतिक चिकित्सा की मदद से देश में कई लोगों ने कोरोना पर जीत हासिल की है, लेकिन ड्रग माफियाओं ने सुनियोजित तरीके से इसको लेकर भ्रांतियां फैलाने का काम भी किया। चिंता इस बात को लेकर भी है कि केंद्र और राज्य सरकारों ने

भय को भुनातीं दवा कंपनियां

कोरोनावायरस के कहर के बीच तमाम दवा कंपनियों की कमाई बढ़ गई है। यह भी तब जब आज तक सही मायने में कोरोना की कोई दवा बाजार में नहीं है। कोरोना के बेहतर निदान यानी जांच और इसका संक्रमण फैलने से रोकने वाले, इम्युनिटी बढ़ाने वाले अवयवों का बाजार इस दवा बिजनेस के मुनाफे को बढ़ा रहा है। अस्पतालों की फार्मेसी, सामान्य केमिस्ट और ऑनलाइन दवा विक्रेताओं के अलावा सरकारी खरीद सब मिलकर इस आपदा में चांदी काट रहे हैं। मुनाफे का महान मौका ताड़कर करीब दो दर्जन दिग्गज दवा कंपनियां इस मुनाफे की मारामारी में कूद पड़ी हैं। फलतः यूरोप, अमेरिका और चीन से अगले दो महीने भीतर कोरोना की 35 नई दवाओं की आमद के आसार हैं। एक दवा कंपनी का दावा है कि उसकी दवा महज 24 घंटे में कोरोना से निजात दिला देगी। दवाओं की यह बाढ़ कोरोना को बहा पाए या नहीं पर दवा कंपनियां लाभ से आप्लावित हो जाएंगी, यह तो तय है। इस मामले में भारतीय कंपनियां भी पीछे नहीं रहेंगी। रूसी स्पुतनिक के बाद अब देश में जल्द ही तीन और वैक्सीन बिकने लगेगी। कुल 6 वैक्सीन ले सकेंगे लोग। संभव है जायडस कैडिला की बनाई दवा पेगीलेटेड इंटरफेरॉन अल्फा-2बी जल्द ही कोरोना की इटोलीजुमैब, रिटोनाविर और लोपिनाविर, डॉक्सीसाइक्लिन के साथ आइवरमेक्टिन का कॉम्बीनेशन, हाइड्रॉक्सीक्लोरोक्वीन और फेवीपिरविर तथा रेमडेसिविर जैसी उन दवाओं में शामिल हो जाए जो देश में कोरोना के इलाज में इस्तेमाल हो रही हैं। देश में मिलने वाली ग्लेनमार्क फार्मा कंपनी की दवा फैबिफ्लू भी ऐसी ही दवा है, जो कभी फ्लू के इलाज में काम आती थी, अब कोरोना का इलाज कर रही है।

आयुर्वेद को एक मजबूत विकल्प के तौर पर बढ़ावा क्यों नहीं दिया?

भारत के मौजूदा हालात को देखते हुए केंद्र सरकार को यह समझना होगा कि चिकित्सा व्यवस्था, सार्वजनिक परिवहन और शिक्षा जैसे कई अहम क्षेत्रों में सरकारी क्षेत्र से जुड़ी संस्थाएं समाप्त नहीं हो, बल्कि इनकी गुणवत्ता में व्यापक सुधार किया जाए, ताकि लोग ब्रांड बनकर मुनाफाखोरी में जुटे किसी अस्पताल में जाने की बजाय सरकारी अस्पतालों को प्राथमिकता दें। इन सरकारी अस्पतालों में इलाज के नाम पर अव्यवस्था न हो, लेकिन यहां काम करने वाले चिकित्सकों को अधिक से अधिक वेतन मिले और उनका सम्मान हो। इसके साथ ही, यह भी सुनिश्चित करना होगा कि कोई भी मंत्री, सांसद या विधायक इनका तबादला नहीं कर सके या करवा सके। सरकारी तंत्र और बेपरवाह जनप्रतिनिधि कोरोना के आरंभिक दौर में लॉकडाउन को लेकर भले ही कुछ लोगों ने नाराजगी जताई थी, लेकिन इस वायरस के संक्रमण को रोकने में यह उस वक्त कारगर उपाय साबित हुआ था, जब हमारे पास इस बीमारी से निपटने के लिए कोई तैयारी नहीं थी। केंद्र और राज्यों ने इस बीमारी को हराने के लिए अपने स्तर पर प्रयास किए, लेकिन कोरोना फिर लौटेगा, सुनामी बनकर आएगा, ऐसी तमाम चेतावनी की केंद्र और राज्य सरकारों ने पूरी तरह अनदेखी की।

भारत में मृत्यु दर कम

इन दिनों देसी-विदेशी मीडिया देश के कमजोर स्वास्थ्य ढांचे की खबर लेने के साथ सरकार को कठघरे में खड़ा कर रहा है। अंतरराष्ट्रीय मीडिया का एक वर्ग सरकार पर कुछ ज्यादा ही हमलावर है। वह इसकी अनदेखी कर रहा है कि 130 करोड़ की आबादी वाले भारत में मृत्यु दर यूरोप और अमेरिका से कहीं कम है। जिन कारणों से विकसित देशों में कोरोना मरीजों की मौत हुई, उन्हीं कारणों से भारत में भी हो रही है, लेकिन विदेशी मीडिया भारत के मामले में अलग मापदंड अपनाए हुए है। जब अमेरिका और यूरोप में प्रतिदिन हजारों की संख्या में कोरोना मरीज मर रहे थे, तब विदेशी मीडिया अपने अस्पतालों की बदहाल स्थिति और सरकारी तंत्र की नाकामी पर सवाल उठाने से बच रहा था। उसके दोहरे रवैये से यह सच छिपने वाला नहीं कि एक समय अमेरिका और यूरोप में भी स्वास्थ्य ढांचा नाकाफी साबित हो रहा था और इस कारण वहां भी अव्यवस्था थी।

विकसित देशों और भारत में एक फर्क यह भी है कि यहां मरीजों के तीमारदार आईसीयू तक के वीडियो बनाने में सक्षम हो जाते हैं। इसी कारण भारत में अस्पतालों और कोरोना मरीजों की बदहाली की जैसी करुण कहानियां चारों ओर नजर आ रही हैं, वैसी विदेश में नहीं दिखतीं। विकसित देशों में तीमारदार अस्पतालों के चक्कर नहीं काटते, न मरीज की मौत के बाद सड़क पर हंगामा करते हैं और न ही इंटरनेट मीडिया पर भड़ास निकालते हैं। भारत में मरीज के मरने पर डॉक्टरों को पीटने और अस्पतालों में तोड़फोड़ की घटनाएं आम हैं। कई बार इन घटनाओं के फोटो और वीडियो मीडिया से लेकर अदालत तक में चर्चा का विषय बन जाते हैं। इससे भी लोगों का चिकित्सा जगत पर अविश्वास और बढ़ जाता है।

आंकलन नहीं हो पाया

यह स्वीकार किया जाना चाहिए कि भारत में कोई भी यह अनुमान नहीं लगा सका कि कोरोना की दूसरी लहर इतनी व्यापक होगी। इस दूसरी लहर से निपटने के लिए कोई खास तैयारी नहीं की गई। अगर भारत को कोविड महामारी से बचना है तो टीकाकरण अभियान और तेज करना होगा। दुर्भाग्य से टीकाकरण पर भी सस्ती राजनीति हो रही है। बहुत दिन नहीं हुए, जब कांग्रेस शासित राज्य और खासकर पंजाब एवं छत्तीसगढ़ कोवैक्सीन लेने से इंकार कर रहे थे। कुछ और राज्य टीकाकरण के प्रति उत्साह नहीं दिखा रहे थे या फिर टीकों के खराब होने की परवाह नहीं कर रहे थे। कम से कम अब तो उन्हें चेत जाना चाहिए, क्योंकि यह महामारी लंबे समय तक रह सकती है। सरकारों को यह सुनिश्चित करना होगा कि अगले दो-तीन महीने में कम से कम देश की आधी आबादी का टीकाकरण हो जाए। ऐसा तभी हो पाएगा, जब टीकों की उपलब्धता बढ़ाकर सचमुच युद्धस्तर पर टीकाकरण किया जाएगा।

तीसरी लहर दूसरी से भी घातक

चूंकि इसकी पूरी आशंका है कि भारत में कोरोना संक्रमण की तीसरी लहर दूसरी से भी घातक हो सकती है, इसलिए यह जरूरी है कि समाज डॉक्टरों और चिकित्सा तंत्र पर विश्वास बनाए रखें। आखिरकार वे ही हमें मुसीबत से निकालेंगे और वे ही तीसरी लहर का मुकाबला करेंगे। संकट के इस दौर में ऐसा कुछ नहीं किया जाना चाहिए जिससे डॉक्टरों और स्वास्थ्य कर्मियों का मनोबल प्रभावित हो। निसंदेह यह भी जरूरी है कि अस्पताल बेड, ऑक्सीजन प्लांट, दवाओं की उपलब्धता बढ़ाने के साथ स्वास्थ्य कर्मियों की संख्या भी बढ़ाई जाए। यदि ऐसा नहीं किया गया तो हालात हाथ से निकल सकते हैं।

कैसे मजबूत हो बुनियाद

अनियमितता, भ्रष्टाचार और लापरवाही भरे रवैये ने हमारे सरकारी तंत्र या व्यवस्था को कमजोर किया है। कोरोना महामारी के वक्त सार्वजनिक स्थल पर मास्क लगाना भले ही जरूरी हो, लेकिन मौजूदा हालात में भी देश के नेता और यहां तक की जनता इसकी अनदेखी करती दिखाई दे जाएगी। लोकतंत्र का मतलब लापरवाही और नियमों का उल्लंघन करना नहीं है, लेकिन भारत में यातायात नियमों को तोड़ने वाले अक्सर ट्रैफिक पुलिस से उलझते नजर आते हैं। भारत के प्रशासनिक तंत्र में सुधार की बड़ी पहल की जरूरत है। मौजूदा प्रशासनिक व्यवस्था की बात करें तो यहां पर एक कलेक्टर कई बार अपने महत्वपूर्ण कार्यों को छोड़कर गैर जरूरी शिष्टाचार निभाने के लिए कई घंटों तक किसी सांसद या विधायक के पीछे हाथ बांधे खड़े रहता है। मंत्रियों के वाहन से लालबत्ती हटाना एक बड़ा प्रतीकात्मक कदम था, लेकिन अभी भी केंद्र और राज्यों में कई मंत्री ऐसे हैं जिनके दिमाग में लगी लालबत्ती को हटाना जरूरी है। जनसरोकार से जुड़ी हर संस्था और विभाग को उत्तरदायी बनाकर देश की बुनियाद को मजबूत करने की जरूरत है और मजबूत बुनियाद पर ही हम सशक्त नए भारत का निर्माण कर सकते हैं।

संकट में देर से जागने का औचित्य

सुना है पश्चिम बंगाल में चुनाव-प्रचार के बाकी दिनों में प्रधानमंत्री बड़ी चुनावी सभाएं नहीं करेंगे। वह कहावत है न, देर आए, दुरुस्त आए! पर क्या बहुत देर नहीं हो गई प्रधानमंत्री को यह जरूरी निर्णय लेने में? कोरोना की स्थिति भयावह है। यह दूसरी लहर कुछ ज्यादा ही खतरनाक सिद्ध हो रही है। लोगों के कोरोनाग्रस्त होने, मरीज के लिए अस्पतालों के दरवाजे बंद होने, जरूरी दवाओं और ऑक्सीजन की कमी होने, श्मशान में लगातार जलती चिताओं की खबरें अब डराने लगी हैं। उम्मीद ही की जा सकती है कि जल्दी ही स्थिति सुधरेगी, पर इस दौरान हमारे हुक्मरानों का व्यवहार जिस तरह का रहा है, उसे देखते हुए तो स्थिति के जल्दी सुधरने की उम्मीद भी खुशफहमी ही लगती है।

उस दिन हरिद्वार में लगे कुंभ के मेले के शेष आयोजन को प्रतीकात्मक बनाने का आग्रह प्रधानमंत्री ने साधु-संतों से किया था। यह आग्रह भी बहुत पहले होना चाहिए था पर सवेरे संत-समाज से यह आग्रह करने के तत्काल बाद शाम को पश्चिम बंगाल में जाकर विशाल चुनावी सभाएं करना आखिर क्या दर्शाता है? हरिद्वार में स्नानार्थियों की भीड़ पर चिंता जताने वाले चुनावी-सभा में उमड़ी भीड़ को देखकर आनंदित हो रहे थे! 'जहां तक नजर जाती है वहां तक लोगों की भीड़' देखकर पुलकित होने वालों को इस बात की तनिक भी चिंता नहीं थी कि उस भीड़ में आधे से अधिक लोगों ने मास्क नहीं पहन रखे थे। जिस 'दो गज दूरी' की बात हमारे प्रधानमंत्री पिछले एक साल से लगातार करते आ रहे हैं, और जो संक्रमण से बचने की सबसे महत्वपूर्ण शर्त है, उसे उन्होंने न याद करना जरूरी समझा, न याद दिलाना।

सच तो यह है कि चुनावों में भाग लेने वाले सभी दलों के नेताओं को 'मास्क' या 'दूरी' की कोई चिंता नहीं थी। सभाओं और जुलूसों की विशालता उन्हें अपनी राजनीतिक सफलता की गारंटी लग रही थी। यह विशालता कोरोना की भयावहता को बढ़ा रही है, यह बात किसी को नहीं सूझ रही थी। देश के गृहमंत्री खुलेआम यह कहते रहे कि पश्चिम बंगाल की चुनावी रैलियों पर उंगली उठाने वाले बाकी जगहों की बात क्यों नहीं करते। बाकी जगहों की बात भी हुई है जनाब। वस्तुत: चार राज्यों और एक केंद्रशासित प्रदेश में होने वाले इन चुनावों में कोरोना से बचने के नियमों की जिस तरह धज्जियां उड़ाई गई हैं, वह अपने आप में किसी अपराध से कम नहीं है। पश्चिम बंगाल में चुनाव इतने लंबे चले हैं, इसलिए वहां की बात ज्यादा हो रही है। हमारे नेताओं ने अपने राजनीतिक स्वार्थों के लिए जिस तरह की लापरवाही बरती है, उससे चुनावों में भले ही उन्हें कुछ लाभ मिल जाए, पर देश की जनता को इसकी भारी कीमत चुकानी पड़ेगी।

गैरजिम्मेदार दिखे नेता

इस समूचे चुनाव-प्रचार के दौरान हमारे राजनीतिक नेतृत्व ने एक गैर-जिम्मेदाराना व्यवहार का उदाहरण ही पेश किया है। सत्ता की राजनीति को प्राथमिकता देने वाले हमारे नेता यह भूल गए कि जनतंत्र में राजनीति सत्ता के लिए नहीं, जनता के लिए होनी चाहिए। जनतंत्र में जनता की सरकार होती है और जनता के लिए होती है। जनता के हितों की उपेक्षा करने वाला भले ही और कुछ भी हो, जनता का सच्चा नेता नहीं हो सकता। जिस दिन प्रधानमंत्री ने हरिद्वार में एकत्र संत समाज से प्रतीकात्मक स्नान की अपील की थी, उस दिन देश में कोरोनाग्रस्त होने वाले मरीजों की संख्या एक लाख साठ हजार से अधिक थी। यह तब तक का सबसे बड़ा आंकड़ा था। और, दुर्भाग्य से यह आंकड़ा लगातार बढ़ता जा रहा है। कह नहीं सकते इस महामारी से हमारी लड़ाई कब तक चलेगी, पर इतना तो कहा ही जा सकता है कि अब इस लड़ाई में कोई भी ढिलाई स्वीकार नहीं होनी चाहिए। राजनीतिक दलों के स्वार्थ जनता के हितों के समक्ष बेमानी है। और जनता के हितों का तकाजा है कि हमारा समूचा राजनीतिक नेतृत्व विवेक का परिचय दे। यह समय एक-दूसरे पर दोषारोपण का नहीं है, एक-दूसरे के साथ मिलकर एक भयावह स्थिति से उबरने का है। सत्ता की राजनीति तो चलती रहेगी, आवश्यकता जनता के हितों की रक्षा करने वाली राजनीति की है। प्रधानमंत्री पर जनता ने भरोसा किया था, इसीलिए उन्हीं को दूसरी बार सत्ता सौंपी। अब यह उनका दायित्व बनता है कि वह जनता के विश्वास पर खरा उतरने की चुनौती को स्वीकार करें। वे देश के प्रधानमंत्री हैं, इसलिए उनसे अपेक्षा की जाती है कि वे दलगत राजनीति से ऊपर उठकर सोचेंगे।

कोरोना की पहली लहर के समय भी हमारे हुक्मरानों को इस बात की चिंता ज्यादा थी कि 'नमस्ते ट्रंप' कार्यक्रम सफलतापूर्वक निपट जाए। इसीलिए, तब लॉकडाउन के निर्णय में देरी की गई और फिर जल्दबाजी में की गई लॉकडाउन की घोषणा के परिणाम देश ने भुगते। प्रधानमंत्री इस दौरान लॉकडाउन की अपनी रणनीति को लेकर अपनी पीठ लगातार थपथपा रहे थे, पर सारे देश ने तब 'नमस्ते ट्रंप' की कथित सफलता की कीमत चुकाई थी, अब तक चुका रहा है!

अब जबकि देश कोरोना की सुनामी को झेल रहा है, यह सवाल बार-बार उठ रहा है कि हमारा नेतृत्व स्थिति की गंभीरता को क्यों नहीं समझना चाहता? अच्छी बात यह है कि प्रधानमंत्री ने देर से ही सही, यह निर्णय लिया है कि अब प्रचार के लिए विशाल सभाएं नहीं होंगी। यहां भी कांग्रेस के नेता राहुल गांधी ने स्वागत-योग्य पहल की है। उनके विरोधी कह सकते हैं कि उन्हें तो एक बहाना मिल गया था अपना सिर छुपाने का, पर विरोधियों द्वारा 'पप्पू' कहे जाने वाले राहुल गांधी ने चुनावी सभाएं रद्द करने की पहल करके निश्चित रूप से सराहनीय कदम उठाया है। यह कदम चुनावी प्रचार में लगे हर नेता को उठाना चाहिए था। सत्तारूढ़ पक्ष (भले ही वह केंद्र का हो या पश्चिम बंगाल का) को इस दिशा में पहल करनी चाहिए थी। वह विफल रहा। चुनाव आयोग भी चाहता तो विवेक का परिचय देते हुए चुनावी रैलियों पर प्रतिबंध लगा सकता था। पर उसने भी पता नहीं क्यों, यह काम नहीं किया। पश्चिम बंगाल और चुनाव वाले अन्य राज्यों में कोरोना कितना फैलता है, यह तो आने वाला कल ही बताएगा, पर हमारे स्वनामधन्य राजनेताओं ने कोई कसर नहीं छोड़ी है कोरोना के स्वागत में।

● सुनील सिंह

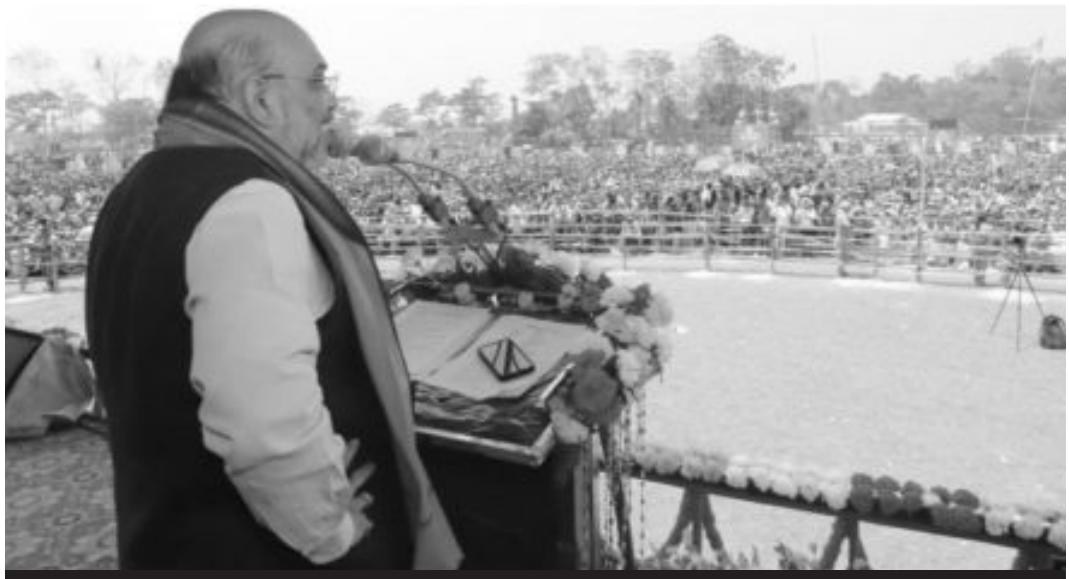

केसरिया गढ़ बनेगा बंगाल?

दुनिया की सबसे बड़ी राजनीतिक पार्टी भाजपा जब अपना 41वां स्थापना दिवस मना रही है, उस वक्त उसका सपना कोलकाता की राइटर्स बिल्डिंग में अपने मुख्यमंत्री को देखने का है। इसी कोलकाता में 70 साल पहले मार्च, 1951 में डॉ. श्यामाप्रसाद मुखर्जी ने जनसंघ की पश्चिम बंगाल इकाई की शुरुआत की थी, जिससे बनी पार्टी के नेताओं को इन चुनावों में मुख्यमंत्री ममता दीदी 'बाहरी' कहकर 'बाहर' करने की बात कर रही हैं।

राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के संस्थापक और पहले सरसंघचालक डॉ. केशव बलिराम हेडगेवार ने कॉलेज के दौरान अपनी शुरुआत क्रांतिकारी संगठन अनुशीलन समिति के साथ कोलकाता में ही की थी, लेकिन भाजपा को इतने अरसे के बाद भी पश्चिम बंगाल में अपनी जड़ें जमाने का मौका नहीं मिल पाया है, क्या इस बार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में यह मुमकिन हो पाएगा? सवाल तो और भी हैं। जैसे- 1999 में जिस एआईएडीएमके की नेता जयललिता की वजह से वाजपेयी की सरकार गिर गई थी, क्या उसी पार्टी की सरकार भाजपा इस बार फिर से तमिलनाडु में बनवा पाने में मदद कर पाएगी।

संघ की सबसे ज्यादा शाखाओं वाले राज्य केरल में भाजपा कमल खिला पाएगी? जहां अपनी ही 75 साल की उम्रसीमा के नियम को तोड़कर 88 साल के मेट्रोमैन श्रीधरन को चुनावी मैदान में उतारा गया है? क्या छोटे से केंद्रशासित प्रदेश पुडुचेरी में पार्टी अपनी सरकार बना लेगी जहां कुछ महीनों पहले उसने कांग्रेस के नारायणसामी की सरकार गिराने में अहम भूमिका निभाई थी और क्या जनसंघ के जमाने से घुसपैठियों का मुद्दा उठाने के बाद भी असम में फिर से सरकार बन जाएगी? इस पर शायद ही कोई शक करेगा कि नरेंद्र मोदी आज देश के सबसे लोकप्रिय राजनेता हैं और साल 1984 में दो सीटों से सफर शुरू करने वाली भाजपा ने मोदी के नेतृत्व में 2019 में 303 लोकसभा सीटें हासिल की हैं और देश के आधे से ज्यादा राज्यों में उसकी सरकारें हैं।

अपने गठन के वक्त गांधीवादी समाजवाद के रास्ते को छोड़कर अब पार्टी हिंदुत्व के रास्ते पर चल रही है उसने अपने कोर एजेंडे के दो बड़े मुद्दों राम मंदिर निर्माण और जम्मू-कश्मीर में धारा 370 हटाने के वादे को पूरा कर दिया है, जाहिर है मोदी के नेतृत्व में यह सब हुआ है। एक जमाने में भाजपा का नारा होता था- सबको मौका दिया, इस बार हमें मौका दें।

भाजपा के इस मंजिल तक पहुंचने के पीछे मोदी का नेतृत्व तो है ही लेकिन संगठन में एकजुट होकर काम करने की उसकी ताकत का मुकाबला नहीं किया जा सकता। राजनीतिक विशेषज्ञों का यह दावा भी किसी हद तक सही है कि मोदी और अमित शाह जैसे 24 घंटे काम करने वाले नेता किसी

भाजपा के इस मंजिल तक पहुंचने के पीछे मोदी का नेतृत्व तो है ही लेकिन संगठन में एकजुट होकर काम करने की उसकी ताकत का मुकाबला नहीं किया जा सकता। राजनीतिक विशेषज्ञों का यह दावा भी किसी हद तक सही है कि मोदी और अमित शाह जैसे 24 घंटे काम करने वाले नेता किसी दूसरी पार्टी में नहीं हैं। संघ लंबे समय से बंगाल और केरल में हिंदू राष्ट्रवाद को मुद्दा बनाने की कोशिश में लगा है। इन दोनों ही राज्यों में विधानसभा के चुनाव हो रहे हैं। केरल पर संघ का जादू अब भी नहीं चल रहा है लेकिन बंगाल पर उसका असर दिखाई दे रहा है।

धर्म के आधार पर मतदान

पश्चिम बंगाल का विधानसभा चुनाव दरअसल भाजपा से ज्यादा राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ (आरएसएस) की प्रतिष्ठा का सवाल बन गया है। बंगाल देश का एक ऐसा राज्य है जहां करीब 50 सालों से धर्म, चुनाव का मुद्दा नहीं बना। वामपंथी दलों ने यहां 34 सालों तक राज किया, उसका एक बड़ा कारण बंगाल की राजनीति पर आर्थिक मुद्दों का बोलबाला था। उसके बाद 2011 में ममता बनर्जी की तृणमूल कांग्रेस भी आर्थिक मुद्दों पर ही सत्ता तक पहुंची। इस बार दो चरणों के मतदान के बाद राजनीतिक समीक्षकों का मानना है कि संघ बंगाल के मतदाताओं को धर्म के आधार पर विभाजित करने में काफी हद तक सफल हो गया है। भाजपा को 2016 के विधानसभा चुनावों में महज तीन सीटें मिली थीं। और अब वो बहुमत के साथ सरकार बनाने की दावेदार बन गई है। इसके पीछे भाजपा की ये सोच है कि बंगाली हिंदू धर्म के आधार पर वोट डाल रहे हैं।

दूसरी पार्टी में नहीं हैं। साथ ही यह भी सच है कि जहां कांग्रेस पिछले कई साल से अपने नए अध्यक्ष की तलाश में ना केवल उलझी हुई है बल्कि इस मांग को करने वालों को बागी करार दिया गया है जबकि भाजपा में पिछले 41 साल में 11 चेहरे अध्यक्ष पद पर रहे हैं बल्कि हर बार आसानी से यह बदलाव हुआ है और उनमें से कोई अध्यक्ष पारिवारिक या वंशवाद का हिस्सा नहीं रहा है। यह बात भी अहम है कि ज्यादातर नेता आम कार्यकर्ता से ऊपर उठकर यहां तक पहुंचे हैं, इसमें वाजपेयी से लेकर मौजूदा अध्यक्ष जेपी नड्डा तक का नाम शामिल किया जा सकता है।

29 दिसंबर, 1980 को मुंबई में नई पार्टी भाजपा के अध्यक्ष अटल बिहारी वाजपेयी ने अपने भाषण में कहा था, 'अंधेरा छटेगा, सूरज निकलेगा, कमल खिलेगा।' कार्यकर्ताओं में जोश भर गया। पूरा मैदान उत्साह से भरा था, लगा कि यह पार्टी देश को नई दिशा देगी और पार्टी को दिशा देने का मौका जल्दी ही इस नेता यानी वाजपेयी को मिलेगा। जनता पार्टी के टूटने, उससे अलग होने, बिछुड़ने की कड़वाहट जैसे गायब हो गई थी। हर कार्यकर्ता जोश और उत्साह से लबालब, मानो बस अब भाजपा की सरकार बनना दूर नहीं। अब कमल खिलने से कोई नहीं रोक सकता। 6 अप्रैल, 1980 को दिल्ली के फिरोजशाह कोटला मैदान में भाजपा की शुरुआत हुई थी। साल 1984 में इंदिरा गांधी की हत्या के बाद हुए चुनावों में भाजपा को सिर्फ दो सीटें मिलीं, जो 1952 में जनसंघ के गठन के बाद हुए पहले चुनाव में मिली तीन सीटों से भी कम थीं तो ज्यादातर राजनीतिक विश्लेषकों ने उसकी कब्र बनाकर फूल चढ़ाना शुरू कर दिया था।

15 से 17 मार्च 1985 तक कोलकाता में हुई भाजपा की राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक में वाजपेयी ने इन नतीजों के लिए नैतिक जिम्मेदारी लेते हुए कई बुनियादी सवाल भी उठाए। वाजपेयी का कहना था कि मुंबई में 1980 में हुए पार्टी के अधिवेशन में यह माना गया था कि भाजपा को कांग्रेस (आई) के विकल्प के तौर पर विकसित किया जाना चाहिए। लेकिन पांच साल बाद हम खुद को उस लक्ष्य से कोसों दूर पाते हैं... वाजपेयी कभी खुद की जिम्मेदारी से नहीं बचते। उन्होंने कहा कि यह मान भी लिया जाए कि 84-85 के चुनाव अप्रत्याशित हालात में हुए थे, जिन पर किसी का नियंत्रण नहीं होता तो भी हमारी पराजय का एकमात्र कारण यह नहीं था।

मई, 1986 में दिल्ली में भाजपा की राष्ट्रीय परिषद की बैठक में आडवाणी अध्यक्ष हो गए। नेतृत्व में बदलाव भले ही दिल्ली में हो रहा था, लेकिन उसका आदेश नागपुर में संघ मुख्यालय से आया था। गांधीवादी समाजवाद से सांस्कृतिक राष्ट्रवाद की तरफ, आदेश था कि चलना है। यानी वाजपेयी को किनारे लगाने की कोशिश। लेकिन ये इतना आसान काम भी नहीं था। भाजपा का काम बिना वाजपेयी के चलने वाला नहीं था, सो उन्हें मप्र से राज्यसभा में भेज दिया गया। 30 जून, 1986 को वाजपेयी ने एक बार फिर राज्यसभा में सांसद की शपथ ली, लेकिन सड़क पर भाजपा ने दूसरा रास्ता अख्तियार करने का फैसला कर लिया।

उस वक्त तक संघ परिवार में माना जाने लगा कि जरूरत हो तो हिंदू हित के लिए अलग पार्टी को भी खड़ा किया जा सकता है। इसी पर विचार करने के लिए 1987 में नागपुर में संघ का सात दिन का वर्ग लगा। इस वर्ग में वाजपेयी और आडवाणी भी शामिल थे और नई पार्टी बनाने या फिर भाजपा के रास्ते हिंदुत्व का एजेंडा आगे बढ़ाने पर गहन विचार मंथन हुआ। कहा गया कि यदि पार्टी खुद को हिंदू हित रक्षक के रूप में प्रस्तुत नहीं करती है तो इसका कोई भविष्य नहीं है लेकिन वाजपेयी इससे सहमत नहीं थे। भाऊराव देवरस इस पूरी योजना की देखरेख कर रहे थे।

तमाम झटकों और पथरीले रास्तों के बावजूद भाजपा अपनी विचारधारा को लेकर आगे बढ़ी और 1996 में केंद्र में भाजपा की सरकार बनी और अटल बिहारी वाजपेयी प्रधानमंत्री बने। भाजपा और वाजपेयी दोनों का राजनीतिक वनवास खत्म हो गया। 1996 में जब वाजपेयी को राष्ट्रपति ने सरकार बनाने के लिए आमंत्रित कर लिया, तब भी कोई दूसरा राजनीतिक दल उनके साथ आने को तैयार नहीं था। लेकिन बाद में वाजपेयी ने 1998-1999 में सरकार बनाई भी और अच्छे से चलाई भी। तब तक कई राज्यों में भी भाजपा की सरकारें बनने लगीं थी।

फिर आया 2014, जब भाजपा ने 282 सीटों के साथ स्पष्ट बहुमत वाली सरकार बनाई और अगले चार साल में पूरे देश का राजनीतिक रंग भगवा कर दिया। मोदी के नेतृत्व में 2019 में जब दोबारा सरकार बनी तो सब हैरान थे। 303 सीटों के साथ भाजपा जीती। तीन सीट से सफर शुरू करने वाली पार्टी और आज कोई ऐसा नहीं था जो उसके साथ मिलकर सरकार नहीं बनाना चाहता हो। 1990 में भाजपा के गठन के साथ ही पंच निष्ठा-राष्ट्रवाद और राष्ट्रीय अखंडता, लोकतंत्र, सकारात्मक धर्मनिरपेक्षता-सर्वपंथ समभाव और गांधीवादी समाजवाद है। जनसंघ के इस उद्देश्य पर ही नई बनी भाजपा ने चलना शुरू किया और बहुत सी बाधाओं के बावजूद विचारधारा का रास्ता नहीं छोड़ा।

भारतीय जनसंघ के महासचिव दीनदयाल उपाध्याय ने 1961 में लिखा था कि 'जनता के लिए काम करने वाले राजनीतिक दल जनता की ताकत से ही खड़े होते हैं... राजनीतिक दलों की रचना जनता करती है और उनका भाग्य भी वही तय करती है... राजनीतिक दल जो लोगों के लिए खड़े हैं, वे लोगों की ताकत पर खड़े होते हैं... यह वे लोग हैं जो राजनीतिक दल के आर्किटेक्ट और उसके राजनीतिक भाग्य के माध्यम होते हैं।

● राजेश बोरकर

पांच राज्यों के चुनाव तय करेंगे कितने लोकप्रिय हैं मोदी?

पांच राज्यों के चुनावों के नतीजे केंद्र सरकार, भाजपा के साथ-साथ कांग्रेस समेत पूरे विपक्ष की राजनीति पर असर डालेंगे। इनसे पता चलेगा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की लोकप्रियता का ग्राफ किस ओर जा रहा है। इनसे ममता बनर्जी का राजनीतिक भविष्य भी तय होगा। लेकिन कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी के लिए भी इन चुनावों के नतीजे मोदी और ममता से किसी भी सूरत में कम अहम नहीं हैं। क्योंकि कांग्रेस में उनकी ताजपोशी का बहुत कुछ दारोमदार इन पांच राज्यों के विधानसभा चुनावों के नतीजों से तय होगा। इन चुनावों से देश की राजनीति के भविष्य से जुड़े पांच यक्ष प्रश्नों के जवाब निकल सकते हैं।

सिकुड़ता दायरा

कांग्रेस और गांधी परिवार की तकदीर आगामी विधानसभा चुनावों के नतीजों से तय हो सकती है। कांग्रेस पांचों राज्यों में सत्ता से बाहर है। अगर वह कम से कम दो राज्य भी जीत लेती है, तो यह राहुल के लिए पार्टी पर अपना प्रभुत्व दोबारा हासिल करने का मुकम्मल मौका होगा। कांग्रेस तमिलनाडु में डीएमके के साथ भागीदारी में सत्ता हासिल करने की उम्मीद कर रही है।

कांग्रेस के इतिहास में जहां पहली बार गांधी परिवार के तीन सदस्य (राहुल गांधी, उनकी मां सोनिया गांधी और बहन प्रियंका गांधी) एक साथ राजनीति में सक्रिय हैं, वहीं पार्टी पर परिवार की पकड़ इससे ज्यादा कमजोर पहले कभी नहीं थी। यह पारिवारिक तिकड़ी ज्यादा से ज्यादा अलग-थलग भी पड़ती जा रही है। अलग-थलग होने की इस तकदीर को मोटे तौर पर गांधी परिवार ने खुद ही न्यौता दिया है। राहुल कई वरिष्ठ नेताओं से दूर रहते हैं और उनके प्रति आलोचनात्मक हैं, वहीं सोनिया की गिरती सेहत परिवार और पार्टी की दूरी बढ़ा रही है। यही नहीं, अहमद पटेल के असमय निधन से सोनिया बुरी तरह लाचार हो गई हैं, जो पार्टी या गांधी परिवार के समक्ष संकट आने पर सबसे प्रमुख संकटमोचन होते थे।

नेताओं के तबकों में स्वीकृति और पर्दे के पीछे जोड़तोड़ में उनकी निपुणता ने सोनिया की मदद की थी और कई मौकों पर जब राहुल आहत अहंकार लिए बैठे थे, वे पार्टी के लिए धन जुटाते थे और सहयोगी दलों के साथ बातचीत करते थे। सबसे अहम बात यह कि उन्हें सोनिया गांधी का पूरा विश्वास हासिल था। लोकसभा के एक सांसद कहते हैं, 'वे परिवार और पार्टी के बीच संवाद का सबसे पहला तार थे। अब जब वह तार कट गया है, पार्टी और परिवार के बीच हमेशा एक-दूसरे के साथ मेल नहीं होता। राहुल हमेशा से ही कम सुलभ थे, अब अपनी सेहत और पटेल की मौत की वजह से सोनिया भी पहुंच से बाहर हो गई हैं।'

पार्टी के बड़े नेताओं के बजाय राहुल अब भी अपनी वफादार चौकड़ी के सलाह पर निर्भर हैं। यहां तक कि देश के लिए अहम मुद्दों पर भी, मसलन यह कि भारत के चीन के साथ चल रहे सरहदी तनाव पर पार्टी का रुख क्या होना चाहिए। वरिष्ठ कांग्रेसजनों की बुद्धिमता में यही वह अविश्वास है जिसकी वजह से दिग्गज नेता दावा करते हैं कि राहुल अलग-थलग और पार्टी मुश्किल में पड़ गई है। यहां तक कि तमिलनाडु और केरल विधानसभा चुनाव के प्रचार अभियान के दौरान भी राहुल पी चिदंबरम, उम्मन चांडी और शशि थरूर सरीखे तपे-तपाए और दिग्गज नेताओं की बजाय केसी वेणुगोपाल और मणिकम टैगोर जैसे भरोसेमंद सहायकों पर ही बहुत ज्यादा निर्भर रहे हैं। पार्टी के प्रथम परिवार ने जहां चुनाव अभियान की अगुवाई करने का जिम्मा वफादारों पर निर्भर करते हुए फिर अपने कंधों पर ले लिया, वहीं वे अक्सर पार्टी कार्यकर्ताओं के साथ बेमेल दिखाई दिए। मिसाल के लिए मार्च के पहले हफ्ते में जब प्रियंका असम पहुंचीं, तब उनकी यात्रा का कार्यक्रम आखिरी मौके पर अचानक बदल दिया गया। कामाख्या मंदिर जाने का कार्यक्रम बाद में सोचकर जोड़ा गया, जिससे परिवार और स्थानीय इकाई के बीच संवाद की खाई साफतौर पर उजागर हो गई।

उधर, विधानसभा चुनावों के मौजूदा

चुनाव परिणाम तय करेंगे राहुल का कद

5 राज्यों में चल रहे विधानसभा चुनाव राहुल गांधी का कद तय करेंगे। जहां तक असंतुष्टों की बात है तो अच्छे चुनाव नतीजों के जोश के साथ पार्टी के सिंहासन पर राहुल का आधिकारिक तौर पर आसीन होने से कांग्रेस में उनकी राजनीतिक पारियों का अंत हो सकता है। अगर नतीजे उलटे पड़ते हैं, तो उनके लिए यह राहुल के नेतृत्व पर निर्णायक हमला बोलने का मौका होगा। बिहार में, जहां राहुल के सबसे नजदीकी सलाहकारों में से एक सुरजेवाला ने चुनाव अभियान की देखरेख की थी, पार्टी के बेहद बुरे प्रदर्शन के बाद असंतुष्टों ने आवाज उठानी शुरू कर दी थी। मगर सोनिया गांधी ने मप्र के पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ की मदद से असंतुष्टों से कुछ मोहलत और शांति हासिल कर ली थी और पिछले साल दिसंबर में उन्हें भरोसा दिलाया था कि पार्टी अध्यक्ष पद के लिए संगठन के चुनाव फरवरी 2020 में करवाए जाएंगे। इस बीच, राहुल के सहयोगी उन्हें मनाने और राजी करने की कोशिशों में लगे रहे कि वे पार्टी अध्यक्ष पद फिर संभाल लें। राहुल का विचार यह था कि किसी को भी अध्यक्ष पद का चुनाव लड़ने दिया जाए।

अभियान के दौरान जमीन से जुड़े और अवाम के नजदीक शख्स के तौर पर दिखाई देने की राहुल की कोशिशों को मिली-जुली कामयाबी हासिल हुई। कुछ लम्हों पर तो खासी तालियां बजीं, जिनमें केरल में मछुआरों के साथ तैरने के लिए राहुल का समुद्र में छलांग लगाना भी शामिल था। वहीं ट्विटर की दुनिया इत्तेफाकन दिखाई दे गए उनके सिक्स-पैक ऐब 'वह भी 50 की उम्र में' और साथ ही उनके मार्शल आर्ट के हुनर को लेकर आहें भरने लगी।

मगर गलतियां भी हुईं और उनमें प्रमुख थी उत्तर-दक्षिण के फर्क पर उनकी टिप्पणी, जो दक्षिण भारतीय वोटरों को रिझाने की गरज से की गई थी। तिरुवनंतपुरम में 24 फरवरी को राहुल ने कहा, 'पहले 15 साल मैं उत्तर भारत का एमपी था। मैं दूसरे किस्म की राजनीति का अभ्यस्त हुआ करता था। मेरे लिए केरल आना ताजा हवा का झोंका था, क्योंकि अचानक यहां मैंने लोगों को मुद्दों में ज्यादा दिलचस्पी लेते पाया और केवल सतही ढंग से ही नहीं, बल्कि मुद्दों के ब्योरों में जाकर।' इस बात से उत्तर के उनके पार्टीजनों में खासी नाराजगी पैदा हुई और विरोधी भाजपा को राजनीतिक चारा मिल गया।

उनके एकाकी चुनाव अभियानों के वांछित नतीजे अभी मिलने हैं, वहीं पार्टी संगठन का ढांचा सुधारने की कोई कोशिश दिखाई नहीं देती है। न ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अगुवाई में भाजपा के बढ़ते कारवां का मुकाबला करने की कोई लगातार विचाराधारात्मक और रणनीतिक योजना ही दिखती है। मसलन, असम में, जहां पार्टी नागरिकता (संशोधन) कानून का इसलिए विरोध कर रही है क्योंकि इससे बांग्लादेश से आए अवैध हिंदू प्रवासियों को नागरिकता मिल जाएगी, वहीं उसने बदरुद्दीन अजमल की एआईयूडीएफ (ऑल इंडिया यूनाइटेड डेमोक्रेटिक फ्रंट) से हाथ मिलाया है, जिसे प्रवासी मूल के मुसलमानों के हितों की हिफाजत करने वाली पार्टी माना जाता है। इससे वह फायदा तिरोहित हो गया जो सीएए-विरोधी रुख की वजह से ऊपरी असम में पार्टी को मिलता। यही नहीं, भाजपा के कथित सांप्रदायिक एजेंडे के खिलाफ जहां वह अपनी सेक्युलर साख सामने रखने की कोशिश कर रही है, वहीं मंदिरों की यात्राएं गांधी भाई-बहनों के हर दौरे का हिस्सा हो गई हैं। लोकसभा के सांसद कहते हैं, 'हम भाजपा के नकली संस्करण बन गए हैं। खोई जमीन फिर जीतनी है तो हमें कुछ नया लेकर आने की जरूरत है।'

यह सब तब हो रहा है जब पार्टी की भौगोलिक मौजूदगी लगातार सिकुड़ती जा रही है। भारत के 30 राज्यों में से वह फिलहाल केवल तीन राज्यों (पंजाब, राजस्थान और छत्तीसगढ़) में सत्ता में है और अन्य दो राज्यों (महाराष्ट्र और झारखंड) में सत्तारूढ़ गठबंधनों में जूनियर पार्टनर है। यह उप्र, बिहार, पश्चिम बंगाल, ओडिशा, तेलंगाना, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु और दिल्ली सरीखे बड़े राज्यों में, जहां से लोकसभा की 543 में से कुल 240 सीटें आती हैं, मुख्य विपक्षी पार्टी भी नहीं रह गई हैं। बीते दो सालों में उसने कर्नाटक, मप्र और पुडुचेरी में मुख्यत: कांग्रेस नेताओं के दलबदल की वजह से अपनी सरकारें गिरती देखी हैं। मप्र में राहुल के सबसे नजदीकी विश्वासपात्रों में से एक ज्योतिरादित्य सिंधिया पाला बदलकर भाजपा में चले गए। राजस्थान में उनके एक और पसंदीदा नेता सचिन पायलट पार्टी छोड़कर तकरीबन चले ही गए थे, लेकिन तभी प्रियंका ने उन्हें कुछ निश्चित आश्वासन देकर रुकने के लिए मना लिया। पार्टी तेलंगाना, मणिपुर और गोवा में, जहां वह सत्ता में नहीं है, बड़े पैमाने पर दलबदल की गवाह बनी है।

जिन राज्यों में कांग्रेस ने बीते छह सालों में विधानसभा चुनाव जीते हैं, वहीं उसके पास या तो मजबूत स्थानीय नेतृत्व या संगठन का आधार है और यह बात पंजाब, मप्र, राजस्थान, छत्तीसगढ़ और कर्नाटक से जाहिर है। अशोक गहलोत से लेकर कमलनाथ और सिद्धारमैया तक इन क्षेत्रीय क्षत्रपों को चुनाव जीतने या जिंदा रहने के लिए गांधी परिवार की जरूरत नहीं है। पंजाब में पार्टी को कामयाबी मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह के प्रबंधन और नियंत्रण की बदौलत ज्यादा है। और जब मप्र और कर्नाटक में सरकारें गिरीं तो गांधी परिवार मूक दर्शक बना रहा। राज्यों के ज्यादातर ताकतवर और वफादार नेता या तो फीके पड़ रहे हैं या दरकिनार कर दिए गए हैं, ऐसे में राज्यों के स्थानीय निकायों के चुनाव में भी पार्टी में नई जान फूंकने का कोई संकेत दिखाई नहीं दे रहा है।

● इन्द्र कुमार

सोनिया की गुप्त रणनीति

आलाकमान के फैसलों का कांग्रेस और इसके अंदर बने धड़ों की किस्मत पर असर 2 मई को ही दिखेगा, जब चुनावों के नतीजे आएंगे, सोनिया गांधी खामोशी से ऐसी किसी परिस्थिति से निपटने की योजना तैयार कर रही हैं। वे पटेल का अस्थायी विकल्प खोज रही हैं जब तक कि राहुल खुद अपना सिपहसालार न ढूंढ लें जो पार्टी के हर तबके में स्वीकार्य हो। हालांकि सुरजेवाला, केसी वेणुगोपाल, अजय माकन और राजीव सातव के रूप में राहुल की सलाहकारों की टीम है, लेकिन वे पटेल के स्तर के नहीं हैं। फरवरी के आखिरी हफ्ते में, सोनिया की राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत से उनके निवास 10, जनपथ पर लंबी बैठक हुई। सूत्रों का कहना है कि सोनिया ने अपने पुराने सिपाही को राहुल के जिम्मेदारी संभालने को तैयार नहीं होने की दशा में कांग्रेस अध्यक्ष का पद संभालने को कहा है। कुछ दिग्गजों ने सोनिया को सलाह दी है कि अब प्रियंका को पार्टी की कमान संभालने दी जाए लेकिन वे अनिच्छुक दिखती हैं क्योंकि यह दोधारी तलवार भी साबित हो सकती है। अगर प्रियंका पार्टी को संभालने में कामयाब हो जाती हैं तो इससे राहुल के सियासी कैरियर पर पर्दा गिर जाएगा। अगर वे नाकाम रहती हैं, तो पार्टी असंतुष्टों के गांधी परिवार को बाहर करने के कोरस में नए सुर लग जाएंगे। गहलोत की पदोन्नति से असंतुष्टों के लिए ज्यादा जगह नहीं बचेगी क्योंकि पार्टी के विभिन्न धड़ों में उनके मित्र हैं, पर वे राजस्थान के मुख्यमंत्री कुर्सी छोड़ने के पक्ष में नहीं हैं। असंतोष की वजह से गांधी परिवार के पास न तो सांगठनिक शक्ति और न ही वह नियंत्रण है कि वह गहलोत को अपनी लाइन पर चलने के लिए मजबूर रख सके।

अटका लेमरू हाथी रिजर्व

छत्तीसगढ़ के जिस इलाके में राज्य सरकार ने केंद्र को हाथी अभयारण्य बनाने का हवाला देते हुए कोयला खदान आवंटित करने से मना किया, अब उसी इलाके में भूमि अधिग्रहण के लिए अधिसूचना जारी की गई है। छत्तीसगढ़ में हाथियों की संख्या बढ़ती जा रही है और राज्य के सरगुजा और बिलासपुर संभाग के जंगलों में रहने वाले हाथियों के झुंड अब भटकते हुए राजधानी रायपुर और बस्तर तक पहुंच रहे हैं। पिछले 20 सालों में राज्य में 162 हाथियों की मौत हो चुकी है और अधिकांश मौत हाथी-मानव संघर्ष का परिणाम हैं। 2005 में राज्य में लेमरू हाथी अभयारण्य बनाने की योजना पर काम शुरू हुआ था लेकिन यह अभयारण्य अब तक फाइलों में कैद है। हसदेव-अरण्य के जिस इलाके में लेमरू हाथी अभयारण्य बनाने की योजना है, उस इलाके में कई कोल ब्लॉक हैं, जिन्हें केंद्र सरकार खनन के लिए आवंटित कर रही है। राज्य सरकार की आपत्ति के बाद भी खुले बाजार में बेचने के लिए कोल ब्लॉक आवंटित किए जा रहे हैं। कोरबा जिले की पतुरियाडांड के सरपंच उमेश्वर सिंह आर्मो को 15 जून 2015 को मदनपुर में कांग्रेस पार्टी के नेता राहुल गांधी का वह वादा याद है, जिसमें उन्होंने कहा था कि अगर आदिवासी और ग्रामसभा नहीं चाहेगी तो इस इलाके में कोयला खनन नहीं होने दिया जाएगा। अब जबकि राज्य में कांग्रेस पार्टी की सरकार है और कुछ महीने पहले तक राज्य सरकार ने इस इलाके को हाथी अभयारण्य में शामिल करने का हवाला देकर केंद्र को एक के बाद एक चिट्ठियां भेजी हैं। बावजूद इसके, इस इलाके में कोयला खदान के लिए भूमि अधिग्रहण की अधिसूचना केंद्र सरकार द्वारा जारी कर दी गई है।

राज्यभर में पर्यावरण और आदिवासी मुद्दों पर काम करने वाले संगठनों के समूह, छत्तीसगढ़ बचाओ आंदोलन के आलोक शुक्ला का कहना है कि कोयला खदानों के लोभ में जंगलों से हाथी बेदखल किए जा रहे हैं। कई सालों से लंबित जिस लेमरू हाथी अभयारण्य पर मुहर लगाने की बात कही थी, वह भी खटाई में पड़ता नजर आ रहा है। नवंबर 2000 में छत्तीसगढ़ अलग राज्य बनने के बाद, कुछ सालों तक तो इन हाथियों को झारखंड और ओडिशा का प्रवासी हाथी घोषित कर इनसे संबंधित जिम्मेवारियों को टालने की कोशिश होती रही। राज्य की भाजपा की सरकार ने हसदेव अरण्य और धर्मजयगढ़ के 450 वर्ग किमी के इलाके में लेमरू हाथी अभयारण्य बनाने की योजना पर काम करना शुरू किया और केंद्र को इससे संबंधित प्रस्ताव भेजा गया। इसके अलावा पहले से ही संरक्षित तमोर पिंगला अभयारण्य के 972.16 वर्ग किमी और बादलखोल सेमरसोत अभयारण्य के 176.14 वर्ग किमी को भी हाथी अभयारण्य घोषित करने के लिए केंद्र को प्रस्ताव भेजा गया। हालांकि इन दो अभयारण्यों में नियमानुसार किसी भी तरह के खनन या गैर-वानिकी गतिविधियों की इजाजत पहले ही नहीं थी। केंद्र सरकार ने मार्च 2007 में एक विशेषज्ञ अध्ययन दल को भेजा और इस दल की रिपोर्ट के आधार पर 5 अक्टूबर 2007 को इन सभी तीन हाथी अभयारण्य को अपनी सहमति भी दे दी। राज्य सरकार ने सहमति के तुरंत बाद तमोर पिंगला अभयारण्य और बादलखोल सेमरसोत अभयारण्य को तो हाथी अभयारण्य घोषित कर दिया लेकिन प्रस्तावित लेमरू हाथी अभयारण्य के इलाके में ही बड़ी संख्या में कोयला खदानों के आवंटन के कारण इस पर चुप्पी साध ली।

कोयला खनन की चाहत से इस इलाके की परिभाषा बदलती रही। केंद्र सरकार के दस्तावेजों को देखें तो 2010 में कोयला मंत्रालय और वन पर्यावरण मंत्रालय ने देश के नौ कोयला प्रक्षेत्र के एक साझा अध्ययन के बाद हसदेव अरण्य के जंगलों की अति संपन्न जैव विविधता और पारिस्थितकी रूप से संवेदनशील पाया और इस पूरे इलाके को 'नो-गो एरिया' घोषित कर दिया। फैसला लिया गया कि यहां कोयला खनन नहीं किया जाएगा। लेकिन कुछ ही दिनों में कोयला खनन की जरूरतों का हवाला देकर 'नो गो' पर सरकार के भीतर ही सवाल उठने लगे। इसके कुछ दिनों के बाद ही 53 प्रतिशत हिस्से को 'नो गो एरिया' से बाहर कर दिया गया। सालभर बाद 'नो गो एरिया' का हिस्सा 47 प्रतिशत से घटाकर 29 प्रतिशत कर दिया गया।

जून-जुलाई 2014 में इस इलाके के 11.99 प्रतिशत हिस्से को निर्बाध क्षेत्र घोषित किया गया। घटते-घटते दिसंबर 2015 में इस इलाके का केवल 7 प्रतिशत हिस्सा ही निर्बाध क्षेत्र रह पाया। शेष इलाके को कोयला खदानों के लिए खोल दिया गया। इधर 2018 में जब राज्य में सरकार बदली और इस इलाके में कोयला खदानों के खिलाफ आंदोलन कर चुके भूपेश बघेल मुख्यमंत्री बने तो उन्होंने हाथियों की बढ़ी हुई संख्या और पर्यावरण संरक्षण के लिहाज से 15 अगस्त 2019 को, राज्य के 1995.48 वर्ग किमी इलाके में लेमरू हाथी अभयारण्य बनाने की घोषणा की और 27 अगस्त को मंत्रिमंडल ने इसकी मंजूरी भी दे दी। पूरे देश में सर्वाधिक कोयला उत्पादन करने वाले छत्तीसगढ़ में 5990.78 करोड़ टन कोयला का भंडार है। यह देश में उपलब्ध कुल कोयला भंडार का करीब 18.34 फीसदी है।

● **रायपुर से टीपी सिंह**

हाथी अभयारण्य में कोयला खदान

राज्य सरकार के दस्तावेज के अनुसार लेमरू हाथी अभयारण्य के लिए घोषित 1995.48 वर्ग किमी के दायरे में मांड-रायगढ़ कोयला प्रक्षेत्र के 11 कोल ब्लॉक का क्षेत्र भी शामिल है। इसके अलावा प्रस्तावित हाथी अभयारण्य के 10 किलोमीटर के बफर क्षेत्र में भी मांड-रायगढ़ के 12 कोल ब्लॉक शामिल हैं। कुल मिलाकर राज्य के 184 में से 54 कोल ब्लॉक हाथी अभयारण्य के दायरे में आ रहे हैं। इन कोयला खदानों के कारण मंत्रिमंडल की मंजूरी के लगभग 20 महीने बाद भी लेमरू हाथी अभयारण्य को अब तक अधिसूचित नहीं किया गया है। वन्यजीव विशेषज्ञ और राज्य सरकार की वन्यजीव बोर्ड की सदस्य मीतू गुप्ता का कहना है कि पिछले कई सालों से लेमरू हाथी अभयारण्य का मामला अटका हुआ है और नई सरकार के फैसले के बाद भी इस पर मुहर नहीं लगी है जिसके कारण वन और वन्यजीव लगातार खतरे में है।

गिर सकती है सरकार

भारत की राजनीति में वर्ष 2022 काफी महत्वपूर्ण रहने वाला है। 8 राज्यों में विधानसभा चुनाव होगा जिसके नतीजों का सीधा असर केंद्र की राजनीति पर पड़ेगा। इन 8 में से 6 प्रदेशों में भाजपा की सरकार है। पंजाब इनमें से एकलौता प्रदेश है जहां भारत की प्रमुख विपक्षी दल कांग्रेस पार्टी की सरकार है। 2019 में जम्मू और कश्मीर का पूर्ण राज्य का दर्जा समाप्त करने और एक केंद्र शासित प्रदेश बनने के बाद वहां पहली बार और नए सिरे से विधानसभा चुनाव होगा।

इस सूची में महाराष्ट्र का नाम शामिल नहीं है। पर इस बात की संभावना लगातार बढ़ती जा रही है कि महाराष्ट्र में भी शायद अगले वर्ष चुनाव हो। महाराष्ट्र में विधानसभा चुनाव अक्टूबर 2019 में हुआ था। भाजपा सबसे बड़ी पार्टी बनकर उभरी थी। भाजपा और शिवसेना ने साथ मिलकर चुनाव लड़ा था और उन्हें पूर्ण बहुमत भी मिला था। लेकिन मुख्यमंत्री पद पर ऐसी खींचतान हुई कि शिवसेना ने भाजपा के साथ दशकों पुराना रिश्ता तोड़ दिया।

भाजपा और शिवसेना ने हमेशा की तरह गठबंधन में चुनाव लड़ा था। 288 सदस्यों वाली विधानसभा में भाजपा 164 पर चुनाव लड़ी और 105 पर सफल रही थी। शिवसेना 124 सीटों पर चुनाव लड़ी और उसके खाते में 56 सीटें गईं। गठबंधन को पूर्ण बहुमत मिला था। बात जब सरकार बनाने की आई तो शिवसेना प्रमुख उद्धव ठाकरे ने मुख्यमंत्री पद की मांग कर डाली। उनका कहना था कि चूंकि भाजपा का मुख्यमंत्री पिछले पाच सालों से था, लिहाजा इस बार मुख्यमंत्री पद शिवसेना को मिलना चाहिए। भाजपा ने साफ मना कर दिया। नौबत राष्ट्रपति शासन लगाने तक की आई और फिर तोड़फोड़ की राजनीति शुरू हो गई। भाजपा ने एनसीपी के बागी नेता अजीत पवार के साथ मिलकर सरकार बनाई। अजीत पवार चाचा शरद पवार के दबाव के सामने टिक नहीं सके। सरकार तीन दिन ही चल पाई।

उद्धव ठाकरे अपने पुत्र आदित्य ठाकरे को मुख्यमंत्री बनाना चाहते थे। आदित्य ठाकरे परिवार का पहला सदस्य था जो चुनाव लड़ा था। शिवसेना के संस्थापक बाल ठाकरे को किंग-मेकर की भूमिका ज्यादा पसंद थी, पर उनकी मृत्यु के बाद ठाकरे परिवार में सत्ता की भूख बढ़ गई, अब वह किंग-मेकर नहीं बल्कि किंग बनना चाहते थे।

शरद पवार ने उद्धव ठाकरे के सामने मुख्यमंत्री पद का चारा डाल दिया, पर शर्त यही थी कि चूंकि आदित्य ठाकरे अभी युवा थे, लिहाजा मुख्यमंत्री स्वयं उद्धव को बनना होगा। कांग्रेस पार्टी के लिए सरकार में भागीदारी किसी लॉटरी से कम नहीं थी, एनसीपी ने सारे मलाईदार मंत्रालय जिसमें गृह मंत्रालय भी शामिल था, ले लिया। और फिर शुरू हुआ भ्रष्टाचार का तांडव जिसके लिए शरद पवार पर हमेशा से आरोप लगते रहे हैं। अब इसी भ्रष्टाचार के आरोप में महाराष्ट्र की सरकार डोलती दिख रही है। अगर उद्धव ठाकरे सरकार अभी भी चल रही है तो इसका एकमात्र कारण है कोरोना महामारी। मौजूदा हालात में कोई भी सरकार गिराने के पक्ष में नहीं है, भाजपा भी नहीं। पर जिस तरह केंद्रीय जांच दलों का शिकंजा कसता जा रहा है, इसकी प्रबल संभावना है कि कोरोना पर विजय मिलते ही महाराष्ट्र में उठापटक शुरू हो जाएगी।

जहां एनसीपी और कांग्रेस के साथ सिर्फ सत्ता के लालच में चिपकने से शिवसेना और ठाकरे परिवार को भारी नुकसान हो रहा है, वहीं दूसरी तरफ शिवसेना ने भाजपा को हिंदू हृदय सम्राट बनने के लिए खुला मैदान छोड़ दिया है। बाल ठाकरे अपने जीवनकाल में खुद को हिंदू हृदय सम्राट कहलवाना पसंद करते थे। इतना तो साफ है कि महाराष्ट्र में बदलाव आएगा, वह भी जल्द ही। अगर शिवसेना वापस भाजपा के साथ नहीं आई तो फिर समय से पूर्व चुनाव होना निश्चित दिख रहा है। शिवसेना के पास ऑफर होगा कि वह आदित्य ठाकरे को उपमुख्यमंत्री बना दें और भाजपा को मुख्यमंत्री पद सौंप दें। वरना केंद्रीय जांच दलों द्वारा महाराष्ट्र सरकार में हुए और हो रहे भ्रष्टाचार पर से पर्दा हटता चला जाएगा और शिवसेना की मुसीबतें बढ़ती चली जाएंगी। इसका नतीजा होगा वर्तमान सरकार का पतन और 2022 में महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव। यानि अगले वर्ष 8 नहीं बल्कि 9 राज्यों में चुनाव हो सकता है, जिसमें अगर भाजपा जीती तो उसकी भारत की राजनीति पर पकड़ मजबूत हो जाएगी और 2024 के लोकसभा चुनाव में विजय की तिकड़ी लगाने की संभावना बढ़ जाएगी। साथ ही साथ कांग्रेस पार्टी और कमजोर हो जाएगी।

● **बिन्दु माथुर**

पवार जो नहीं बोलते, डेफिनेटली करते हैं

शरद पवार के बारे में एक बात को लेकर सभी पार्टी के लोग एकमत हैं। शरद पवार जो बोलते हैं, वो करें या ना करें, जो वो नहीं बोलते वो डेफिनेटली करते हैं। अनप्रेडिक्टबिलिटी शरद पवार की राजनीति की विशेषता रही है। और इसके लिए ज्यादा पीछे जाने की जरूरत नहीं। जो राजनीतिक पंडित आज यह कहा करते हैं कि पवार और भाजपा का साथ हो ही नहीं सकता, वही पहले कहा करते थे कि सेकुलर पवार और हिंदुत्ववादी शिवसेना का साथ आना मुमकिन नहीं है। महाराष्ट्र की जनता ने वो मुमकिन होते देखा। इससे पहले 2014 के लोकसभा के चुनाव के वक्त सारे राजनीतिक पंडित सोचते रह गए जब शिवसेना से भी पहले शरद पवार की पार्टी ने ऐलान कर दिया कि 'मोदी है तो मुमकिन है।' यानी शिवसेना से पहले एनसीपी ने भाजपा को समर्थन देने का ऐलान कर दिया। इससे पहले कांग्रेस-एनसीपी की सरकार ठीक-ठाक चल रही थी। एनसीपी ने अचानक कांग्रेस से अपना समर्थन वापस ले लिया। और भाजपा-शिवसेना की सरकार बनने के लिए राहें आसान कर दी। इसलिए पवार राजनीति के बड़े खिलाड़ी हैं। राजनीतिक पंडितों को जो नहीं सूझता वो शरद पवार को सूझ जाता है।

फंस गए योगी!

योगी आदित्यनाथ लॉकडाउन के पिछले दौर में लोगों के लिए मसीहा बने हुए थे। उप्र के जो मजदूर दूसरे राज्यों में फंसे हुए थे या फिर इंजीनियरिंग की तैयारी करने गए जिनके बच्चे कोटा में फंसे हुए थे, उप्र में हर किसी के लिए मदद की आखिरी उम्मीद मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ही हुआ करते रहे। योगी आदित्यनाथ की हद से ज्यादा सक्रियता से बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार बेहद खफा रहे और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ कोरोना वायरस को लेकर हुई मीटिंग में तो मजदूरों की घर वापसी को लेकर एक राष्ट्रीय नीति बनाने की मांग कर डाली थी। मुख्यमंत्रियों की मीटिंग में नीतीश कुमार ने जो कुछ भी बोला था, निशाने पर योगी आदित्यनाथ ही नजर आए।

दरअसल, नीतीश कुमार लोगों के बिहार लौटने के पक्ष में कभी नहीं रहे। वो खुलकर बोल भी रहे थे कि जो जहां है वहीं रहे, वरना लॉकडाउन फेल हो जाएगा। हालांकि, लॉकडाउन से ज्यादा चिंता उनके अपने सिस्टम के फेल हो जाने की रही। हुआ भी वही। लगातार हाहाकार मचा रहा और बिहार विधानसभा चुनाव के नजदीक आते-आते सर्वे में भी नीतीश कुमार की लोकप्रियता घटती दर्ज की जाने लगी। भाजपा के आंतरिक सर्वे में भी मालूम हुआ कि नीतीश कुमार के लिए चुनाव जीत पाना मुश्किल हो सकता है और फिर चुनाव जिताने का पूरा दारोमदार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर ही आ गया। मोदी ने मिशन हाथ में तो लिया ही, मुमकिन भी बनाया। मोदी ने मुमकिन तो बनाया लेकिन सब कुछ भाजपा के खाते में डाल दिया। भाजपा के साथ नीतीश कुमार की भी पार्टी चुनाव जरूर जीती लेकिन जेडीयू तीसरे नंबर की पार्टी बन गई। नीतीश कुमार मुख्यमंत्री तो बन गए, लेकिन पावर छिन गया। बिहार सरकार में भाजपा का दखल काफी बढ़ गया।

योगी आदित्यनाथ के भाजपा के होने के चलते नीतीश कुमार जैसी समस्या तो नहीं आने वाली, लेकिन कोरोना संकट का दूसरा दौर अब पहले दौर की उनकी सारी कमाई पर पानी फेरने लगा है, उप्र की राजधानी लखनऊ ही नहीं, प्रधानमंत्री मोदी का संसदीय क्षेत्र वाराणसी के साथ-साथ प्रयागराज और कानपुर सभी शहरों का हाल एक जैसा हो चला है। ऐसे में जबकि उप्र में पंचायत चुनाव हो रहे हैं, सूबे के किसानों के निशाने पर रहे योगी आदित्यनाथ, कोरोना वायरस से बेकाबू हो चुके हालात में आम लोगों के गुस्से का शिकार हो रहे हैं और वो भी तब जब विधानसभा चुनावों की अग्नि परीक्षा की तारीख एक साल भी दूर नहीं रह गई है। अब तो यही लगता है नीतीश कुमार की ही तरह प्रधानमंत्री मोदी को ही योगी आदित्यनाथ के लिए भी खेवनहार बनना पड़ेगा।

योगी को भी मोदी का ही आसरा

उप्र पंचायत चुनाव के नतीजे अगर योगी आदित्यनाथ के शासन पर जनमत संग्रह समझे जाएं तो इसे विधानसभा चुनावों के लिए सेमीफाइनल के तौर पर भी देखा जा सकता है। जो हालात हैं, लगता तो ऐसा ही है कि आने वाले चुनाव में योगी आदित्यनाथ को भी चुनावी वैतरणी पार लगाने के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का ही आसरा होगा। ये तो करीब-करीब पक्का ही लगता है कि जैसे बिहार चुनाव में पिछले साल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आगे बढ़कर नीतीश कुमार को उबार लिया था, अगले साल उप्र चुनाव में योगी आदित्यनाथ के लिए भी वैसा ही कुछ करना पड़ेगा, लेकिन क्या कोरोना वायरस से पैदा हुई ये मुश्किलें खुद प्रधानमंत्री मोदी के लिए चुनौती नहीं बनेंगी, बड़ा सवाल ये भी है। प्रधानमंत्री मोदी के लिए भी उप्र चुनाव बिहार चुनाव जितना आसान नहीं होने वाला। बिहार में तो भाजपा ने सारी गड़बड़ियों का ठीकरा नीतीश कुमार के सिर फोड़कर एक रास्ता निकाल लिया था। बिहार चुनाव में भाजपा सारी बुरी बातों के लिए नीतीश कुमार को प्रोजेक्ट कर रही थी, जबकि सारी अच्छी बातों के लिए मोदी सरकार के नाम पर क्रेडिट ले रही थी। लेकिन अब ये डबल इंजन ही उप्र में भारी पड़ने वाला है, क्योंकि प्रधानमंत्री मोदी भी मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को नीतीश कुमार की तरह अलग करके प्रोजेक्ट नहीं कर सकते।

मार्च, 2020 में जब दिल्ली में मजदूरों का सैलाब किराए के मकानों से अपने पुश्तैनी घरों के लिए सड़क पर निकलकर आनंद विहार या गाजियाबाद बस अड्डा पहुंच गया तो सबसे पहले मदद की बसें भिजवाने वाला कोई और नहीं बल्कि योगी आदित्यनाथ ही रहे। योगी आदित्यनाथ ने दिल्ली-उप्र बॉर्डर पर कुछ ही घंटे के भीतर कई बसें भेज दीं और लोगों को पूरे प्रदेशभर में उनके घरों तक पहुंचाया था। ऐसे ही इंतजाम योगी आदित्यनाथ ने दूसरे राज्यों में फंसे उप्र के रहने वाले दिहाड़ी मजदूरों के लिए भी किया। वैसे भी मुसीबत की घड़ी में मिली मदद को हर कोई जिंदगीभर याद रखता है, फिर भी कुछ एहसान फरामोश होते जो दुनिया के तमाम अपवादों की तरह ऐसे मामलों में भी होते हैं। याद कीजिए कैसे नीतीश कुमार ने कोटा में पढ़ रहे बच्चों के सवाल पर रिएक्ट किया था। तब तो नीतीश कुमार यही समझा रहे थे कि सारे बच्चे सक्षम परिवारों के हैं और वे अपने बूते भी सब कर सकते हैं, लेकिन योगी आदित्यनाथ ने ऐसा कतई नहीं किया था।

योगी आदित्यनाथ ने न सिर्फ कोटा में फंसे छात्र-छात्राओं को साधन मुहैया कर उनका अपने-अपने घरों तक पहुंचना सुनिश्चित कराया बल्कि शिक्षा विभाग के अधिकारियों को निर्देश भी दे रखा था कि वे बच्चों से बराबर संपर्क में रहें और अगर उनकी कोई जरूरत हो तो हर संभव मदद भी करें। लेकिन कोरोना वायरस का मौजूदा दौर तो जैसे पहले दौर में हीरो बने रहे योगी आदित्यनाथ को जीरो बनाने पर तुला हुआ है। क्या लखनऊ और क्या बनारस या फिर कोई और भी शहर क्यों न हो, हाल बेहाल ही है। और शहर ही क्यों गांव देहात में भी हाहाकार मचा हुआ है। अब ये ऑक्सीजन की कालाबाजारी है या और कोई वजह लेकिन दावा और हकीकत में फासला तो लंबा ही है।

● **लखनऊ से मधु आलोक निगम**

राज्य में कांग्रेस की सरकार आते ही पार्टी के नेताओं को उम्मीद जगी थी कि उन्हें निगम या बोर्ड में कुर्सी मिल जाएगी। लेकिन 3 साल बाद भी उनकी उम्मीदें अधूरी हैं। इससे कांग्रेस नेताओं में आक्रोश पनप रहा है।

कांग्रेस नेताओं की उम्मीदें अधूरी

राजस्थान में अशोक गहलोत के नेतृत्व वाली सरकार के ढाई साल का यानी आधा कार्यकाल पूरा कर लिया है। इसके बावजूद अभी तक राजनीतिक नियुक्तियों की कांग्रेस नेताओं की उम्मीदें पूरी नहीं हो सकीं। हालांकि, पूर्व उपमुख्यमंत्री सचिन पायलट से लेकर उनके तमाम समर्थक विधायकों और कांग्रेस के नेताओं द्वारा राजनीतिक नियुक्तियों को लेकर लगातार आवाज उठाई जाती रही हैं। इसके बाद भी अभी तक मुख्यमंत्री गहलोत ने राज्य के किसी निगम या बोर्ड के अध्यक्ष और मेंबर को नियुक्त नहीं किया है, जिसके चलते तमाम कांग्रेस नेताओं के सपने अधूरे हैं?

बता दें कि राजस्थान में गहलोत सरकार बनने के बाद से ही कांग्रेस नेताओं और कार्यकर्ताओं को राजनीतिक नियुक्तियों का इंतजार है। सचिन पायलट के साथ-साथ उनके समर्थक विधायक मंत्रिमंडल विस्तार और राजनीतिक नियुक्तियां जल्द करने के लिए आवाज उठा रहे हैं। सचिन पायलट ने कहा था कि प्रदेश में सरकार बने ढाई साल का वक्त हो गया है और अब प्रदेश में राजनीतिक नियुक्तियां और मंत्रिमंडल विस्तार में देरी नहीं होनी चाहिए। पायलट के बाद उनके सहयोगी विधायकों ने भी उनके सुर में सुर मिलाना शुरू कर दिए और कई विधायकों ने भी इस मांग को दोहराया। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत राजनीतिक नियुक्तियों और मंत्रिमंडल के विस्तार के मूड में फिलहाल नहीं दिख रहे हैं। इसकी वजह यह है कि गहलोत अपने पिछले कार्यकाल में भी राजनीतिक नियुक्तियां आखिर के दो सालों में करते रहे हैं। इसी ट्रैक रिकॉर्ड को देखते हुए माना जा रहा है कि मुख्यमंत्री गहलोत राजनीतिक नियुक्तियों को लेकर अभी कुछ समय और भी ले सकते हैं। हालांकि, कांग्रेस प्रभारी अजय माकन ने वादा किया था कि 15 फरवरी तक प्रदेश में राजनीतिक नियुक्तियों को पूरा कर लिया जाएगा। लेकिन, तीन सीटों पर उपचुनाव और पांच राज्यों के विधानसभा के चलते यह मामला टल गया था। वहीं, अब जब सचिन पायलट गुट जिस तरह से राजनीतिक नियुक्तियों को लेकर मुखर है, ऐसे में अब इस मामले को ज्यादा टालना कांग्रेस के लिए मुश्किल खड़ी कर सकता है।

राजस्थान में प्रदेश स्तर पर तकरीबन 70 राजनीतिक नियुक्तियां होनी हैं जबकि जिलास्तर पर करीब 2 हजार से ज्यादा पदों पर नियुक्तियां होनी हैं। ऐसे में जिलास्तर की नियुक्तियों को लेकर ज्यादा सियासी खींचतान नहीं है, लेकिन प्रदेश स्तर की नियुक्तियों को लेकर पायलट और गहलोत दोनों ही खेमे नजर बनाए हुए हैं। हालांकि, कुछ महत्वपूर्ण पदों पर गहलोत अपने करीबी नेताओं की नियुक्तियां धीरे-धीरे कर चुके हैं। प्रदेश स्तर पर राजनीतिक नियुक्तियों में अति महत्वपूर्ण माने जाने वाले राज्य वित्त आयोग, हाऊसिंग बोर्ड, आरपीएससी, मानवाधिकार आयोग, सूचना आयोग और कर्मचारी चयन बोर्ड में नियुक्तियां हो चुकी हैं। बोर्ड और आयोगों में गहलोत एक-एक कर पहले ही अपने समर्थकों को एडजस्ट कर चुके हैं, लेकिन इनके अलावा भी करीब 65 से ज्यादा आयोग अभी खाली हैं। ऐसे में गहलोत समर्थक विधायक उम्मीद लगाए बैठे हैं कि मंत्रिमंडल में उन्हें अगर हिस्सेदारी नहीं मिलती है तो कम से कम राजनीतिक नियुक्तियों में उन्हें जगह दी जाएगी, क्योंकि इनमें से कई को आयोगों के जरिए सरकार मंत्री का दर्जा भी देती है। आयोगों और बोर्डों के अध्यक्ष को राज्यमंत्री और कैबिनेट मंत्री का ओहदा तक मिलता है। इसीलिए सभी की नजर बनी हुई है। हालांकि, गहलोत अभी एक साथ सभी नियुक्तियां करके किसी तरह से अपनी सरकार के लिए जोखिम भरा कदम नहीं उठाना चाहते हैं। इसीलिए फूंक-फूंक कर कदम रख रहे हैं ताकि पार्टी में किसी तरह की कोई फूट न हो सके। ऐसे में सचिन पायलट को साधने के लिए उपचुनाव नतीजों के बाद गहलोत मंत्रिमंडल का विस्तार कर सकते हैं, साथ ही राजनीतिक नियुक्तियों को धीरे-धीरे करने की रणनीति अपना सकते हैं?

● **जयपुर से आर.के. बिन्नानी**

गहलोत की मुश्किलें बढ़ा रहे पायलट

राजस्थान की सत्ताधारी पार्टी कांग्रेस में एक बार फिर से सियासी खींचतान और घमासान शुरू हो गया। पूर्व उपमुख्यमंत्री सचिन पायलट खेमा अपना हक मांगने लगा है। पायलट के साथ-साथ उनके समर्थक विधायकों ने मंत्रिमंडल विस्तार और राजनीतिक नियुक्तियां जल्द करने की आवाज उठानी शुरू कर दी है, लेकिन मुख्यमंत्री अशोक गहलोत जल्द विस्तार के मूड में नहीं हैं। पायलट के करीबी विधायक वेदप्रकाश सोलंकी ने सत्ता में अनुसूचित जाति और जनजाति की हिस्सेदारी का मुद्दा उठाया। ऐसे में देखना है कि मुख्यमंत्री अशोक गहलोत इस संकट से कैसे निपटते हैं? विधायक वेदप्रकाश सोलंकी ने कहा कि अनुसूचित जाति और जनजाति समुदाय की कांग्रेस सरकार के गठन में अहम भूमिका रही है। ऐसे में इन समुदाय के विधायकों को जनता से जुड़े दमदार और महत्वपूर्ण विभाग में मंत्री बनाया जाए। उन्होंने कहा कि वर्तमान में अनुसूचित जाति के मंत्रियों को कारखाना बायलर्स, श्रम जैसे विभागों का जिम्मा दिया गया है, जिन्हें कोई जानता तक नहीं है और इन विभागों से आम लोगों का भला भी नहीं किया जा सकता। सोलंकी ने मांग की है कि एससी और एसटी वर्ग के विधायकों को ऐसे विभाग दिए जाएं, जिससे वे अपने वर्ग का हित कर सकें। उन्हें चिकित्सा, ऊर्जा, पानी और स्वायत्त शासन जैसे विभाग दिए जाएं।

चारा घोटाला में लालू यादव फंसे या फंसाए गए?

बिहार के चारा घोटाले की शुरुआत पशुपालन विभाग के छोटे स्तर के कर्मचारियों ने की, जिन्होंने कुछ फर्जी फंड ट्रांसफर दिखाए। उस समय बिहार और झारखंड अलग नहीं थे। मामला 1985 में पहली बार सामने आया जब नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक (सीएजी) टीएन चतुर्वेदी ने पाया कि बिहार के कोषागार और विभिन्न विभागों से धन निकाला जा रहा है और इसके मासिक हिसाब किताब में देरी हो रही है। साथ ही व्यय की गलत रिपोर्ट भी पाई गई। करीब 10 साल बीतने पर यह बड़ा रूप ले चुका था।

लालू प्रसाद के शासनकाल में 1996 में राज्य के वित्त सचिव वीएस दुबे ने सभी जिलों के जिलाधिकारियों और डिप्टी कमिश्नरों को आदेश दिया कि अतिरिक्त निकासी की जांच करें। इसी समय डिप्टी कमिश्नर अमित खरे ने चाईबासा के पशुपालन विभाग के कार्यालय पर छापा मारा। इस छापेमारी में बड़ी मात्रा में दस्तावेज मिले, जिसमें अवैध निकासी और अधिकारियों व आपूर्तिकर्ताओं के बीच साठगांठ का पता चला। इसके बाद लालू प्रसाद सरकार ने अलग-अलग एक सदस्यीय जांच आयोग का गठन किया। पहले आयोग के अध्यक्ष राज्य विकास आयुक्त फूलचंद सिंह थे, जिसका गठन 30 जनवरी, 1996 को किया गया। बहरहाल, जब सिंह का नाम भी चार्जशीट में लिया जाने लगा तो इस आयोग को भंग कर दिया गया। दूसरे आयोग का गठन जस्टिस सरवर अली की अध्यक्षता में 10 मार्च, 1996 को किया गया। इस बीच भाजपा के तत्कालीन राज्य अध्यक्ष सुशील कुमार मोदी ने पटना उच्च न्यायालय में सीबीआई जांच की मांग करते हुए जनहित याचिका दायर कर दी। न्यायालय ने मामले की सुनवाई करने के बाद मामले को सीबीआई को सौंप दिया। यहीं से लालू प्रसाद के बुरे दिन शुरू हो गए। लालू प्रसाद न सिर्फ बिहार में प्रभावशाली थे, बल्कि केंद्र में भी किंगमेकर थे। उन्हीं की सहमति से केंद्र में एचडी देवगौड़ा की सरकार बनी थी। देवगौड़ा व लालू प्रसाद के आपसी अहम टकराने लगे थे और कहा जाता है कि लालू के मुंहफट स्वभाव के कारण देवगौड़ा से मतभेद बनने शुरू हुए थे। साथ ही विभिन्न जांच मामलों को लेकर देवगौड़ा के साथ कांग्रेस के सीताराम केसरी और पीबी नरसिंहराव में खींचतान चल रही थी।

लालू प्रसाद ने कवायद की कि सीबीआई के निदेशक पद पर एसएन सिंह की नियुक्ति हो जाए, जिन्हें राव का भी समर्थन हासिल था। आखिरकार देवगौड़ा ने कर्नाटक कैडर के आईपीएस जोगिंदर सिंह को सीबीआई निदेशक बना दिया। उसके बाद खींचतान इतनी बढ़ी कि कांग्रेस ने देवगौड़ा सरकार से समर्थन वापस ले लिया और उसके बाद इंद्र कुमार गुजराल प्रधानमंत्री बन गए। जोगिंदर सिंह ने जब पद से हटाए जाने की संभावना देखी तो उन्होंने चारा घोटाला मामले में आनन-फानन में चार्जशीट दाखिल कर दी। जुलाई, 1997 में दाखिल चार्जशीट में लालू प्रसाद एवं उनके पूर्ववर्ती मुख्यमंत्री जगन्नाथ मिश्र को भी आरोपी बनाया गया।

अनुमानित रूप से चारा घोटाला मामला 900 करोड़ रुपए का माना जाता है। इसमें 64 मामले दर्ज किए गए, जिसमें से 53 याचिकाएं रांची में दायर की गईं। सीबीआई ने 23 जून, 1997 को दाखिल चार्जशीट में लालू प्रसाद और 55 अन्य लोगों को आरोपी बनाया और आईपीसी की धाराओं 420 (धोखाधड़ी) और 120 बी (आपराधिक षड्यंत्र) और भ्रष्टाचार निरोधक अधिनियम की धारा 13 बी में मुकदमे दर्ज हुए। लालू प्रसाद को केंद्र और सीबीआई के माध्यम से घेरने की कहानी दिलचस्प है और धीरे-धीरे यह दिलचस्प होती गई। राज्य का मुखिया होने के कारण लालू प्रसाद को हर जिले के हर मामले में हुए आर्थिक हेरफेर के लिए जवाबदेह बनाया गया। सीबीआई न्यायालय ने 5 अप्रैल, 2000 को लालू प्रसाद के साथ उनकी पत्नी राबड़ी देवी को भी सह अभियुक्त बनाया, जो राज्य की तत्कालीन मुख्यमंत्री थीं। इसके अलावा आयकर विभाग ने 1998 में लालू और राबड़ी देवी को आय से अधिक संपत्ति रखने के मामले में आरोपी बनाया, जिसमें उन्हें दिसंबर 2006 में बरी कर दिया गया। इस मामले में आयकर विभाग का आरोप था कि लालू ने कोषागार से हुई निकासी में से 46 लाख रुपए लिए हैं। रांची में सीबीआई के विशेष न्यायालय ने जून, 2007 में तत्कालीन रेल मंत्री लालू प्रसाद के दो भतीजों सहित 58 लोगों को ढाई साल से 6 साल तक की सजा सुनाई, जो चाईबासा ट्रेजरी से 1990 में 48 करोड़ रुपए निकाले जाने को लेकर थी। इसके बाद मार्च, 2012 में सीबीआई की विशेष अदालत ने लालू प्रसाद और जगन्नाथ मिश्रा के खिलाफ आरोप तय किए, जो बांका और भागलपुर जिलों के कोषागार से 1995-96 में गलत तरीके से 47 करोड़ रुपए निकाले जाने के मामले से जुड़ा था। सितंबर, 2013 में सीबीआई के विशेष न्यायाधीश ने प्रसाद और मिश्रा के साथ 45 अन्य लोगों को दोषी करार दिया। लालू प्रसाद की लोकसभा की सदस्यता खत्म हो गई और सजा खत्म होने के 6 साल बाद तक के लिए उनके ऊपर चुनाव लड़ने से प्रतिबंध लग गया।

● **विनोद बक्सरी**

कई मामले चल रहे हैं लालू पर

कुल मिलाकर 900 करोड़ रुपए के कथित चारा घोटाला मामले में आयकर विभाग ने पाया कि लालू प्रसाद और राबड़ी देवी ने इसमें से 46 लाख रुपए लिए। लेकिन उस मामले से भी उच्चतम न्यायालय ने लालू प्रसाद को बरी कर दिया। लेकिन सीबीआई और उसकी विशेष अदालत ने लालू प्रसाद को अच्छे से रगड़ा। चारा घोटाला मामले को एक यूनिट न मानकर अलग-अलग मामलों में लालू प्रसाद को अलग-अलग सजाएं सुनाई गईं, जिसमें लालू प्रसाद को अलग-अलग सजा भुगतने के आदेश दिए गए। चाईबासा मामले में 5 साल की सज़ा, देवघर मामले में साढ़े तीन साल की सजा और दुमका कोषागार मामले में 7 साल की सजा। उच्च न्यायालय ने भी लालू प्रसाद को कोई ढील देने से मना कर दिया। आयकर विभाग ने पाया कि उनके आय से अधिक 46 लाख रुपए हैं, जो चारा घोटाले में सरकारी ट्रेजरी से आए और उससे भी सुप्रीम कोर्ट ने लालू को बरी कर दिया। झारखंड हाईकोर्ट ने पिछले शनिवार को लालू प्रसाद को जमानत दे दी। वह आधी सजा जेल में काट चुके हैं। हाईकोर्ट ने उन्हें जेल से बाहर आने के लिए 10 लाख रुपए मुचलका भरने का आदेश दिया है।

इकलौते जिहादी इमरान खान!

पाकिस्तान में कट्टरपंथियों और सरकार के बीच एक बार फिर ताजा झड़प हुई है। आतंकी संगठन के आरोप में प्रतिबंधित हुई तहरीक-ए-लब्बैक पाकिस्तान के समर्थकों और पुलिस के बीच गत दिनों को लाहौर सुलग पड़ा। टीएलपी कार्यकर्ताओं ने पुलिस के जवानों बंधक बना लिया था। हालांकि बंधकों को बाद में रिहा करा लिया गया। 'द डॉन' के मुताबिक इमरान खान ने पाकिस्तान की कुछ राजनीतिक पार्टियों पर धार्मिक भावनाओं के दुरुपयोग का आरोप लगाया। दावा किया कि उन्होंने अन्य मुस्लिम देशों के साथ प्रमुखता से फ्रांस में पैगंबर के अपमान के मुद्दे को लेकर अंतरराष्ट्रीय स्तर पर अभियान शुरू किया।

इमरान ने कहा- 'हमारे देश का यह एक बड़ा दुर्भाग्य है कि कई बार हमारे राजनीतिक दल और धार्मिक दल इस्लाम का गलत तरीके से इस्तेमाल करते हैं और इसका इस्तेमाल ऐसे करते हैं कि वे अपने ही देश को नुकसान पहुंचाते हैं।' यह भी कहा कि उन्होंने किसी भी दूसरे देश में धर्म (इस्लाम) के प्रति लोगों का ऐसा लगाव और पैगंबर से प्यार नहीं देखा। पाकिस्तान में पैगंबर के अपमान के लिए फ्रांस पर कार्रवाई का दबाव है। टीएलपी फ्रांस पर कार्रवाई के लिए पिछले कई महीनों से मुहिम चला रही है। 12 अप्रैल को टीएलपी पर बैन लगाकर उसके चीफ मौलाना साद हुसैन रिजवी को गिरफ्तार कर लिया गया था जिसके बाद दंगे भड़क गए थे। बीच-बचाव की कोशिशें भी जारी हैं जिसके तहत टीएलपी के साथ इमरान सरकार ने एक दौर की बातचीत की। पाकिस्तान से मिली खबरों पर यकीन करें तो जल्द ही दूसरे दौर की बातचीत भी होगी।

इमरान तीन चीजें एक साथ डील कर रहे हैं। एक- फ्रांस पर कार्रवाई के साथ गैर इस्लामिक अंतरराष्ट्रीय बिरादरी में रिश्ते खराब नहीं करना चाहते। दो- टीएलपी ले साथ सुलह के जरिए देश में खराब हो रही कानून व्यवस्था की स्थिति को दुरुस्त करना चाहते हैं और तीन- पाकिस्तान में कट्टरपंथी इस्लामिक राजनीति पर अपना नियंत्रण (एक तरह से कॉपी राइट) बनाए रखना चाहते हैं। यही वजहें हैं कि सरकार जिसे आतंकी संगठन बता रही है उसी के साथ सुलह की कोशिशों में भी जुटी है। फ्रांस में पैगंबर के विवादित कार्टून से शुरू हुआ अब तक का पूरा घटनाक्रम और इमरान के बयान से साफ हो जाता है कि टीएलपी और मौलाना साद हुसैन रिजवी की बढ़त से इमरान को बहुत दिक्कतें हैं।

पाकिस्तान समेत दुनियाभर का कट्टरपंथी समाज साद हुसैन को लेकर इमरान सरकार पर रिहाई का दबाव बनाए हुए है। कार्रवाई से टीएलपी पकड़ तो मजबूत दिख ही रही है साद हुसैन को भी लोकप्रियता मिल रही है। पाकिस्तान की सियासत में नवाज शरीफ जैसे वरिष्ठ नेता जेल में हैं। दूसरी पीढ़ी में मरियम नवाज और बिलावल जरदारी जैसे नेता बाहर होकर भी इमरान की राजनीति के सामने नेतृत्व की चुनौती पेश नहीं कर पाए हैं। अब विपक्ष की ओर से वो चुनौती टीएलपी और 27 साल के साद हुसैन पेश करते दिख रहे हैं।

1992 में इमरान की कप्तानी में पाकिस्तान ने क्रिकेट का विश्वकप जीता। इसके बाद पड़ोसी देश में उनकी छवि सबसे बड़े सेलिब्रिटी के रूप में बन गई। मां की याद में आला दर्जे का अस्पताल बनाने और दूसरे सामजिक कार्यों को करते हुए इमरान ने 1996 में तहरीक-ए-इंसाफ पाकिस्तान की नींव डाली। विकास, युवाओं को रोजगार और ताकतवर 'नया पाकिस्तान' के नारे के साथ राजनीति में कदम रखा। लेकिन राजनीति उनकी सोच से अलग निकली। उन्हें सफलता नहीं मिली। एक समय तो ऐसा भी दिखा कि इमरान राजनीति में हाशिए पर थे। मगर पिछले कुछ सालों में इमरान की राजनीति में जबरदस्त परिवर्तन दिखा।

राजनीति के शुरुआती वक्त में बेहद प्रगतिशील दिख रहे इमरान ने नए पाकिस्तान के नारे में एक और चीज जोड़ ली। भारत का अंधा विरोध और इस्लाम की ग्लोबली पॉपुलर इस्लामी कट्टरपंथी विचारधारा। फ्रांस इमरान के लिए राजनीति भुनाने का मुद्दा है लेकिन वो कभी चीन में उइगर मामलों को लेकर बोलते नहीं दिखते। इमरान ने अपनी छवि गढ़ने के लिए एक पर एक खूब समझौते किए। भारत से नजदीकी दिखा रहे नवाज शरीफ के विरोध में खड़ी हुई सेना की मदद ली। कट्टरपंथी नेताओं के दर पर पहुंचे। खुलकर उनका समर्थन लिया। भारत विरोध के हर मौके पर आगे रहे और इस्लाम के धार्मिक प्रतीकों का जमकर इस्तेमाल किया। कहा तो यह भी जाता है कि अपनी इस्लामिस्ट छवि गढ़ने के लिए इमरान ने बुशरा बीबी के साथ तीसरी शादी की। वो भी चुनाव से कुछ ही महीनों पहले। पहली पत्नी जेमिमा गोल्डस्मिथ के आधुनिक पहनावे और उनका रहन-सहन कट्टरपंथियों को पसंद नहीं आता था। इमरान से बुशरा बीबी की मुलाकात 2015 में हुई थी। वो पाकिस्तान के पंजाब प्रांत में कट्टरपंथी राजनीतिक परिवार से ताल्लुक रखती हैं। बुशरा बीबी इस्लाम की परंपराओं को मानने वाली बहुत ही धार्मिक किस्म की महिला हैं। वो बुर्के में ही रहती हैं। इस्लामिक पहनावे की वजह से कई बार सोशल मीडिया पर बहस का विषय भी बनी हैं। बहरहाल, इमरान खान के साथ मुलाकात बुशरा बीबी की बहन ने कराई थी जो पहले से ही पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ में सक्रिय थीं। बुशरा वो बड़ा जरिया हैं जिसकी वजह से इमरान ने कट्टरपंथी तबके को आकर्षित किया।

● **ऋतेन्द्र माथुर**

गले की हड्डी बना पुराना वादा

इमरान को तब टीएलपी की उस मांग पर आश्वासन देना पड़ा जिसमें फ्रांस के साथ कूटनीतिक और व्यापारिक रिश्तों के खात्मे की बात थी। उन्हें समयसीमा भी मिली। लेकिन इसी महीने अप्रैल में तय समयसीमा के नजदीक 27 साल का साद हुसैन रिजवी राजनीति कर सके ये बात इमरान को नागवार गुजरी। अचानक से रिजवी पर कार्रवाई हुई और सिर्फ चार साल में मजबूत राजनीतिक आधार बना लेने वाली पार्टी को बंधित कर दिया जिसका संस्थापक खुद को पाकिस्तान में पैगंबर का चौकीदार बताता था। भला इमरान ने जिस धार्मिक आधार पर सत्ता हथियाई उसकी राजनीति दूसरे के लिए कैसे छोड़ सकते हैं? मरियम नवाज और बिलावल से बिल्कुल अलग एक 27 साल का लड़का जो कुछ ही महीनों में सीधे इमरान के सामने है। इमरान की बौखलाहट से तो यही लगता है कि राजनीति में वो इकलौते जिहादी बने रहना चाहते हैं।

अफगानिस्तान की नई चुनौती

अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन ने अफगानिस्तान से अपने सैनिकों को बुलाने की समयसीमा तय कर दी है। अब इस साल 11 सितंबर तक अमेरिकी सैनिक पूरी तरह से अफगानिस्तान छोड़ देंगे। इस वक्त अफगानिस्तान में साढ़े तीन हजार अमेरिकी सैनिक हैं। हालांकि बाइडेन प्रशासन ने यह वादा किया है कि अमेरिका जरूरत पड़ने पर अफगान सेना को मदद देता रहेगा। पूर्व राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के कार्यकाल में भी तालिबान और अमेरिका के बीच हुए समझौते में मई 2021 तक अफगानिस्तान से अमेरिकी सैनिकों की पूर्ण वापसी पर सहमति बनी थी।

जो भी हो, अमेरिका के इस फैसले से अफगानिस्तान में एक बार फिर संकट का नया दौर शुरू होने जा रहा है। अफगान आबादी का बड़ा हिस्सा, खासतौर से महिलाएं अमेरिकी सैनिकों की पूर्ण वापसी नहीं चाहतीं। अफगान महिलाओं को डर है कि अब तालिबान उन्हें मिले अधिकार छीन सकता है। वहीं ताजिक, हजारा और उज्बेक जनजातियां भी इस फैसले से निराश हैं। अमेरिकी सैनिकों की वापसी की खबर भारत के लिए भी चिंता का विषय है।

अफगानिस्तान में भारत के अपने आर्थिक हित हैं। तालिबान के मजबूत होने के बाद अफगानिस्तान में पाकिस्तान मजबूत होने लगेगा। चीन ने भी अफगानिस्तान में भारी निवेश कर रखा है। ऐसे में वह चाहेगा कि भारत की स्थिति वहां कमजोर हो। रूस, अफगानिस्तान के खनिज संसाधनों पर नजरें गड़ाए हुए है। गौरतलब है कि अफगानिस्तान में तांबा, लोहा, लिथियम जैसे महत्वपूर्ण खनिज तत्वों का प्रचुर भंडार है।

इसमें कोई शक नहीं कि अमेरिकी सेना की वापसी के बाद अफगानिस्तान में तालिबान मजबूत होगा और इसका फायदा पाकिस्तान को मिलेगा। तालिबान और पाकिस्तान के संबंध जगजाहिर हैं। तालिबान के ज्यादातर कमांडर पाकिस्तान के देवबंदी मदरसों से ही निकले हैं। आईएसआई भी इन्हें प्रशिक्षण देती है। दो दशक पहले अफगानिस्तान पर अमेरिकी हमले के बाद तालिबान के ज्यादातर कमांडर भागकर पाकिस्तान ही पहुंचे थे। तालिबान शीर्ष कमेटी शूरा भी क्वेटा से ही संचालित होती है।

इस समय अफगानिस्तान के कुल 325 जिलों में से 76 जिलों पर तालिबान का कब्जा है और 127 जिले अफगानिस्तान की निर्वाचित सरकार के नियंत्रण में हैं। बाकी के बचे जिलों पर नियंत्रण के लिए अफगान सेना और तालिबान के बीच लंबे समय से संघर्ष चल रहा है। तालिबान और पाकिस्तान दोनों को लग रहा है अमेरिकी सेना की पूर्ण वापसी के बाद अफगान सेना कमजोर पड़ जाएगी। पाकिस्तान रणनीतिक तौर पर काबुल में मजबूत होकर भारत को पूरी तरह से वहां से बाहर कर और क्षेत्रीय शक्तियों के साथ संतुलन बनाकर अफगानिस्तान को नियंत्रित करना चाहता है।

हाल में रूसी विदेश मंत्री सर्गेई लावरोव की इस्लामाबाद यात्रा के दौरान पाक हुक्मरानों ने अफगानिस्तान के भविष्य पर उनसे विस्तृत चर्चा की। अफगानिस्तान में रूस की मौजूदगी का मतलब पाकिस्तान अच्छी तरह समझता है। बेशक रूस तीन दशक पहले अफगानिस्तान छोड़ गया हो, लेकिन रूसी खुफिया एजेंसियों की मजबूत मौजूदगी आज भी वहां है। यही नहीं अफगानिस्तान से लगने वाले मध्य एशियाई देशों में रूसी की भारी दखल है। इसलिए पाकिस्तान रूस से तालमेल बनाकर अफगानिस्तान में अपने को मजबूत करने की फिराक में है।

लेकिन सवाल यह है कि क्या पाकिस्तान के लिए यह सब इतना आसान होगा। अमेरिकी फौज की वापसी के बाद भी पाकिस्तान को लाभ के साथ-साथ नुकसान की संभावना है। दरअसल तालिबान की मौजूदगी को अफगानिस्तान की तीन दूसरी सशक्त जनजातियां स्वीकार करेंगी, इसकी संभावना कम है। ताजिक, उज्बेक और हजारा जनजातियों की पश्तून जनजातियों के वर्चस्व वाले संगठन तालिबान से कट्टर दुश्मनी है।

अफगान सेना में भी इन तीनों जनजातियों की खासी तादाद है। ये तीनों जनजातियां पाकिस्तान को नापसंद करती हैं और लंबे समय से आईएसआई-तालिबान गठजोड़ का मुकाबला कर रही हैं। ऐसे में अमेरिकी सैनिकों की वापसी के बाद तालिबान और आक्रामक होगा और अफगानिस्तान में गृह युद्ध भड़केगा। अगर यह गृह युद्ध लंबा खिंच गया तो इसका सीधा असर पाकिस्तान पर पड़ेगा। अफगान शरणार्थियों की भीड़ फिर से पाकिस्तान में पहुंचेगी। पाकिस्तान के सीमावर्ती खैबर पख्तूनख्वा और बलूचिस्तान में अफगान शरणार्थियों की खासी तादाद पहले से ही है। आज भी पाकिस्तान में 14 लाख से ज्यादा अफगान शरणार्थी हैं।

● **बृजेश साहू**

अफीम की खेती की चिंता

अमेरिकी सैनिकों की वापसी के बाद दुनिया की चिंता अफगानिस्तान में होने वाली अफीम की खेती को लेकर भी है। तालिबान का प्रभाव बढ़ने के साथ अफगानिस्तान में अफीम की खेती तेजी से बढ़ेगी। यह तालिबान की आय का सबसे बड़ा जरिया है। तालिबान अपनी आय का 60 प्रतिशत अफीम की खेती से हासिल करता है। पूरी दुनिया में अफीम के कारोबार में 90 फीसदी हिस्सेदारी अफगानिस्तान की ही है। हालांकि एक गलतफहमी यह है कि अफगानिस्तान में अमेरिकी सैनिकों की मौजूदगी से अफीम की खेती पर लगाम लगा। आंकड़े बताते हैं कि अफीम की खेती को नियंत्रित करने में पश्चिमी देशों की फौजें नकारा साबित हुईं। 2001 में जब अमेरिका ने अफगानिस्तान पर हमला किया, तब वहां 74 हजार हैक्टेयर में अफीम की खेती हो रही थी और उस साल 1800 मीट्रिक टन अफीम हुई थी। अमेरिकी फौजों की मौजूदगी के दौरान पिछले 20 वर्षों में अफीम की खेती तेजी से बढ़ी। 2002 में ही अफीम का उत्पादन बढ़कर 3400 मीट्रिक टन हो गया। वर्ष 2017 में 3 लाख 28 हजार हैक्टेयर में अफीम पैदा की गई और 6400 मीट्रिक टन पैदावार हुई। 2019 में भी यहीं आंकड़ा रहा।

जमीन का हक और महिलाएं

आधी आबादी के समान अधिकारों को वास्तविक रूप देना जटिल और चुनौती भरा काम है। देखा जाए तो यह अधूरा मानव अधिकार संघर्ष है। वैश्विक महामारी कोरोना ने इस अधूरे संघर्ष को और मुश्किल बना दिया है। महामारी का सबसे ज्यादा असर महिलाओं पर इसलिए हुआ है कि दुनियाभर में उनकी आर्थिक स्थिति हमेशा से हाशिए पर रही है। महिला सशक्तिकरण के तमाम दावे इस सत्य की अवहेलना करते आए हैं कि बगैर आर्थिक सुदृढ़ीकरण के महिला सशक्तिकरण की हर परिभाषा और कोशिश अधूरी है।

अनौपचारिक अर्थ अर्जन में संलग्न अधिकांश महिलाएं अर्थव्यवस्था की विपरीत लहर आते ही अपने रोजगार खो देती हैं। भूमि का अधिकार विश्व के अधिकांश देशों में आर्थिक स्थिरता का सबसे मजबूत साधन माना गया है। विभिन्न देशों में हुए अध्ययन बताते हैं कि जहां भी महिलाओं के पास भूमि संबंधी अधिकार होते हैं, वहां उनका परिवार पर प्रभाव होता है। वे अपने विचारों को आत्मविश्वास के साथ रख पाती हैं और इन सबसे महत्वपूर्ण यह कि वे घरेलू हिंसा की भी बहुत कम शिकार होती हैं। यह स्वाभाविक भी है क्योंकि जिसके पास अचल संपत्ति के अधिकार होते हैं, उसका प्रभुत्व परिवार और समाज में कहीं अधिक होता है, बनिस्बत उनके जिनके पास संपत्ति नहीं है।

वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम की ताजा रिपोर्ट बताती है कि दुनियाभर में आर्थिक समानता में महिलाओं की संख्या अट्ठावन फीसदी है। लेकिन पुरुषों के बराबर आने में उन्हें अभी सदियां लग जाएंगी। 156 देशों में हुए इस अध्ययन में महिला आर्थिक असमानता में भारत का स्थान 151वां है। यानी महिलाओं को आर्थिक आजादी और अचल संपत्ति का हक देने के मामले में एक तरह से हम दुनिया में सबसे नीचे आते हैं। ऐसे में यह प्रश्न उठना लाजिमी है कि आखिर ऐसा क्यों है कि शहरी और ग्रामीण दोनों ही क्षेत्रों में महिलाओं को भूमि पर अधिकार हासिल नहीं हैं, जबकि कानून में महिलाओं को संपत्ति पर पुरुषों के समकक्ष अधिकार हासिल होने का दावा किया जाता है।

भारतीय परिप्रेक्ष्य से इस संपूर्ण संदर्भ को देखें तो पाएंगे कि दो प्रकार के व्यवधान महिलाओं को संपत्ति का अधिकारी होने से वंचित करते हैं। पहला तो पुरुष सत्तात्मक समाज प्रभुत्व के सबसे महत्वपूर्ण साधन यानी भूमि को किसी भी स्थिति में महिलाओं को सौंपने को तैयार नहीं होता। दूसरा कारण यह कि महिलाएं स्वयं अपने अधिकारों को भावनात्मक कारणों से छोड़ देती हैं। परिवार के पुरुष सदस्यों द्वारा निरंतर उन्हें इस बात के लिए बाध्य किया जाता है कि अगर वे संपत्ति पर अधिकार के लिए कानून का सहारा लेंगी तो उन्हें पारिवारिक संबंधों को छोड़ना पड़ेगा।

इन वास्तविकताओं के साथ ही अगर तथ्यात्मक बिंदुओं का विवेचन किया जाए और आंकड़ों पर ध्यान दिया जाए तो जनगणना के आंकड़ों के अनुसार कृषि क्षेत्र में महिलाओं की भागीदारी एक तिहाई है। लेकिन उनके नाम भूमि मात्र 13 फीसद ही है। 2017-18 का श्रम बल सर्वे बताता है कि 73.2 फीसदी ग्रामीण महिलाएं खेती करती हैं, लेकिन जमीन सिर्फ 12.8 फीसदी महिलाओं के पास ही है।

पितृ सत्तात्मक व्यवस्था में यह सोच बहुत गहरे पैठी हुई है कि जमीन पुरुषों के नाम ही होनी चाहिए। नौकरी के लिए पुरुषों के शहरी क्षेत्रों में प्रवास के बाद पूरे एशिया में कृषि क्षेत्र में महिलाओं की संख्या बढ़ी है। बावजूद इसके अभी भी जमीन का मालिकाना हक महिलाओं के नाम नहीं के बराबर है। यही नहीं, विवाहित महिलाओं से उनके पीहर पक्ष द्वारा निरंतर दबाव बनाया जाता है कि वे पैतृक संपत्ति पर अपना अधिकार छोड़ दें।

जमीन के मालिकाना हक में बहुत बड़ी असमानताएं हैं। किसान की परिभाषा जमीन के मालिकाना हक से जुड़ी है। इसलिए खेतिहर महिलाएं किसान की परिभाषा के दायरे से ही बाहर हो जाती हैं। कहने को केंद्र की 2007 की राष्ट्रीय किसान नीति को ज्यादा व्यापक और समावेशी बनाया गया। इस नीति दस्तावेज में किसान की परिभाषा ऐसे व्यक्ति की है जो फसल उगाने और दूसरी प्रमुख कृषि उपज की गतिविधि से आजीविका और आर्थिक उपार्जन के लिए जुड़ा है। लेकिन वास्तविकता के धरातल पर महिलाओं के हाथ में कुछ भी नहीं है। संयुक्त राष्ट्र की एक रिपोर्ट के मुताबिक जबरन बेदखली या गरीबी के खतरे को कम कर के प्रत्यक्ष और सुरक्षित भूमि अधिकार महिलाओं को घर में उनकी सौदेबाजी की शक्ति को बढ़ाते हैं और उनकी सार्वजनिक भागीदारी के स्तर में सुधार करते हैं। परंतु जमीन पर अधिकार न होने का खमियाजा महिलाओं को सामाजिक और आर्थिक जीवन के सभी स्तरों पर भुगतना पड़ता है। सरकारी योजनाओं और अन्य सुविधाओं पर महिलाओं की पहुंच तब और कम हो जाती है जब जमीन उनके नाम पर नहीं हो, क्योंकि राजस्व विभाग एक किसान को भूमि के रिकॉर्ड के आधार पर परिभाषित करता है और कृषि विभाग राजस्व विभाग की परिभाषाओं का पालन करता है।

● **ज्योत्सना अनूप यादव**

जमीन के नियमों में लैंगिक गणना की आवश्यकता

भारत में विरासत के निर्धारित नियम हैं। जमीन को लेकर बने नियमों में लैंगिक गणना की आवश्यकता है, ताकि क्रियान्वयन में जो कमियां हैं उनकी पहचान कर दूर किया जा सके। फरवरी, 2019 में हुए एक अध्ययन के मुताबिक जमीन पर अधिकार देने से न सिर्फ महिलाओं को बल्कि समुदायों को भी जलवायु परिवर्तन के असर से बचाया जा सकता है। दुनियाभर में जितने लोग अपनी आजीविका के लिए जमीन और प्राकृतिक संसाधनों पर पूरी तरह निर्भर हैं, उनमें आधी से ज्यादा आबादी महिलाओं की है। बावजूद इसके अपनी जमीन से जीविका चलाने वाले किसानों में सिर्फ 40 फीसदी महिलाएं हैं। अफ्रीका और पूर्वी एशिया में ऐसी महिलाओं की संख्या और भी कम है। परिवार और सामुदायिक दोनों ही स्तरों पर महिलाएं एक बेहतर प्रबंधक की भूमिका निभाती हैं। ऐसे में आवश्यकता है उनकी इस भूमिका को मान्यता देने की। जब महिलाओं को अधिकार दिए जाते हैं तो इससे उनके पूरे समुदाय को लाभ मिलता है। इनमें खाद्य सुरक्षा, बच्चों के लिए स्वास्थ्य व शिक्षा में निवेश और भूमि का बेहतर प्रबंधन शामिल हैं।

जीवन के दर्शन को पूरी तरह से समझाने और भौतिक व आध्यात्मिक ज्ञान प्रदान करने के बाद भगवान श्रीकृष्ण ने अंत में अर्जुन से कहा- 'इस प्रकार मैंने सभी रहस्यों से भी अधिक रहस्यमयी और गोपनीय यह ज्ञान तुम्हें बतला दिया है। इस पर पूरी तरह से विचार करने के पश्चात जैसी तुम्हारी इच्छा हो, वैसा तुम करो।' अर्जुन के साथ संवाद के दौरान श्रीकृष्ण ने जीवन के विभिन्न पहलुओं पर प्रकाश डालते हुए हर एक वस्तु के फायदे और नुकसान समझाए। सब कुछ विस्तार में बताने के बाद श्रीकृष्ण ने अर्जुन से इस बारे में गंभीरता से सोचने और फिर जैसा उसे ठीक लगे वैसा करने को कहा।

भगवद् गीता स्वतंत्र इच्छा का सिद्धांत

महात्मा गांधी के पास एक दिन एक व्यक्ति आया। उसने गांधीजी से कहा- 'मैं आपसे गीता का रहस्य जानने आया हूं।' महात्मा गांधी उस समय आश्रम की भूमि फावड़े से खोद रहे थे। महात्मा गांधी ने उसे बैठने के लिए कहा। काफी समय तक बैठने के बाद वह व्यक्ति बोला, 'मैं इतनी दूर से आपकी ख्याति सुनकर गीता का मर्म समझने आया था, मगर आपको तो केवल समय का महत्व ही अधिक जान पड़ता है।' महात्मा गांधी हंसे और मधुरता से बोले, 'भाई, गीता का रहस्य ही तो मैं समझा रहा हूं।' 'कहां समझा रहे हैं, कब से यहां बैठा हूं, आपने एक शब्द भी नहीं कहा।' वह व्यक्ति बोला। महात्मा गांधी ने कहा, 'बोलने की जरूरत ही क्या है? गीता का उपदेश यह है कि बस, कर्म करो। मैं तब से आपके सामने कर्म ही तो कर रहा था। गीता का रहस्य भी यही है, लगातार कर्म करो, फल की चिंता न करो।'

भगवद् गीता का मार्ग बाध्यता का मार्ग नहीं है, बल्कि यह तो स्वतंत्र इच्छा का मार्ग है। यह आत्म-साक्षात्कार की वह राह है जिसमें संबधित व्यक्ति की राय को नकारा नहीं जाता, बल्कि उसके ईमानदार और सुविचारित मत को पूरा सम्मान दिया जाता है। परमात्मा ने मानव को अपने फैसले स्वयं लेने की स्वतंत्रता दी है। लेकिन स्वतंत्रता असीमित नहीं हो सकती। मनुष्य को उस स्वतंत्रता का उपयोग जीवन के परम उद्देश्य को ध्यान में रखते हुए पूरी सावधानी के साथ करना चाहिए।

जीवन के दर्शन को पूरी तरह से समझाने और भौतिक व आध्यात्मिक ज्ञान प्रदान करने के बाद भगवान श्रीकृष्ण ने अंत में अर्जुन से कहा- 'इस प्रकार मैंने सभी रहस्यों से भी अधिक रहस्यमयी और गोपनीय यह ज्ञान तुम्हें बतला दिया है। इस पर पूरी तरह से विचार करने के पश्चात जैसी तुम्हारी इच्छा हो, वैसा तुम करो।' अर्जुन के साथ संवाद के दौरान श्रीकृष्ण ने जीवन के विभिन्न पहलुओं पर प्रकाश डालते हुए हर एक वस्तु के फायदे और नुकसान समझाए। सब कुछ विस्तार में बताने के बाद श्रीकृष्ण ने अर्जुन से इस बारे में गंभीरता से सोचने और फिर जैसा उसे ठीक लगे वैसा करने को कहा। श्रीकृष्ण ने अर्जुन पर ही फैसला छोड़ दिया। परमात्मा ने मनुष्य को स्वतंत्र इच्छा प्रदान की है ताकि परिस्थितियों को देखते हुए वह उपयुक्त विकल्प चुन सके। परंतु मनुष्य को अपने फैसले किसी आवेग में आकर नहीं लेने चाहिए। निर्णय सुविचारित होना चाहिए। यही कारण है कि श्रीकृष्ण ने अर्जुन से अपनी शिक्षाओं का पालन बिना सोचे समझे करने को नहीं कहा।

भगवान केवल पथ दिखा सकते हैं, मनुष्य का मार्गदर्शन कर सकते हैं, जब कभी वह लड़खड़ाता है तो उसको सहारा दे सकते हैं। लेकिन ईश्वर न तो मनुष्य को कोई कार्य करने के लिए बाध्य करते हैं और न ही वह कभी अपनी ओर से कार्य करते हैं। इस प्रकार भगवद्गीता न केवल व्यक्ति के अपने निर्णय स्वयं लेने के अधिकार पर जोर देती है, बल्कि यह भी बताती है कि उस अधिकार का इस्तेमाल कैसे किया जाए। अपने फैसलों को आवेग और जुनून से नहीं बल्कि आध्यात्मिक ज्ञान से निर्देशित किया जाना चाहिए। यदि हम अपने स्वार्थों से ऊपर नहीं उठ पाते और हमारा आचरण बुद्धि द्वारा निर्देशित नहीं होता तो हम वासना, जो कि मनुष्य का सबसे बड़ा दुश्मन है, के शिकार बन सकते हैं।

आत्मा के रूप में मनुष्य एक ऐसा विषय है जो जीवन का अनुभव करता है, और मन एवं शरीर उसके अनुभव की वस्तुएं हैं। परमात्मा चाहता है कि आत्मा मन और शरीर पर नियंत्रण प्राप्त करे। वह चाहता है कि सभी को पूर्णता प्राप्त हो। साथ ही परमात्मा यह भी चाहता है कि मनुष्य उसे प्राप्त करने का प्रयास किसी भय या मजबूरी से नहीं बल्कि अपनी इच्छा से करे। मनुष्य को परमात्मा के साथ एक होना चाहिए और उस एकता को प्राप्त करने के लिए सदा प्रयास करते रहना चाहिए।

श्रीकृष्ण के द्वारा घोषित ज्ञान को सभी रहस्यों से भी अधिक रहस्यमय क्यों कहा गया है? गीता में आत्मा, जीवात्मा और परमात्मा जैसी आध्यात्मिक अवधारणाओं पर विस्तार से चर्चा की गई है। यह भी बताया गया है कि मोक्ष कैसे प्राप्त किया जा सकता है। इतना गहरा ज्ञान प्रत्यक्ष बोध के माध्यम से प्राप्त नहीं किया जा सकता। इसलिए इसे गोपनीय ज्ञान की संज्ञा दी गई है। श्रीकृष्ण वो शिक्षक हैं जिन्होंने अपने शिष्य अर्जुन को जीवन के सभी सत्य विस्तारपूर्वक समझाए। उन्होंने अर्जुन को कोई भी प्रश्न पूछने या किसी भी संदेह को साझा करने से कभी नहीं रोका। उन्होंने धैर्य से उनकी बातें सुनीं और हर एक सवाल का उत्तर दिया। एक-एक शंका को भी दूर किया। इस प्रकार बताया गया कि मनुष्य को सावधानी के साथ अपनी मुक्ति का रास्ता स्वयं चुनना चाहिए और दृढ़ विश्वास के साथ उस पथ पर चलना चाहिए। विचार और कर्म की ऐसी स्वतंत्रता के कारण ही कहा जाता है कि भगवद्गीता के उपदेश बंधनकारी नही हैं। यह तो मुक्ति प्रदान करने वाले हैं।

● **ओम**

मानवीयता का पाठ

कहां जा रहे हैं आप लोग! आप लोगों को पता नहीं है कि शहर की सीमाएं सील की गई हैं। न तो कोई शहर में आ सकता है और न ही कोई जा सकता है।

सर, मेरे भाई की हार्ट अटैक से मौत हो गई है। मुझे उनके अंतिम संस्कार में उज्जैन पहुंचना है। कार में बैठी संभ्रांत महिला ने रोते हुए पुलिस अधिकारी से अनुनय की।

देखिए मैडम, आपका दुख मैं समझ सकता हूं लेकिन अभी कोरोना का कहर मचा हुआ है। जाने वाले तो चले गए, अब आप क्यों अपना, अपने परिवार और समाजजनों का अहित करना चाह रहे हैं। हमें कोरोना की चैन तोड़ना है। बेहतर होगा कि आप सभी अपने घरों में रहें और वहीं से मृतात्मा की शांति के लिए प्रार्थना करें। बहुत ही संयमित और शांत स्वर में उसने समझाना चाहा।

आप लोगों में जरा सी भी मानवीयता नहीं है। शायद आपको मानवीयता का पाठ अपने घरों में पढ़ाया ही नहीं गया होगा। हम आपकी यह गैरकानूनी बात मानने के लिए बाध्य नहीं हैं। महिला लगभग चीखते हुए बिफर गई।

देखिए मैडम, आप मुझे सख्त कदम उठाने के लिए मजबूर न करें। और गाड़ी में बैठे ड्राइवर को डपटते हुए कहा- चलो गाड़ी वापस मोड़ो और इन लोगों को इनके घर पर छोड़ो और तुम अपने घर जाओ। नहीं तो गाड़ी जप्त कर लूंगा और आप लोगों के विरुद्ध सख्त कार्यवाही करने पर मजबूर होना पड़ेगा।

उधर गाड़ी वापस लौट रही थी और पुलिस अधिकारी बुदबुदा रहा था-मानवीयता का पाठ! हम खुद अपनी जान जोखिम में डालकर चौबीसों घंटे ड्यूटी दे रहे हैं लोगों को संक्रमण से बचाने के लिए और उस पर ये लोग मानवीयता के पाठ की बात करते हैं। हां, एक टीस जरूर है कि काश! मैं स्वयं अपनी पत्नी और बच्ची को मायके की शादी में जाने से रोक लेता तो कोरोना के कहर से उन्हें भी बचा सकता था और आज वे जिंदा होते।

- डॉ. प्रदीप उपाध्याय

गीत

सूख चुके अधरों से,
मधुर गीत क्या गाऊं?
काल नग्न नाच रहा,
शोक है, विलाप है।
हर तरफ से सिर्फ
शोक समाचार मिलते हैं।
सूरज के साथ रोज
मृत्युदूत खिलते हैं।
किसको मैं ढांढस दूं,
किसको मैं समझाऊं,
जगती भयभीत हुई
कैसा अभिशाप है?
सूख चुके अधरों...
गांव-गांव, नगर-नगर
हाय करुण क्रंदन है।
रौंद रहां सांसों को
मृत्यु का स्पंदन है।
देख-देख सोंच रहा,
कैसे मैं बतलाऊं
अंतस को जला रहा,
पीड़ा का ताप है।
सूख चुके अधरों...
त्राहि-त्राहि कर रहें हैं,
मानव बेचारे हैं।
लघुतम रोगाणु,
बड़े अविष्कार हारे हैं।
नाथ! अब सहाय करो,
किस दर को मैं जाऊं?
क्षमा करो दीनबंधु,
जो जग का पाप है।
सूख चुके अधरों...

- डॉ. दिवाकर दत्त त्रिपाठी

मंगलसूत्र

पत्नी ने अपने मंगलसूत्र को पति को देते हुए कहा, इसे किसी के पास गिरवी रखकर बीस-तीस हजार रुपए ले आओ।

क्यों, क्या जरूरत पड़ गई तुम्हें इस लॉकडॉउन में? इसे अपने भविष्य के लिए सुरक्षित रखो, पति ने कहा।

मेरा असली भविष्य मेरा मुन्ना है। उसका भविष्य सुरक्षित तो मेरा, मेरे पूरे परिवार का भविष्य सुरक्षित, पत्नी ने जवाब दिया।

मैं तुम्हारी बात समझा नहीं, क्या करना है?

मुन्ने की पढ़ाई के लिए बत्तीस इंच का

एक टीवी खरीद लाओ। मुन्ना दसवीं में पढ़ता है। टीवी के बिना उसकी ऑनलाइन पढ़ाई नहीं हो पा रही है।

मैं तो जानता था कि औरतों को अपने गहने से काफी मोह होता है, खासकर अपने मंगलसूत्र से पति ने कहा।

मंगलसूत्र पति और परिवार के कल्याण की निशानी है। बुरे वक्त के लिए मंगलसूत्र सुरक्षित रखा जाता है। आज बेटे के भविष्य के लिए इतना त्याग तो कर ही सकती हूं, पत्नी ने कहा।

पत्नी की समझदारी और त्याग की भावना के आगे पति को झुकना पड़ा।

- निर्मल कुमार

आईपीएल छोड़ घर जा रहे हैं विदेशी खिलाड़ी

भारत में कोरोना महामारी की दूसरी लहर ने इंडियन प्रीमियर लीग 2021 से विदेशी खिलाड़ियों का मोह भंग शुरू कर दिया है। ऑस्ट्रेलिया के कुछ खिलाड़ियों ने लीग से अपना नाम वापस ले लिया है। कोरोना की बेकाबू रफ्तार ने विदेशी खिलाड़ियों की चिंता बढ़ा दी है और संभावना जताई जा रही है कि कई अन्य ऑस्ट्रेलियाई खिलाड़ी भी लीग को अलविदा कह सकते हैं। भारत के अनुभवी स्पिन गेंदबाज रविचंद्रन अश्विन ने भी परिवार के एक सदस्य के कोरोना संक्रमित होने पर लीग से ब्रेक ले लिया है। सुरक्षित और कड़ा बायो बबल होने के बावजूद विदेशी खिलाड़ियों का इंडियन प्रीमियर लीग (आईपीएल) से दूरी बनाना चौंकाता है। लेकिन, इस आशंका से इनकार नहीं किया जा सकता है कि आईपीएल पर भी कोरोना संकट के बादल गहरा सकते हैं। सवाल उठना लाजिमी है कि आखिर क्यों बीसीसीआई यानी भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड ने कोरोना की दूसरी लहर के बीच भी आईपीएल को जारी रखा हुआ है?

बीसीसीआई के एक अधिकारी ने कहा है कि आईपीएल जारी रहेगा। कोई इसे छोड़कर जाना चाहता है, तो कोई हर्ज नहीं है। हजारों करोड़ की स्पॉनसरशिप से चल रही ये भारतीय क्रिकेट लीग इस साल अपनी शुरुआत से पहले ही कोरोना की चपेट में आ गई थी। आईपीएल शुरू होने से पहले चार खिलाड़ी और एक टीम कंसल्टेंट कोविड-19 संक्रमण का शिकार हो गए थे। वहीं, मुंबई के वानखेड़े स्टेडियम के ग्राउंड स्टाफ के दस लोग भी कोरोना संक्रमित मिले थे। हालांकि, अब ये सभी लोग संक्रमण से उबरकर टीम में वापसी कर चुके हैं। महाराष्ट्र में जहां सर्वाधिक मामले सामने आ रहे हैं, वहां के वानखेड़े स्टेडियम में लगातार मैच खेले जा रहे हैं। कमोबेश जिन राज्यों में आईपीएल के मैचों का आयोजन हो रहा है, वहां कोरोना के मामले लगातार बढ़ ही रहे हैं।

आईपीएल का आयोजन एक कड़े बायो बबल में किया जा रहा है, लेकिन किसी भी खिलाड़ी की एक अनचाही गलती इसे तार-तार कर देगी। आईपीएल का आयोजन एक कड़े बायो बबल में किया जा रहा है, लेकिन किसी भी खिलाड़ी की एक अनचाही गलती इसे तार-तार कर देगी। अगर आईपीएल को रद्द किया जाता, तो बीसीसीआई को काफी आर्थिक नुकसान उठाना पड़ता। लेकिन, केवल आर्थिक नुकसान न उठाना पड़े, इस वजह से सैकड़ों लोगों की जिंदगी को खतरे में क्यों डाला जा रहा है, यह बात समझ से परे है। दरअसल, आईपीएल की वजह से सरकार को करोड़ों रुपए के टैक्स का कलेक्शन मिलता है। क्रिकेट में सट्टेबाजी को लीगल बनाने वाली दर्जनों एप और बेवसाइट जीत की रकम पर कमीशन के साथ ही टैक्स काटती हैं, जो सीधा सरकार के खाते में जाता है। कहना गलत नहीं होगा कि बीसीसीआई और केंद्र सरकार ने महज पैसों के लिए ही आईपीएल को नहीं टालने का फैसला लिया था। ठीक 5 राज्यों में हुए विधानसभा चुनावों की तरह, जहां संक्रमण का खतरा बने रहने के बाद भी चुनावी रैलियां चलती रहीं।

भारत में कोरोना के बढ़ते मामलों की वजह से कई देशों ने यहां से भारतीय विमान सेवाओं पर रोक लगा दी है। ऑस्ट्रेलिया ने भी हवाई सेवा में 30 फीसदी तक कटौती कर दी है। भारत से हवाई यात्राओं पर प्रतिबंध और स्वदेश वापसी पर क्वारेंटाइन का डर खिलाड़ियों को आईपीएल से हटने पर मजबूर कर रहा है। मार्च में आईपीएल से पहले भारत में हुई रोड सेफ्टी वर्ल्ड सीरीज भी कोरोना संक्रमण के साये में आ गई थी। फाइनल मैच के बाद सचिन तेंडुलकर, इरफान पठान समेत चार खिलाड़ी कोरोना संक्रमित पाए गए थे। इस स्थिति में यह कहना गलत नहीं होगा कि आईपीएल के खत्म होने तक यह एक बड़ा कोरोना बम साबित हो सकता है। किसी भी एक खिलाड़ी की छोटी सी गलती इस आयोजन को किसी भी समय कोरोना संक्रमण से बर्बाद कर सकती है। इसी बीच भारत में कोरोना की बेकाबू रफ्तार को देखते हुए मुंबई इंडियंस के बल्लेबाज क्रिस लिन ने इंडियन प्रीमियर लीग के अंत में खिलाड़ियों को घर लाने के लिए ऑस्ट्रेलिया के क्रिकेट बोर्ड से एक चार्टर फ्लाइट की व्यवस्था करने को कहा है।

बता दें कि इससे पहले तीन ऑस्ट्रेलियाई क्रिकेटरों ने पहले ही अपने आईपीएल से अपना नाम वापस ले लिया है, लेकिन स्टीव स्मिथ, डेविड वार्नर और पैट कमिंस सहित देश के कई शीर्ष खिलाड़ी अभी भारत में बने हुए हैं। वहीं क्रिकेट ऑस्ट्रेलिया और ऑस्ट्रेलियाई क्रिकेटर संघ ने संयुक्त बयान में कहा कि वे आइपीएल में शामिल अपने क्रिकेटरों, कोचों और कमेंटेटरों के संपर्क में हैं और हालात पर नजर रखे हुए हैं। उन्होंने कहा कि हम भारत में मौजूद लोगों से फीडबैक लेते रहेंगे और ऑस्ट्रेलिया सरकार को सलाह देंगे।

● आशीष नेमा

बबल फटीग दे सकता है कोरोना को निमंत्रण

आईपीएल का आयोजन एक कड़े बायो बबल में किया जा रहा है, लेकिन किसी भी खिलाड़ी की एक अनचाही गलती इसे तार-तार कर देगी। ऐसे समय में जब खबरें हैं कि कोरोना हवा में भी फैल रहा है। आईपीएल का आयोजन खतरे की घंटी है। आईपीएल में खेल रही आठ टीमों के करीब 200 खिलाड़ी बायो बबल में रह रहे हैं। इन खिलाड़ियों के साथ ही सपोर्टिंग स्टाफ, टीम प्रबंधन स्टाफ, ग्राउंड स्टाफ, कैटरिंग स्टाफ समेत सैकड़ों लोग इस बबल में रह रहे हैं। भारत में जिस तरह से स्थितियां भयावह होती जा रही हैं, बहुत जल्द ही कई अन्य देशों के खिलाड़ी भी यह लीग छोड़कर अपने देश वापस जा सकते हैं। आईपीएल छोड़ने वाले विदेशी खिलाड़ियों ने बबल फटीग को इसका कारण बताया है। ये सभी खिलाड़ी लंबे समय से बायो बबल में हैं और लगातार बायो बबल में रहने की वजह से थक चुके हैं। खिलाड़ियों पर बायो बबल में बने रहने का भीषण दबाव भी उन्हें लीग छोड़ने पर मजबूर कर रहा है।

काजोल की वजह से अजय देवगन से नफरत करते थे किच्चा सुदीप

साउथ इंडियन एक्टर किच्चा सुदीप की मानें तो बॉलीवुड एक्ट्रेस काजोल उनकी पहली सेलेब्रिटी क्रश हैं। एक एंटरटेनमेंट वेबसाइट से बातचीत में जब उनसे इसके पीछे की वजह पूछी गई तो उन्होंने कहा, क्योंकि वे काजोल हैं और उनकी वजह से मैंने अजय देवगन सर से बहुत नफरत की है। एक वक्त था, जब जिस मैगजीन में काजोल की फोटो आती थी, वह मेरे पास होती थी। मेरे पास 30-40 बुक्स हुआ करती थीं। जब सुदीप से पूछा गया कि क्या कभी उन्हें काजोल से यह सब कहने का मौका मिला तो उन्होंने कहा, नहीं, तब तक उनकी शादी हो चुकी थी।

अंदाज अपना-अपना की शूटिंग के दौरान सलमान को घमंडी समझते थे आमिर

आमिर ने आगे कहा, मेरा तलाक हो चुका था। सलमान मुझसे मिलने आए और फिर हमने साथ में ड्रिंक किया और ढेर सारी बातें कीं। उस दिन मेरी धारणा सलमान के प्रति बिलकुल बदल गई और तब हमारी असली मायनों में दोस्ती शुरु हुई जो समय के साथ और ज्यादा मजबूत ही हुई है।

बॉलीवुड की कल्ट क्लासिक फिल्मों में शुमार अंदाज अपना-अपना भले ही 27 साल पहले रिलीज हुई थी लेकिन इसके किस्से आज भी मशहूर हैं। इस फिल्म में आमिर खान, सलमान खान, रवीना टंडन और करिश्मा कपूर ने मुख्य भूमिका निभाई थी। फिल्म पहले तो बॉक्स ऑफिस पर फ्लॉप साबित हुई थी लेकिन फिर धीरे-धीरे ये हिट हो गई जब इसका प्रसारण टीवी पर हुआ और माउथ पब्लिसिटी के जरिए फैन्स ने इसे काफी पसंद करना शुरू कर दिया।

इस फिल्म को लेकर आमिर खान ने 2013 में करण जौहर के चैट शो कॉफी विद करण में कुछ दिलचस्प खुलासे किए थे। उन्होंने कहा था, अंदाज अपना-अपना की शूटिंग के दौरान सलमान खान के साथ काम करने का मेरा अनुभव बहुत ही खराब था। मैं उन्हें तब पसंद नहीं करता था। मैं उन्हें रूड और घमंडी मानता था। इस फिल्म में उनके साथ काम करने के बुरे अनुभव के बाद मैं भविष्य में उनके साथ कभी दोबारा काम नहीं करना चाहता था।

ये हैं दोनों की अगली फिल्में

सलमान की अपकमिंग फिल्म की बात करें तो ये राधे: योर मोस्ट वांटेड भाई है जो कि इसी साल ईद के मौके पर रिलीज हो रही है। वहीं, आमिर इन दिनों फिल्म लाल सिंह चड्ढा की शूटिंग में व्यस्त हैं जो कि हॉलीवुड फिल्म फारेस्ट गंप की ऑफिशियल रीमेक है।

एक घटना ने बदली आमिर की सोच

आमिर ने आगे कहा, अंदाज अपना-अपना फिल्म में काम करने के बाद 2002 में हमारा एक बार फिर आमना-सामना हुआ। तब मैं अपनी पहली पत्नी रीना दत्ता के साथ सेपरेशन के दौर से गुजर रहा था और बेहद परेशान रहता था। मैं तब काफी शराब पीने लग गया था और एक शाम को सलमान मेरे पास आए। सलमान तब मुझसे मिलने आए जब मैं जिंदगी के सबसे बुरे दौर से गुजर रहा था। मेरा तलाक हो चुका था। सलमान मुझसे मिलने आए और फिर हमने साथ में ड्रिंक किया और ढेर सारी बातें कीं। उस दिन मेरी धारणा सलमान के प्रति बिलकुल बदल गई और तब हमारी असली मायनों में दोस्ती शुरू हुई जो समय के साथ और ज्यादा मजबूत ही हुई है।

विंदू ने फराह नाज से की थी पहली शादी, 6 साल में हो गया था तलाक

फिल्म और टीवी अभिनेता विंदू दारा सिंह का जन्म 6 मई 1964 को मुंबई, महाराष्ट्र में हुआ था। वे टीवी जगत में हनुमान के नाम से मशहूर एक्टर और पहलवान स्व. दारा सिंह के बेटे हैं। टीवी धारावाहिकों और फिल्मों में काम कर चुके विंदू अपने पिता यानी दारा सिंह की तरह लोकप्रियता हासिल करने में असफल रहे हैं। विंदू ने बतौर अभिनेता फिल्म करन (1994) से बॉलीवुड में एंट्री ली, लेकिन बॉक्स ऑफिस पर कोई कमाल नहीं दिखा सके। इसके बाद उन्होंने पिता के निर्देशन में बनी फिल्म रब दियां राखां (1996) में काम किया। विंदू अब तक गर्व, मैंने प्यार क्यों किया, पार्टनर और हाउसफुल जैसी कई बॉलीवुड फिल्में कर चुके हैं,

जिनमें से अधिकतर में उन्होंने बतौर सपोर्टिंग स्टार काम किया है।

विंदू ने एक्ट्रेस और तब्बू की बहन फराह नाज से 1996 शादी की थी, लेकिन कुछ समय बाद ही 2002 में दोनों का तलाक हो गया। दोनों का एक बेटा भी है, जिसका नाम फतेह रंधावा है। फराह से रिश्ता खत्म होने के बाद उन्होंने मॉडल डीना उमारोवा से शादी की और अब खुशहाल जीवन जी रहे हैं। पिता के नक्शेकदम पर चलते हुए विंदू भी टीवी पर हनुमान का किरदार जी चुके हैं। उन्होंने स्टार प्लस के शो जय वीर हनुमान में यह रोल अदा किया था। टीवी पर वे मिसेज कौशिक की पांच बहुएं, श्श्श्श कोई है, कर्मा और ब्लैक जैसे शो में किरदार निभा चुके हैं। इसके अलावा मां एक्सचेंज, वेलकम : बाजी मेहमान नवाजी की और बिग बॉस जैसे रियलटी शो में भी वे नजर आ चुके हैं। साल 2009 में उन्होंने बिग बॉस का तीसरा सीजन जीता था।

अथ बकरी-बैल कथा

दोनों एक गांव में पले-बढ़े थे। साथ स्कूल जाते थे और साथ खेलते थे। एक का नाम राजा था तो दूसरा राजू था। राजा गड़ेरिया था। राजू खेत मजदूर। राजू स्कूल से आने के बाद जमींदार के खेत में जुट जाता था।

राजा पेड़ की छांव में बैठकर घास चरती बकरियों की निगहबानी करता था और राजू से बात करता रहता था। राजू के खेत में उतरकर राजू की मदद करने का ख्याल उसको कभी नहीं आया था। वह आराम से छांव में बैठकर इधर-उधर की लंतरानी हांका करता था। फावड़ा चलाता हुआ राजू हांफते हुए राजा की बात का हूं-हां में जवाब देता था। प्यास लगने पर लोटा लेकर नहर से जल ले आता था। राजा गला तर करने के लिए बकरी के थन से मुंह लगा देता था। बकरी का दूध सेहत के लिए बहुत अच्छा होता है, वह थन से मुंह अलग करके राजू से हर बार कहता था, पर राजू को लोटा भर दूध निकाल लेने की पेशकश कभी नहीं करता था।

जब भी वह राजू को बकरी की तरफ आस भरी नजर लगाए देखता था, तो मुस्कराकर कहता था, 'काश तू भी गड़ेरिया होता। दूध पीता। तेरी भी बकरियां किसी दूसरे राजू के खेत में मुंह मार आतीं और बढ़िया दूध तुझे देतीं।' राजा की बात सुनकर राजू चुपचाप खेत से खर-पतवार निकालने के काम में लग जाता था। खेत उसका नहीं था, फसल भी किसी और की थी, पर वह अपनी जिम्मेदारी निभाने में कोताही नहीं बरतता था। राजा राजू की इस आदत पर अक्सर हंसता था।

राजा ने अपनी बातों से बकरियों को इतना प्रभावित कर लिया कि उन्होंने दूर-दूर बसे अपने झुंडों को भी राजा से जोड़ दिया।

बकरियों की संख्या रोज बढ़ती जा रही थी। उनकी भीड़ इतनी हो गई थी कि कुछ राजा की गोदी में घुस जाती थीं, कुछ कंधों पर चढ़ जाती थीं और कुछ तो सिर पर चढ़कर खुर पटकने लगती थीं। वह परेशान हो जाता था और बकरियों का ध्यान बंटाने के लिए और लंबी-लंबी हांकने लगता था। सिर से उतरकर कुछ देर वे हांक पर ध्यान देती थीं, पर फिर चढ़ जाती थीं। राजा का हांकते-हांकते दम फूल जाता था, पर वह मजबूर था। जैसे भी गला गीला करने के लिए थन में मुंह लगाता था, दो-चार बकरियां उसके कंधों को खुरों से खरोंच देती थीं। कई बकरियां अब राजा से सवाल भी करने लगी थीं कि नथुने फैलाने के बावजूद हम अभी तक बैल क्यों नहीं बनी हैं? राजा इस सवाल के जवाब में और हांकने में जुट जाता था। वह नई-नई कहानियां बनाता था, जिससे बकरियां बैल बनना कुछ देर के लिए भूल जाएं और वह उनका दूध पीकर आराम कर ले।

राजू दूर से राजा की हालत देखता था। दोस्त के लिए उसके मन में प्रेम था और सहानुभूति भी। एक दिन उसने राजा से कहा कि खूब दूध पी लिया है तुमने, अब क्यों यह जिल्लत उठा रहे हो। बकरियों से हट लो। उन्हें बता दो कि बैल वाली बात जुमला थी। बकरी बैल नहीं बन सकती है। और फिर तुम अपने गड़ेरिया वाले काम पर वापस आ जाओ। उसमें मेहनत करोगे तो तुम्हें झूठ-फरेब की जिल्लत नहीं उठानी पड़ेगी। बकरियों को गुमराह करने से क्या फायदा? उनका जीवन तुम नरक कर रहे हो। गड़ेरिए का धर्म निभाओ। यह एक सुर में हांकना छोड़ो।'

राजा ने अट्टहास किया, 'मैं राजा गड़ेरिया था, अब राजा राजा हूं।' उसने गर्व से छाती पीटी, 'मेरा स्वभाव गड़ेरिए वाला नहीं, राजा वाला है। राजा का धर्म अपना राज कायम रखना है। मैं कुछ खुरों की चोट से विचलित नहीं हो सकता हूं। वैसे राजनीति की एक बात मैं तुम्हें बता दूं- बकरियों को बैल बनाने के आश्वासन पर राज चलता है। मुझे राज करना है। मैं इन्हें बैल बनाता और पेड़ की छांव में बैठा रहूंगा। मेरी बकरियां अगर तुम्हारा पूरा खेत भी चर जाएं, तो मुझ पर कोई फर्क नहीं पड़ता है।'

'अगर यह अनाज चर गईं तो तुम खाओगे क्या?'

'हवा', राजा ने तपाक से कहा, 'राजा का राज हवा पर चलता है। जब तक हवा ठीक है, राजा राजा बना रहेगा।'

● **प्रमोद दीक्षित 'मलय'**

विश्वसनीय खबरों के लिए पढ़ते रहिए

In Pursuit of Truth

पाक्षिक

अक्स

E-Magazine पढ़ने और PDF डाउनलोड करने के लिए हमारी वेबसाइट पर जाएं

www.akshnews.com

वार्षिक सदस्यता के लिए संपर्क करें, 150, जोन-1, एम.पी.नगर भोपाल

फोन:0755-4017788,2575777

D-17008

For Any Medical & Pathology Equipments Contact Us

Science House Medicals Pvt.Ltd.

17/1, Sector-1, Shanti Niketan, Near Chetak Bridge, Bhopal (M.P.) INDIA-462023

GST. No. : 23AAPCS9224G1Z5 Email : shbpl@rediffmail.com

PH. : +91-0755-4241102, 4257687, Fax : +91-0755-4257687